

करेंट अफेयर्स

माध्य प्रदेश

(संग्रह)



फरवरी

2026

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

मध्य प्रदेश	5
☉ पूरे देश में 'दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन' की शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई.....	5
☉ सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना.....	5
☉ मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26.....	6
☉ मध्य प्रदेश बजट 2026-27.....	7
☉ जबलपुर में पहला UN स्मॉल आर्म्स कंट्रोल प्रशिक्षण कार्यक्रम.....	10
☉ मध्य प्रदेश सरकार ने किया सरसों के किसानों के लिये भावांतर भुगतान योजना का विस्तार.....	11
☉ सांसद ने पहले राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव-2026 का उद्घाटन किया.....	11
राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स	13
☉ भारत की रामसर सूची में दो नई आर्द्रभूमियाँ शामिल की.....	13
☉ MoSPI ने PAIMANA पोर्टल लॉन्च किया.....	13
☉ मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज UNESCO विश्व धरोहर सूची के लिये नॉमिनेट हुए.....	14
☉ पश्चिम बंगाल में पुलिस में बड़ा फेरबदल: पीयूष पांडे को कार्यवाहक DGP नियुक्त किया.....	15
☉ अमेरिकी म्यूजियम लौटाएगा तमिलनाडु से चोरी तीन दुर्लभ कांस्य मूर्तियाँ.....	15
☉ भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने टाइम्स B-स्कूल रैंकिंग 2026 में टॉप किया.....	16
☉ कैप्टन हंसजा शर्मा रुद्रा आर्म्ड हेलीकॉप्टर की पहली महिला पायलट बनीं.....	16
☉ SBI ने उभरते क्षेत्रों के वित्तपोषण के लिये CHAKRA सेंटर लॉन्च किया.....	17
☉ तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा शिपबिल्डिंग क्लस्टर.....	18
☉ नागालैंड में नई पुष्पीय पौध प्रजाति होया नागाएंसिस की खोज.....	18
☉ गुजरात में मुख्यमंत्री प्रामोत्थान योजना शुरू की.....	19
☉ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026.....	19
☉ अभ्यास अग्नि परीक्षा: भारतीय सेना-ITBP की संयुक्त पहल.....	20
☉ सामाजिक विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र आयोग के 64वें सत्र में भारत.....	20
☉ चित्तूर जिले ने ई-साइकिल वितरण के लिये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया.....	21
☉ दलाई लामा ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित.....	21
☉ वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को क्रैफ़ोर्ड पुरस्कार 2026 मिला.....	22
☉ पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0: त्रिपुरा की ग्राम पंचायत प्रथम.....	23

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



कलपेट्टा भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला न्यायालय बना.....	23
तमिलनाडु ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की.....	24
विश्व कैंसर दिवस 2026	24
ओलंपिक शीतकालीन खेल मिलानो कॉर्टिना 2026.....	25
आंध्र प्रदेश में भारत का पहला स्वदेशी हरित यूरिया संयंत्र.....	26
प्लास्टईंडिया 2026 नई दिल्ली में शुरू हुआ.....	26
केरल के सीएम ने इनवेसिव स्पीशीज डिटेक्शन ऐप लॉन्च किया.....	27
भारत ने छठी बार ICC U-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता.....	27
भारतीय टीचर रूबल नागी ने प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता.....	28
यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनीरल का दर्जा.....	29
रॉयल चैलेंजर्स बंगलूरु ने दूसरा खिताब जीता.....	29
अंतरिक्ष-आधारित AI डेटा केंद्रों के लिये चीन की योजना.....	30
वर्ष 2035 तक आंध्र प्रदेश को क्लीन एनर्जी हब बनाएगा नीति आयोग.....	31
दिल्ली पुलिस ने 'ऑपरेशन शास्त्र' शुरू किया.....	31
गोवा बना बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा भारतीय राज्य.....	32
VOC पोर्ट एंटी-ड्रोन सुरक्षा तैनात करने वाला भारत का पहला पोर्ट बना.....	33
कोटक बना पूरी तरह से डिजिटल FPI रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक.....	33
वॉलमार्ट \$1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुँचने वाला पहला रिटेलर बना.....	34
केरल में भारत का पहला 'एल्डरली बजट'	34
एयरबस-GSV सेंटर ऑफ एक्सीलेंस.....	35
जर्मनी में BIOFACH 2026 में भारत को 'कंट्री ऑफ द ईयर' चुना गया.....	36
विशाखापत्तनम में ऐतिहासिक समुद्री संगम.....	37
IIT मद्रास ने डीप-टेक स्टार्टअप्स के लिये ₹600 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड बनाया.....	37
गुजरात ने हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिये स्टारलिनक के साथ LoI एक्सचेंज किया.....	38
भारत लगाएगा लद्दाख में दो नए टेलीस्कोप.....	39
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 'पढ़ाई विद AI' ऐप लॉन्च किया.....	39
नेशनल क्वांटम मिशन के तहत अमरावती क्वांटम वैली लॉन्च की गई.....	40
दिल्ली ने 'लखपति बिटिया योजना' शुरू की.....	41
विश्व रेडियो दिवस 2026	41
हिमाचल प्रदेश में देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन.....	42
लिम्फैटिक फाइलेरिया के उन्मूलन हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान.....	43
निवेदिता दुबे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की पहली महिला सदस्य बनीं.....	43
भारत पहली BRICS शेरपा बैठक 2026 की मेजबानी करेगा.....	44
नई दिल्ली में सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का उद्घाटन.....	44
केरल में स्त्री सुरक्षा योजना.....	45

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



PNB सोल्वरथॉन 2026	46
भारत-थाईलैंड संयुक्त इन-सिटू एयर एक्सप्रेससाइज.....	46
भारत में निर्मित ओरल पोलियो वैक्सीन (nOPV2) को WHO की पूर्व-अर्हता प्राप्त	47
भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025.....	48
प्रधानमंत्री का सेवा तीर्थ से पहला निर्णय.....	48
भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में वाटरजेट प्रोडक्शन एवं टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया	49
गुजरात ने भारत की पहली CBDC-आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की.....	50
पीएम मोदी ने बारबाडोस की पीएम मिया मोटली को ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी	50
रिलायंस को वेनेजुएला से कच्चा तेल आयात करने का अमेरिकी लाइसेंस मिला.....	51
केरल बना शहरी नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य.....	51
सरकार ने शिक्षा में AI को जोड़ने के लिये बोधन AI लॉन्च किया.....	52
अंडमान में दो दशक बाद मिट्टी का ज्वालामुखी उद्गार.....	52
तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिये तैयार.....	53
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026.....	54
BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर 2025.....	54
मैनस कार्लसन ने 2026 FIDE फ्रीस्टाइल वर्ल्ड चैस टाइटल जीता	55
रूस ने व्हाट्सएप को ब्लॉक किया, सरकारी ऐप को बढ़ावा दिया.....	55
पहला स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज 'कृष्णा' चेन्नई में लॉन्च किया गया	56
यूरोपियन यूनियन ने खोला भारत में अपना पहला 'लीगल गेटवे' ऑफिस.....	57
केरल ने ज्वारीय बाढ़ को 'राज्य-विशिष्ट आपदा' घोषित किया.....	57
उत्तर पूर्व में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु NEST को स्वीकृति दी गई	58
थान्या नाथन केरल की पहली दृष्टिहीन महिला न्यायाधीश बनेंगी	59
राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मधुमक्खी गलियारे विकसित करेगा NHAI.....	59
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026	60
भारतीय मणिपुरी फिल्म 'बूंग' ने BAFTA पुरस्कार 2026 जीता.....	61
केंद्रीय कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने की स्वीकृति दी.....	61
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2026	62
ज़िम्बाब्वे ने लंबे समय तक असर करने वाला HIV-निरोधक इंजेक्शन लेनाकापैविर लॉन्च किया.....	63
UN ने चार भारतीय राज्यों में सड़क सुरक्षा वित्तपोषण परियोजना लॉन्च की.....	64
रॉब जेटन नीदरलैंड के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने.....	64
पाँच नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे स्टेशनों को 'ईट राइट स्टेशन' सर्टिफिकेशन मिला.....	65

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मध्य प्रदेश

पूरे देश में 'दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन' की शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले के अमलाहा से 'दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन' के अंतर्गत देशव्यापी दलहन क्रांति की शुरुआत की।

मुख्य बिंदु:

- ◆ **शुरुआत:** 'दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन' का उद्घाटन अमलाहा स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र (FLRP), सीहोर ज़िला, मध्य प्रदेश में किया गया, जिसका उद्देश्य भारत को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है।
 - **मुख्य अतिथि:** कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की।
- ◆ **उद्देश्य:** यह मिशन दलहन आयात पर भारत की निर्भरता समाप्त कर देश को दलहन निर्यातक बनाने का प्रयास करता है, जिसके लिये उत्पादन, उत्पादकता, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा दिया जाएगा।
 - इसका फोकस बीज से लेकर बाज़ार तक पूरी मूल्य शृंखला विकसित करने पर है, जिसमें बीज सुधार, क्लस्टर विकास और किसानों को उचित मूल्य दिलाने के उपाय शामिल हैं।
- ◆ **क्लस्टर मॉडल और प्रोत्साहन:** मिशन के तहत पूरे देश में 1,000 दलहन मिलें स्थापित की जाएँगी ताकि प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाई जा सके।
 - सरकार इन मिलों को सब्सिडी (प्रति इकाई ₹25 लाख तक) प्रदान करेगी और क्लस्टर-आधारित उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी, जिससे विशेष रूप से मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ होगा।
- ◆ **बीज वितरण सुधार:** इस मिशन का लक्ष्य राज्य स्तर पर बीजों के विमोचन और वितरण प्रणाली को और अधिक मज़बूत बनाना है।
 - किसानों को उन्नत बीज किट तथा बेहतर उत्पादन पद्धतियाँ अपनाने के लिये वित्तीय सहायता (₹10,000 प्रति हेक्टेयर) दी जाएगी।
- ◆ **महत्त्व:** यह पहल आयात-प्रतिस्थापन, किसानों की आय वृद्धि और पोषण सुरक्षा को समर्थन देती है।

सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना

चर्चा में क्यों ?

जैसे-जैसे भारत विकेंद्रीकृत भंडारण नेटवर्क के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश का बालाघाट ज़िला सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना (WLGSP) के अंतर्गत पायलट ज़िले के रूप में चयनित किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- ◆ **पारसवाड़ा मॉडल:** पायलट परियोजना का केंद्रबिंदु बहुदेशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित (PACS), पारसवाड़ा है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ अवसंरचना: 500 मीट्रिक टन क्षमता का अत्याधुनिक गोदाम निर्मित किया गया है।
- ❖ उद्घाटन: परियोजना का पूर्ण कार्य पूर्ण होने के बाद 24 फरवरी, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया।
- ❖ संचालनात्मक व्यवहार्यता: PACS की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये इस गोदाम को मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन (MPWLC) द्वारा किराए पर लिया गया है, जिससे समिति को तत्काल और स्थिर आय प्राप्त हो रही है।
- ❖ अनाज भंडारण योजना: यह एक केंद्रीय क्षेत्र की पहल है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में विकेंद्रीकृत खाद्यान्न भंडारण अवसंरचना का निर्माण करना है।
 - ⦿ यह सरकार के 'सहकार से समृद्धि' (सहयोग के माध्यम से समृद्धि) के दृष्टिकोण का एक प्रमुख घटक है।
- ❖ कार्यान्वयन तंत्र: यह योजना भारत सरकार की मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से लागू की जा रही है, ताकि सार्वजनिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित हो सके।

मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26

चर्चा में क्यों ?

मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को 17 फरवरी, 2026 को राज्य विधानसभा में पेश किया गया। यह सर्वेक्षण सेवा क्षेत्र में उच्च वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था के मजबूत विस्तार पर प्रकाश डालता है।

मुख्य बिंदु:

- ❖ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP): राज्य का नाममात्र GSDP वर्ष 2025-26 के लिये लगभग ₹16.69 लाख करोड़ आँका गया है, जो सशक्त आर्थिक विस्तार को दर्शाता है।
 - ⦿ नाममात्र वृद्धि दर: नाममात्र वृद्धि दर 11.14% अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में आर्थिक गतिविधियों में तेजी को प्रतिबिंबित करती है।
 - ⦿ वास्तविक वृद्धि दर: वास्तविक रूप से (2011-12 के स्थिर मूल्यों पर), राज्य की अर्थव्यवस्था के 8.04% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो मुद्रास्फीति समायोजन के बाद भी मजबूत वृद्धि को दर्शाता है।
- ❖ राजकोषीय घाटा: वर्ष 2025-26 के लिये राजकोषीय घाटा GSDP का 4.6% रहने का अनुमान है।
- ❖ प्रति व्यक्ति आय: सर्वेक्षण में प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाई गई है, जो वर्तमान मूल्यों पर वर्ष 2025-26 में ₹1,69,050 तक पहुँच गई है। यह वर्ष 2011-12 में ₹38,497 थी अर्थात् एक दशक में चार गुने से अधिक की वृद्धि।
 - ⦿ स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय ₹76,971 अनुमानित है, जो जीवन स्तर में वास्तविक सुधार को दर्शाती है।
- ❖ राजकोषीय संतुलन: राज्य के वर्ष 2025-26 में ₹2,618 करोड़ के राजस्व अधिशेष प्राप्त करने का अनुमान है।
 - ⦿ कर राजस्व वृद्धि अधिक होने की उम्मीद है, वर्ष 2025-26 में यह लगभग 13.57% रहने का अनुमान है।
- ❖ ऋण स्थिरता: ऋण-GSDP अनुपात 31.3% अनुमानित है, जो हाल के अतीत की तुलना में बेहतर और सतत ऋण प्रबंधन को दर्शाता है।
- ❖ GSDP में क्षेत्रवार योगदान: सर्वेक्षण प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विविधीकरण तथा संतुलित वृद्धि को दर्शाते हुए क्षेत्रवार योगदान की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



क्षेत्र	GSDP में हिस्सेदारी (2025-26)
प्राथमिक क्षेत्र (Primary)	43.09%
द्वितीयक क्षेत्र (Secondary)	19.79%
तृतीयक/सेवा क्षेत्र (Tertiary)	37.12%

- ❖ **वृद्धि रुझान:** तृतीयक क्षेत्र में 15.8% की दर से सर्वाधिक तेज़ वृद्धि दर्ज की गई। प्राथमिक क्षेत्र 7.31% और द्वितीयक क्षेत्र 9.93% की दर से बढ़ा।
- ❖ **कृषि एवं ग्रामीण विकास:** प्राथमिक क्षेत्र का महत्त्व बना हुआ है, जिसमें फसल उत्पादन, पशुपालन तथा संबद्ध गतिविधियों में सुधार हुआ है।
 - ⦿ ग्रामीण सड़कों और आवास कार्यक्रमों जैसे अवसंरचना विस्तार से आजीविका की मजबूती तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन को बढ़ावा मिला है।
- ❖ **उद्योग और निवेश:** 1,028 इकाइयों को औद्योगिक भूमि का आवंटन तथा ₹1.17 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्तावित निवेश से औद्योगिक विश्वास में सुधार का संकेत मिलता है।
 - ⦿ इन निवेशों से लगभग 1.7 लाख रोजगार सृजन का अनुमान है, जो राज्य की रोजगार चुनौती से निपटने में सहायक होगा।
- ❖ **सेवाएँ, स्टार्टअप और पर्यटन:** सेवा क्षेत्र ने व्यापार, परिवहन, आतिथ्य और डिजिटल सेवाओं के सहारे तीव्र वृद्धि दर्ज की है।
 - ⦿ राज्य में 1,723 स्टार्टअप और 103 इनक्यूबेशन केंद्र हैं, जो बढ़ती उद्यमशील गतिविधियों को दर्शाते हैं।
 - ⦿ पर्यटन और उससे जुड़ी सेवा गतिविधियाँ GSDP तथा रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
- ❖ **शिक्षा: प्राथमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर शून्य तक पहुँच गई है,** जो सार्वभौमिक शिक्षा पहुँच में प्रगति को दर्शाती है।
 - ⦿ उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर घटकर 6.3% रह गई है।
 - ⦿ शिक्षा के लिये बजटीय आवंटन कुल व्यय का 10.37% है, जो मानव पूंजी विकास के लिये एक महत्वपूर्ण नीतिगत प्राथमिकता को दर्शाता है।
- ❖ **स्वास्थ्य: आयुष्मान स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार और मातृ मृत्यु दर जैसे प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार से सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के सुदृढ़ होने का संकेत मिलता है।**
- ❖ **रणनीतिक लक्ष्य:** राज्य का लक्ष्य वर्ष 2047 तक 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है और वर्ष 2029 तक बजट तथा GSDP को दोगुना करने का उद्देश्य रखा गया है।

मध्य प्रदेश बजट 2026-27

चर्चा में क्यों ?

मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भोपाल में राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें महिला सशक्तीकरण, किसान कल्याण, अवसंरचना, स्वास्थ्य और वित्तीय अनुशासन को सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया गया।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु:

- ❖ **रिकॉर्ड बजट परिव्यय:** वित्त वर्ष 2026-27 के लिये कुल बजट आकार **₹4.38 लाख करोड़** है, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है और विकासोन्मुख विस्तारात्मक व्यय को प्रतिबिंबित करता है।
 - ⦿ सरकार ने **कोई नया कर नहीं लगाया** है और मौजूदा कर दरों को यथावत रखा है, ताकि **आर्थिक स्थिरता बनी रहे** और नागरिकों व व्यवसायों पर कर भार कम हो।
- ❖ **बजट के प्रमुख आँकड़े (₹ करोड़ में):**
 - ⦿ कुल प्राप्तियाँ: 3,89,397
 - ⦿ कुल व्यय: 3,88,925
 - ⦿ राजस्व प्राप्तियाँ: 3,08,703
 - ⦿ राजस्व व्यय: 3,08,659
 - ⦿ पूंजीगत प्राप्तियाँ: 80,694
 - ⦿ पूंजीगत व्यय: 80,266
 - ⦿ राजस्व अधिशेष: 44
 - ⦿ राजकोषीय घाटा: **GSDP का 3.87%**
 - ⦿ अनुदान राशि (**Appropriation Amount**): 4,38,317
 - ⦿ **GSDP: 18,48,274**
 - ⦿ प्रति व्यक्ति आय: **₹1,52,615 (2024-25)**
- ❖ **क्षेत्रवार प्रावधान (₹ करोड़ में):**
 - ⦿ कृषि क्षेत्र: 38,850
 - ⦿ स्वास्थ्य एवं महिला कल्याण: 56,478
 - ⦿ शिक्षा: 45,358
 - ⦿ एससी/एसटी/ओबीसी: 24,024
 - ⦿ अवसंरचना: 49,084
 - ⦿ शहरी एवं ग्रामीण विकास: 61,665
 - ⦿ सांस्कृतिक संवर्द्धन: 2,069
 - ⦿ रोजगार: 6,104
- ❖ **प्रमुख योजनाओं के लिये प्रावधान (₹ करोड़ में):**
 - ⦿ मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना: 23,883
 - ⦿ विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) की गारंटी: 10,428
 - ⦿ अटल गृह ज्योति योजना: 6,033
 - ⦿ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NUHM/NRHM): 4,600
 - ⦿ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: 2,000
 - ⦿ लाडली लक्ष्मी योजना: 1,801

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ेंUPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026UPSC
क्लासरूम
कोर्सेसIAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्सदृष्टि लर्निंग
ऐप

- ◆ **महिला-केंद्रित आवंटन:** महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिये लगभग ₹1.27 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें लाइली बहना योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रमों को निरंतर समर्थन शामिल है, जिससे महिलाओं के वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा।
 - बजट में राज्य भर में महिला श्रमिकों की सुरक्षा और रोजगार तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये 5,700 कार्यरत महिलाओं के छात्रावासों के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है।
- ◆ **'किसान कल्याण वर्ष' की घोषणा:** वर्ष 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' के रूप में घोषित किया गया है, जिसके तहत कृषि, सिंचाई, फसल खरीद और सहायक क्षेत्रों के लिये आवंटन बढ़ाया गया है।
- ◆ **कृषि एवं सिंचाई को बढ़ावा:** सिंचाई के विस्तार, किसानों के लिये सोलर पंपों की व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) खरीद तंत्र को मजबूत करने के लिये महत्वपूर्ण निवेश का प्रस्ताव किया गया है।
- ◆ **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पर विशेष ध्यान:** ग्रामीण सड़कों, जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति तथा ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिये आवंटन बढ़ाया गया है, ताकि स्थानीय स्तर पर विकास को गति मिल सके।
- ◆ **ग्रामीण रोजगार को समर्थन:** ग्रामीण रोजगार गारंटी को सुदृढ़ करने के लिये वीबी ग्राम आरजी योजना के तहत ₹10,428 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिये प्रधानमंत्री जनमन योजना हेतु ₹900 करोड़ का आवंटन किया गया है।
- ◆ **शहरी अवसंरचना का विस्तार:** बजट में मेट्रो रेल विस्तार, शहरी आवास, ई-बसों और स्मार्ट सिटी पहलों के लिये धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिससे शहरी केंद्रों का आधुनिकीकरण किया जा सके।
- ◆ **स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करना:** स्वास्थ्य सेवाओं के लिये लगभग ₹23,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसमें नए अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार शामिल है।
- ◆ **शिक्षा एवं कौशल विकास:** विद्यालयी शिक्षा पर व्यय में वृद्धि, शिक्षकों की भर्ती, कॉलेजों के उन्नयन तथा युवाओं के लिये रोजगार सृजन हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया है।
 - उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, स्वरोजगार योजनाओं और औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार सृजन के लिये भी विशेष प्रावधान किये गए हैं।
- ◆ **औद्योगिक एवं रोजगार समर्थन:** बजट में MSME, स्टार्ट-अप एवं निवेश प्रोत्साहन के लिये प्रोत्साहन तथा अवसंरचना उपलब्ध कराकर औद्योगिकीकरण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिले।
- ◆ **समावेशी विकास का ढाँचा:** यह बजट GYANII (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, अवसंरचना, उद्योग) नामक छह-सूत्रीय विकास ढाँचे के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, युवा सशक्तीकरण, कृषि समर्थन, महिला सशक्तीकरण, अवसंरचना विकास और औद्योगिक वृद्धि को एक साथ आगे बढ़ाना है।
- ◆ **अवसंरचना और आर्थिक विकास:** ग्रामीण सड़कों, संपर्क व्यवस्था, केन-बेतवा लिंक जैसी सिंचाई परियोजनाओं तथा सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार सहित अवसंरचना विकास के लिये बड़ी धनराशि का प्रावधान किया गया है।
 - इसके अलावा, राज्य के इतिहास में पहली बार ₹1 लाख करोड़ से अधिक के पूंजीगत निवेश का प्रावधान भी किया गया है।
- ◆ **ऊर्जा और नवीकरणीय क्षेत्र पर जोर:** नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और ग्रामीण विद्युतीकरण में निवेश का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना तथा सतत विकास को प्रोत्साहित करना है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **वित्तीय अनुशासन और घाटा प्रबंधन:** सरकार ने FRBM सीमाओं के भीतर नियंत्रित राजकोषीय घाटे का अनुमान प्रस्तुत किया है तथा राजस्व अधिशेष का संकेत दिया है, जो वित्तीय विवेकशीलता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- ❖ **ऋण और कर्ज प्रबंधन:** बजट सत्र से पहले राज्य ने ₹5,600 करोड़ का ऋण लिया, साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि कर्ज का स्तर प्रबंधनीय सीमाओं के भीतर बना हुआ है।
- ❖ **आर्थिक वृद्धि संकेतक:** राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण में लगभग 8% की अनुमानित विकास दर दर्ज की गई है, जो निरंतर आर्थिक विस्तार को दर्शाती है।
- ❖ **रोलिंग बजट का नवाचार:** पहली बार राज्य ने रोलिंग बजट प्रणाली अपनाई है। यह एक अनुकूल वित्तीय योजना पद्धति है, जिसमें तय 12 माह की अवधि से आगे बढ़कर बजट की प्रगति के साथ अतिरिक्त महीनों या तिमाहियों को जोड़ा जा सकता है।
 - ⦿ इसका उद्देश्य वित्तीय प्रतिक्रिया क्षमता और योजना निर्माण को बेहतर बनाना है।
- ❖ **महत्त्व:** बजट योजना में समावेशी कल्याण को प्राथमिकता दी गई है, जो महिलाओं, किसानों और गरीब वर्गों के लिये सामाजिक-आर्थिक समर्थन की दिशा में बदलाव का संकेत देती है।

जबलपुर में पहला UN स्मॉल आर्म्स कंट्रोल प्रशिक्षण कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

भारत ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिये स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स (SALW) के नियंत्रण पर पहला संयुक्त राष्ट्र फेलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया।

मुख्य बिंदु

- ❖ **UN SALW प्रशिक्षण:** एशिया में पहली बार भारत ने अवैध हथियारों के प्रसार के विरुद्ध क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स (SALW) के नियंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र फेलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी की है।
 - ⦿ **स्थल:** यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट (MCM) में भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
- ❖ **आयोजक:** इस प्रशिक्षण का आयोजन संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण कार्य कार्यालय (UNODA) द्वारा एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिये शांति एवं निरस्त्रीकरण के क्षेत्रीय केंद्र (UNRCPD) के माध्यम से किया जा रहा है। यह भारत के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के संरक्षण में आयोजित है।
 - ⦿ एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 13 देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं, जिससे यह निरस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है।
- ❖ **क्षमता निर्माण:** यह प्रशिक्षण दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय साधनों के कार्यान्वयन पर केंद्रित है:
 - ⦿ **संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम कार्ययोजना (UN Programme of Action - PoA):** स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स के अवैध व्यापार को सभी रूपों में रोकने, उससे निपटने तथा उसे समाप्त करने हेतु वैश्विक प्रतिबद्धता।
 - ⦿ **अंतर्राष्ट्रीय ट्रेसिंग उपकरण (International Tracing Instrument - ITI):** अवैध SALW की समयबद्ध और विश्वसनीय पहचान एवं अनुरेखण हेतु एक मानक व्यवस्था।
 - ⦿ स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स (SALW) का प्रसार संघर्ष, आतंकवाद और संगठित अपराध का एक प्रमुख कारण है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ **भारत की वैश्विक भूमिका:** यह पहल वैश्विक सुरक्षा शासन में एक जिम्मेदार भागीदार के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करती है तथा हथियार नियंत्रण, सुरक्षित भंडारण प्रबंधन और निरस्त्रीकरण प्रशिक्षण में उसकी विशेषज्ञता को प्रदर्शित करती है।
- इस प्रकार भारत ने क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक शांति तथा उत्तरदायी हथियार प्रबंधन व्यवस्था में अपने योगदान को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने किया सरसों के किसानों के लिये भावांतर भुगतान योजना का विस्तार

चर्चा में क्यों ?

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से भावांतर योजना को सरसों तक विस्तारित कर दिया है तथा प्रमुख फसलों के लिये सहायक उपायों की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु

- ◆ **कृषि पर विशेष ध्यान:** राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से वर्ष 2026 को 'कृषक कल्याण वर्ष' घोषित किया है।
- ◆ **पाँच लक्षित फसलें:** नई सहायता घोषणाओं के अंतर्गत प्रमुख फसलों में उड़द, सरसों, चना, मसूर और तुअर (अरहर) शामिल हैं।
 - उड़द की कृषि करने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अतिरिक्त ₹600 प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा, जिससे इस दलहन फसल की कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा।
- ◆ **सरसों के लिये भावांतर:** सरकार ने सरसों के लिये भावांतर भुगतान योजना का विस्तार किया है, जिसके तहत MSP और वास्तविक बाजार मूल्य के बीच यदि कोई अंतर होगा तो उस मूल्यांतर की भरपाई किसानों को की जाएगी।
 - तुअर (अरहर) की खरीद के लिये मूल्य समर्थन व्यवस्था के अंतर्गत NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय खरीद एजेंसियों के माध्यम से प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है।
- ◆ **उद्देश्य:** इन उपायों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को अपनी उपज के लिये लाभकारी मूल्य मिलें, मूल्य अस्थिरता के जोखिम कम हों, फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले और अंततः ग्रामीण आय में वृद्धि हो।
- ◆ **महत्त्व:** मध्य प्रदेश की नवीनतम कृषि नीति घोषणाएँ वित्तीय प्रोत्साहनों, सुदृढ़ खरीद प्रणालियों और प्रमुख फसलों के लिये मूल्य जोखिम न्यूनीकरण के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने की बहु-आयामी रणनीति को दर्शाती हैं।
 - ये निर्णय ग्रामीण विकास और दीर्घकालिक कृषि अनुकूलन पर राज्य सरकार के निरंतर फोकस की पुष्टि करते हैं।

सांसद ने पहले राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव-2026 का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों ?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव-2026 का उद्घाटन किया। यह एक अनूठा खेल आयोजन है, जिसमें दिव्यांग खिलाड़ी 100 घंटे तक लगातार क्रिकेट खेलकर एक नया वैश्विक रिकॉर्ड स्थापित करेंगे।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
कलासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- ◆ **महोत्सव का उद्घाटन:** मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित पहले राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव-2026 की शुरुआत की।
 - उन्होंने पिच पर उतरकर बल्लेबाजी की और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की टीमों के बीच पहले मैच का औपचारिक उद्घाटन किया।
- ◆ **थीम:** यह महोत्सव 'नॉट आउट @ 100' थीम पर आधारित है, जिसके अंतर्गत 25 राज्यों के लगभग 350 दिव्यांग खिलाड़ी 100 घंटे तक लगातार क्रिकेट खेलेंगे। यह आयोजन वैश्विक स्तर पर अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है।
 - यह खेल महोत्सव सामाजिक सुधारक स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी को समर्पित है, जो रिकॉर्ड बनाने से आगे सामाजिक उत्थान का संदेश देता है।
- ◆ **आयोजन:** इस महोत्सव में मैराथन स्टाइल में कई T-20 मैच खेले जा रहे हैं। इसका आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट, TASK इंटरनेशनल सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च तथा अन्य सहयोगी संगठनों के सहयोग से किया जा रहा है।
 - आयोजक 100 घंटे तक चलने वाले इस निरंतर क्रिकेट आयोजन का दस्तावेजीकरण कर इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल कराने की योजना बना रहे हैं।
- ◆ **महत्त्व:** यह महोत्सव न केवल विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने का लक्ष्य रखता है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग खिलाड़ियों में खेल भावना, समावेशन और सशक्तीकरण को भी बढ़ावा देता है। यह एक सशक्त संदेश देता है कि संकल्प और अवसर के साथ किसी भी सीमा को पार किया जा सकता है।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

भारत की रामसर सूची में दो नई आर्द्रभूमियाँ शामिल की

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 से पहले भारत की रामसर सूची में दो नई आर्द्रभूमियों को जोड़े जाने की घोषणा की।

मुख्य बिंदु

- ❖ नई रामसर स्थल: उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के कच्छ जिले में स्थित छारी-ढांड को भारत की रामसर सूची में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमियों के रूप में शामिल किया गया है।
 - ⦿ भारत का रामसर नेटवर्क वर्ष 2014 में 26 स्थलों से बढ़कर वर्ष 2026 में 98 स्थलों तक पहुँच गया है।
- ❖ पटना पक्षी अभयारण्य: यह सबसे छोटे संरक्षित पक्षी अभयारण्यों में से एक है और एक महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव-विविधता क्षेत्र (IBA) भी है।
- ❖ छारी-ढांड आर्द्रभूमि: कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित एक मौसमी लवणीय आर्द्रभूमि, जो प्रवासी जलपक्षियों और मरुस्थलीय जैव-विविधता के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है।
 - ⦿ यह नलसरोवर, थोल, खिजड़िया और वधवाना के बाद गुजरात का पाँचवाँ रामसर स्थल है।
- ❖ महत्व: नए जोड़े गए स्थल सैकड़ों प्रवासी और स्थानीय पक्षी प्रजातियों का समर्थन करते हैं तथा संकटग्रस्त पक्षियों के अतिरिक्त चिंकारा, भेड़िये, कैराकल, मरु बिल्ली एवं मरु लोमड़ी जैसे वन्यजीवों का भी आवास हैं।
- ❖ प्रासंगिकता: रामसर सूची में शामिल होना वैश्विक रूप से स्वीकृत ढाँचों के अंतर्गत आर्द्रभूमि संरक्षण और सतत प्रबंधन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दर्शाता है।
- ❖ रामसर कन्वेंशन: यह आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिस पर वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किये गए थे।
 - ⦿ भारत 1 फरवरी, 1982 को इसका पक्षकार बना।
- ❖ विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026: यह 2 फरवरी को मनाया जाता है।
 - ⦿ थीम: आर्द्रभूमियाँ और पारंपरिक ज्ञान: सांस्कृतिक विरासत का उत्सव।

MoSPI ने PAIMANA पोर्टल लॉन्च किया

चर्चा में क्यों ?

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने ₹150 करोड़ और उससे अधिक लागत वाले केंद्रीय क्षेत्र के अवसंरचना परियोजनाओं के लिये PAIMANA नामक एक नया वेब-आधारित निगरानी पोर्टल शुरू किया है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- ◆ **PAIMANA:** इसका पूर्ण रूप **प्रोजेक्ट असेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन-बिल्डिंग पोर्टल** है और यह बड़े अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी के लिये एक केंद्रीकृत डिजिटल मंच है।
 - यह वास्तविक-समय ट्रैकिंग और विश्लेषण में सुधार हेतु पूर्ववर्ती **OCMS-2006 (ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम)** का स्थान ले चुका है।
- ◆ **एकीकरण:** PAIMANA को **DPIIT के इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल** के साथ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) के माध्यम से जोड़ा गया है, जिससे स्वचालित डेटा प्रवाह संभव होता है और मैनुअल डेटा प्रविष्टि कम होती है।
 - यह एकीकरण 'वन डेटा, वन एंट्री' सिद्धांत का पालन करता है, ताकि परियोजना रिपोर्टिंग को मानकीकृत किया जा सके और त्रुटियाँ न्यूनतम हों।
- ◆ **परियोजना कवरेज:** दिसंबर 2025 तक कुल 1,392 चालू केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाएँ PAIMANA पोर्टल पर शामिल की जा चुकी हैं।
- ◆ **क्षेत्रीय विस्तार:** परियोजनाएँ परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स, रेलवे, कोयला, विद्युत, आवास एवं शहरी कार्य, जल संसाधन, दूरसंचार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आदि प्रमुख क्षेत्रों में फैली हुई हैं।
- ◆ **विशेषताएँ:** यह पोर्टल बेहतर निगरानी और निर्णय-निर्माण के लिये इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, उन्नत विश्लेषण, भूमिका-आधारित पहुँच, स्वचालित रिपोर्ट तथा क्वेरी मॉड्यूल प्रदान करता है।
- ◆ **उद्देश्य:** प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, डेटा गुणवत्ता और समयबद्धता को बढ़ाना, जिससे राष्ट्र-निर्माण तथा आर्थिक विकास को समर्थन मिले।

मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज UNESCO विश्व धरोहर सूची के लिये नॉमिनेट हुए

चर्चा में क्यों ?

भारत ने मेघालय की लिविंग रूट ब्रिज को 'जिंगकिंग जरी/ल्यू च्राई सांस्कृतिक परिदृश्य' शीर्षक के अंतर्गत UNESCO में नामांकन दस्तावेज़ (डॉसियर) के रूप में प्रस्तुत किया है।

मुख्य बिंदु

- ◆ **नामांकन प्रस्तुत:** UNESCO में भारत के राजदूत **विशाल वी. शर्मा** ने UNESCO विश्व धरोहर केंद्र के निदेशक को नामांकन दस्तावेज़ सौंपा।
 - **धरोहर का महत्व:** यह नामांकन इन लिविंग रूट ब्रिज के सांस्कृतिक, पारिस्थितिक और तकनीकी महत्त्व पर प्रकाश डालता है, जिसमें पारंपरिक पारिस्थितिक प्रबंधन तथा पीढ़ीगत ज्ञान पर जोर दिया गया है।
- ◆ **स्थान:** ये ब्रिज मुख्यतः मेघालय में खासी और जयंतिया पहाड़ियों की दक्षिणी ढलानों में स्थित हैं।
- ◆ **सांस्कृतिक महत्त्व:** ये ब्रिज स्वदेशी खासी और जयंतिया समुदायों द्वारा निर्मित तथा संरक्षित जैव-अभियांत्रिक (Bio-engineered) संरचनाएँ हैं।
 - ये लोगों, प्रकृति और पारंपरिक ज्ञान के बीच गहरे सामंजस्य का प्रतीक हैं।
- ◆ **वैश्विक मान्यता:** यदि इसे स्वीकृति मिलती है तो यह स्थल UNESCO विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त करेगा, जिससे वैश्विक पहचान मिलेगी और संरक्षण प्रयासों तथा सतत पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



पश्चिम बंगाल में पुलिस में बड़ा फेरबदल: पीयूष पांडे को कार्यवाहक DGP नियुक्त किया

चर्चा में क्यों ?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले किये गए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल में राज्य सरकार ने वरिष्ठ IPS अधिकारी पीयूष पांडेय को राजीव कुमार के स्थान पर कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त किया है।

मुख्य बिंदु

- ◆ **DGP नियुक्ति नियम: प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006)** के निर्णय के अनुसार—
 - **चयन:** राज्यों को पात्र वरिष्ठ अधिकारियों की सूची UPSC को भेजनी होती है।
 - **संक्षिप्त सूची:** UPSC योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर तीन अधिकारियों का एक पैनल तैयार करता है।
 - **कार्यकाल:** सेवानिवृत्ति की तिथि चाहे जो भी हो, DGP का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष होना चाहिये।
- ◆ **कार्यवाहक DGP:** सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार 'कार्यवाहक DGP' नियुक्त करने की प्रथा को हतोत्साहित किया है और इस तर्क पर जोर दिया है कि वर्तमान पदाधिकारी के सेवानिवृत्त होने से पहले स्थायी नियुक्ति अंतिम कर ली जानी चाहिये।
- ◆ **चुनाव-पूर्व तैयारी:** 52 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला-पुनर्नियोजन विधानसभा चुनावों से पहले प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिये एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है।
- ◆ **'कार्यवाहक' DGP की प्रवृत्ति:** यह नियुक्ति अंतरिम व्यवस्थाओं की परंपरा को आगे बढ़ाती है। चयन पैनल को लेकर राज्य सरकार और UPSC के बीच चल रहे कानूनी विवादों के कारण पश्चिम बंगाल में दिसंबर 2023 से कोई स्थायी DGP नहीं रहा है।
- ◆ **कानूनी अड़चनें:** स्थायी नियुक्ति से संबंधित मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

अमेरिकी म्यूज़ियम लौटाएगा तमिलनाडु से चोरी तीन दुर्लभ कांस्य मूर्तियाँ

चर्चा में क्यों ?

स्मिथसोनियन के नेशनल म्यूज़ियम ऑफ एशियन आर्ट ने घोषणा की है कि वह तीन प्राचीन कांस्य मूर्तियाँ भारत को वापस करेगा। यह निर्णय कई वर्षों तक चली स्रोत-जाँच के बाद लिया गया है, जिसमें यह पुष्टि हुई कि ये कलाकृतियाँ तमिलनाडु के मंदिरों से अवैध रूप से हटाई गई थीं।

मुख्य बिंदु

- ◆ **वापस लाई गई मूर्तियाँ:** ये तीनों धरोहर दक्षिण भारतीय कांस्य शिल्पकला की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं, जिन्हें मूल रूप से मंदिर अनुष्ठानों में पवित्र शोभायात्रा मूर्तियों (उत्सव मूर्तियों) के रूप में उपयोग किया जाता था—
 - **शिव नटराज:** चोल काल की एक उत्कृष्ट कृति, जो लगभग 990 ईस्वी की मानी जाती है।
 - **सोमस्कंद:** 12वीं शताब्दी की चोलकालीन कांस्य प्रतिमा, जिसमें शिव अपनी पत्नी पार्वती और पुत्र स्कंद के साथ दर्शाए गए हैं।
 - **परवई के साथ संत सुंदरर:** 16वीं शताब्दी की विजयनगर कालीन कांस्य मूर्ति, जिसमें तमिल संत और उनकी पत्नी को दर्शाया गया है।
- ◆ **पहचान:** मूर्तियों के मूल स्थानों की पुष्टि पुदुचेरी स्थित फ्रेंच इंस्टीट्यूट के अभिलेखागार में उपलब्ध 1950 के दशक की दुर्लभ तस्वीरों के माध्यम से की गई।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ मूल स्थल: शिव नटराज की मूर्ति तंजावुर जिले के श्री भव औषधेश्वर मंदिर से चुराई गई थी।
- ❶ सोमस्कंद की प्रतिमा तिरुवरूर जिले के अलाथुर गाँव स्थित विश्वनाथ स्वामी मंदिर से संबंधित पाई गई।
- ❶ संत सुंदरर की मूर्ति कल्लाकुरिची जिले के वीरसोलापुरम गाँव के एक शिव मंदिर से प्राप्त हुई थी।
- ❖ संग्रहालय की नैतिक प्रतिबद्धता: स्मिथसोनियन संग्रहालय ने मूर्तियों की वापसी पर सहमति देने के आधार के रूप में अपनी नैतिक प्रबंधन और पारदर्शिता नीतियों का हवाला दिया, जिसमें इसकी 'साझा प्रबंधन और नैतिक वापसी नीति' (Shared Stewardship and Ethical Returns Policy) भी शामिल है।
- ❖ सांस्कृतिक विरासत की पुनर्स्थापना: पवित्र मंदिर-कांस्य मूर्तियों की वापसी भारत के अपने कलात्मक वंश और धार्मिक इतिहास को पुनः प्राप्त करने के प्रयासों को सशक्त बनाती है।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने टाइम्स B-स्कूल रैंकिंग 2026 में टॉप किया

चर्चा में क्यों ?

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) ने टाइम्स B-स्कूल रैंकिंग 2026 में पहला स्थान हासिल किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक व्यवसाय शिक्षा पर विशेष ध्यान देने वाले भारत के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों में उसकी स्थिति और सुदृढ़ हुई है।

मुख्य बिंदु

- ❖ IIFT: यह वर्ष 1963 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया।
- ❶ स्थिति: यह एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है जिसके परिसर दिल्ली, कोलकाता, काकिनाडा और गिफ्ट सिटी में स्थित हैं।
- ❶ मुख्य फोकस: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये विशेष रूप से तैयार प्रमुख MBA कार्यक्रम, कार्यकारी शिक्षा और डॉक्टरल अनुसंधान प्रदान करता है।
- ❖ SRM यूनिवर्सिटी AP (पारी स्कूल ऑफ बिजनेस): शीर्ष उभरते B-स्कूल श्रेणी में प्रथम स्थान पर रही।
- ❖ रैंकिंग का महत्त्व: टाइम्स B-स्कूल रैंकिंग 2026 शैक्षणिक उत्कृष्टता, रोजगार परिणाम, उद्योग सहभागिता, पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता और प्रतिष्ठा जैसे मापदंडों पर बिजनेस स्कूलों का मूल्यांकन करती है।
- ❶ नेतृत्वकारी भूमिका: IIFT का प्रथम स्थान हासिल करना अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय शिक्षा में उसकी मजबूती और वैश्विक व्यापार की गतिशीलताओं के लिये भविष्य के अभिकर्ताओं को तैयार करने में उसकी भूमिका को दर्शाता है।
- ❖ रणनीतिक विस्तार: यह उपलब्धि संस्थान के बढ़ते वैश्विक उन्मुखीकरण, शैक्षणिक कठोरता और दुबई में उसके ऑफशोर परिसर जैसी नई पहलों की शुरुआत को श्रेय दिया जाता है।
- ❖ विज्ञान 2047: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने जोर दिया कि संस्थान की उत्कृष्टता 'विकसित भारत' के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है और ऐसे प्रशिक्षित कार्यबल को तैयार कर रही है जो भारत को वैश्विक व्यापार की महाशक्ति बनाने में सक्षम हों।

कैप्टन हंसजा शर्मा रुद्रा आर्म्ड हेलीकॉप्टर की पहली महिला पायलट बनीं

चर्चा में क्यों ?

कैप्टन हंसजा शर्मा ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि वे भारतीय सेना में रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिये बनने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। यह अत्याधुनिक हथियारों से लैस हेलीकॉप्टर अग्रिम मोर्चा पर युद्धक भूमिकाओं में इस्तेमाल किया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- ❖ **ऐतिहासिक उपलब्धि:** जहाँ अब तक महिलाएँ परिवहन और उपयोगिता हेलीकॉप्टरों (जैसे चीता और चेतक) को उड़ाती रही हैं, वहीं कैप्टन शर्मा एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH-WSI) रुद्र—एक समर्पित आक्रमण मंच पर स्थानांतरित होने वाली पहली महिला बनी हैं।
- ❖ **रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर:** रुद्र, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा विकसित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) का सशस्त्र संस्करण है।
 - ⦿ यह 20 मिमी टॉर्न (Turret) गन, 70 मिमी रॉकेट तथा टैंक-रोधी निर्देशित मिसाइलों से लैस है।
 - ⦿ इसे निकटवर्ती वायु सहायता (CAS) और उच्च-ऊँचाई वाले युद्ध अभियानों के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- ❖ **युद्ध भूमिकाओं में लैंगिक समानता:** यह उपलब्धि वर्ष 2021 में महिलाओं को आर्मी एविएशन कोर में पायलट के रूप में शामिल करने के निर्णय के बाद संभव हुई। इससे पहले महिलाएँ प्रायः स्थानीय जिम्मेदारियों या गैर-युद्धक उड़ानों तक सीमित थीं।
- ❖ **एविएशन कोर का आधुनिकीकरण:** कैप्टन शर्मा जैसे प्रशिक्षित पायलटों को रुद्र बेड़े में शामिल करने से सेना की आकाशीय 'आँखों और कानों' की संचालन क्षमता और मजबूत होती है।
- ❖ **स्वदेशी शक्ति का प्रतीक:** रुद्र का संचालन रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ मानव कौशल के समन्वय को प्रदर्शित करता है।

SBI ने उभरते क्षेत्रों के वित्तपोषण के लिये CHAKRA सेंटर लॉन्च किया

चर्चा में क्यों ?

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने उभरते क्षेत्रों (सनराइज सेक्टर) के वित्तपोषण को समर्थन देने के लिये 'CHAKRA' नामक एक समर्पित उत्कृष्टता केंद्र (CoE) शुरू किया है। यह देश के सबसे बड़े ऋणदाता द्वारा भावी पीढ़ी के उद्योगों में पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक रणनीतिक पहल को दर्शाता है।

मुख्य बिंदु

- ❖ **उद्देश्य:** यह पहल वर्ष 2030 तक भविष्य-उन्मुख महत्वपूर्ण उद्योगों में ₹100 लाख करोड़ से अधिक के पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखती है।
- ❖ **विज्ञान:** यह परियोजना मूल्यांकन, साक्ष्य-आधारित नीति संवाद, श्वेत पत्र (White Papers) और उद्योग गोलमेज बैठकों के माध्यम से निवेशकों तथा नीति-निर्माताओं को जानकारी उपलब्ध कराएगी।
- ❖ **आठ केंद्रित 'उभरते' क्षेत्र:** यह उत्कृष्टता केंद्र विशेष रूप से विकसित भारत 2047 के विज्ञान के लिये आवश्यक क्षेत्रों को लक्ष्य बनाता है—
 - ⦿ हरित ऊर्जा: नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन एवं अमोनिया तथा डीकार्बोनाइजेशन।
 - ⦿ प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना: सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर अवसंरचना और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर।
 - ⦿ भविष्य की गतिशीलता: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (ई-मोबिलिटी) और उन्नत सेल रसायन (ACC)/बैटरी भंडारण।
- ❖ **जोखिम प्रबंधन:** पारंपरिक थिंक-टैंक के विपरीत, CHAKRA को एक 'व्यावहारिक कार्यान्वयन मंच' के रूप में तैयार किया गया है, जो उभरती तकनीकों के लिये विशेष जोखिम मॉडल विकसित करेगा ताकि असंगत या समयपूर्व निवेश से बचा जा सके।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ वैश्विक साझेदारियाँ: SBI ने संयुक्त परियोजना मूल्यांकन और सह-वित्तपोषण को सक्षम करने के लिये जापान के MUFG और SMBC सहित 21 घरेलू व वैश्विक वित्तीय संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं।

तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा शिपबिल्डिंग क्लस्टर

चर्चा में क्यों ?

भारत को वैश्विक समुद्री केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के तहत तमिलनाडु में नेशनल शिपबिल्डिंग एंड हेवी इंडस्ट्रीज़ पार्क (NSHIP, TN) की स्थापना की गई है, जो विशाल जहाज निर्माण क्लस्टर के विकास के लिये समर्पित देश का पहला विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) है।

मुख्य बिंदु

- ❖ संयुक्त उद्यम: यह SPV वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट प्राधिकरण (VOCPA) जो केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख बंदरगाह है और तमिलनाडु राज्य उद्योग प्रोत्साहन निगम (SIPCOT) के बीच 50:50 की साझेदारी है।
- ❖ रणनीतिक स्थान: यह क्लस्टर तूतीकोरिन (थूथुकुडी) में विकसित किया जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के निकट अपनी रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाएगा।
- ❖ परियोजना विनिर्देश: यह ग्रीनफील्ड क्लस्टर लगभग 2,000 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा, जिसमें 2 किलोमीटर लंबा जलतट (वॉटरफ्रंट) शामिल होगा।
 - ⦿ 1,000 एकड़ क्षेत्र विशेष रूप से शिपयार्ड के लिये आरक्षित होगा।
 - ⦿ शेष 1,000 एकड़ में सहायक उद्योग, समुद्री उपकरण निर्माण तथा सामान्य सामाजिक अवसंरचना विकसित की जाएगी।
- ❖ क्षमता लक्ष्य: इस क्लस्टर को ऐसे शिपयार्ड स्थापित करने के लिये डिजाइन किया गया है, जिनकी कुल क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 1.2 मिलियन ग्राँस टनेज (GT) होगी।
- ❖ आर्थिक गुणक प्रभाव: इस परियोजना से 55,000 से अधिक लोगों के लिये रोजगार सृजन और बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश आकर्षित होने की संभावना है।
- ❖ वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता: यह 'प्लग-एंड-प्ले' औद्योगिक केंद्र विकसित करके भारत की वैश्विक जहाज निर्माण में हिस्सेदारी बढ़ाने में सहायता करेगा।

नागालैंड में नई पुष्पीय पौध प्रजाति होया नागाएंसिस की खोज

चर्चा में क्यों ?

नागालैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने नागालैंड के उच्च-पर्वतीय क्षेत्रों में एक नई पुष्पीय पौध प्रजाति की खोज की है।

मुख्य बिंदु

- ❖ वैज्ञानिक नाम: होया नागाएंसिस (*Hoya nagaensis*)
 - ⦿ कम-अन्वेषित वनों में किये गए व्यवस्थित वनस्पति सर्वेक्षणों के दौरान इसका दस्तावेजीकरण किया गया।
- ❖ खोज स्थल: कावुनहोउ सामुदायिक आरक्षित वन, फेक जिला, नागालैंड।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- यह खोज सामुदायिक संरक्षण वाले वनों के महत्त्व को रेखांकित करती है, क्योंकि ऐसे वन प्रायः मानव हस्तक्षेप से लगभग मुक्त होते हैं और जैव विविधता से समृद्ध रहते हैं।
- ◆ IUCN स्थिति: अत्यंत संकटग्रस्त (Critically Endangered)।
- ◆ जैव विविधता हॉटस्पॉट: नागालैंड के उच्च-पर्वतीय वन पूर्वी हिमालयी जैव-विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा हैं।
- ◆ अनुसंधान महत्त्व: यह खोज भारत के वनस्पति अभिलेखों और वैश्विक पादप विज्ञान के लिये महत्त्वपूर्ण आँकड़े जोड़ती है तथा क्षेत्र में आगे पारिस्थितिक एवं संरक्षण-आधारित अध्ययनों को प्रोत्साहित करती है।

गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की

चर्चा में क्यों ?

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ग्रामीण शासन व्यवस्था और अवसंरचना को मजबूत करने के लिये मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की।

मुख्य बिंदु

- ◆ स्थल: गुजरात के आनंद ज़िले के भादरण गाँव में इसकी आधारशिला रखी गई।
- ◆ कवरेज: स्थानीय शासन को सुदृढ़ करने के लिये 2,666 गाँवों में ग्राम पंचायत भवन-सह-तलाटी आवास का निर्माण किया जाएगा।
- वित्तपोषण: गाँव स्तर पर कार्यशील पंचायत अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु ₹663 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है।
- ◆ शहरी-सदृश सुविधाएँ: योजना में सड़कें, जल आपूर्ति, स्वच्छता, सौर स्ट्रीट लाइट, ई-ग्राम डिजिटल सेवाएँ और सामुदायिक भवन जैसी आधुनिक सुविधाएँ शामिल हैं।
- ◆ फोकस: प्रारंभिक चरण में उन 114 गाँवों के विकास को लक्ष्य बनाया गया है जो तालुका मुख्यालय के रूप में कार्य करते हैं लेकिन जिनके पास नगरपालिका दर्जा नहीं है।
- ग्रामीण-शहरी अंतर को कम करने के लिये ग्रामीण नागरिकों तक आवश्यक सेवाएँ पहुँचाने का उद्देश्य है।
- ◆ भविष्य विस्तार: पूरे गुजरात में अन्य बड़ी ग्राम पंचायतों (जनसंख्या 10,000 से अधिक) को भी शामिल करने की योजना है।
- ◆ महत्त्व: इससे ग्रामीण शासन क्षमता में वृद्धि होगी, सेवा-प्रदान में सुधार आएगा और शहरी क्षेत्रों के समान अवसंरचनात्मक सुविधाएँ विकसित होंगी।

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2026 का ऑस्ट्रेलियन ओपन (जो मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है) का समापन पुरुष एकल में कार्लोस अल्काराज़ तथा महिला एकल में एलेना रिबाकिना की जीत के साथ हुआ।

मुख्य बटु

- ◆ पुरुष एकल विजेता: कार्लोस अल्काराज़ (स्पेन) ने फाइनल में नोवाक जोकोविच (सर्बिया) को हराकर वर्ष 2026 के ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- उपविजेता: नोवाक जोकोविच (सर्बिया) फाइनल मुकाबले में अल्काराज से हारकर उपविजेता रहे।
- ◆ ऐतिहासिक उपलब्धि (पुरुष श्रेणी में): यह अल्काराज का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब और कुल मिलाकर उनका सातवाँ ग्रैंड स्लैम एकल खिताब था।
- ◆ महिला एकल विजेता: एलेना रिबाकिना (कज़ाख़स्तान) ने आर्यना सबालेंका (बेलारूस) को हराकर महिला एकल खिताब अपने नाम किया।
- उपविजेता: आर्यना सबालेंका (बेलारूस) फाइनल में रिबाकिना से हारकर उपविजेता रहीं।
- ◆ महिला वर्ग की उपलब्धि: यह जीत रिबाकिना का दूसरा ग्रैंड स्लैम एकल खिताब और पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब था, जिससे शीर्ष खिलाड़ी के रूप में उनकी क्षमता का प्रदर्शन हुआ।
- ◆ आयोजन स्थल: यह टूर्नामेंट मेलबर्न पार्क के हार्ड कोर्ट्स में आयोजित हुआ, जिसमें विश्व भर के शीर्ष टेनिस खिलाड़ियों ने भाग लिया।

अभ्यास अग्नि परीक्षा: भारतीय सेना-ITBP की संयुक्त पहल

चर्चा में क्यों ?

भारतीय सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 'अग्नि परीक्षा' नामक छह दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का सफल समापन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य सीमा क्षेत्रों में दोनों बलों के बीच परिचालन समन्वय को सुदृढ़ करना था।

मुख्य बिंदु

- ◆ स्थान: यह अभ्यास अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के सिगार क्षेत्र में आयोजित हुआ।
- ◆ उद्देश्य: इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य नॉन-आर्टिलरी कार्मिकों (जिनमें इन्फैंट्री और ITBP के जवान शामिल हैं) को तोपखाना प्रक्रियाओं, फायर कंट्रोल सिस्टम, समन्वय तंत्र तथा यथार्थपरक फील्ड परिस्थितियों में फायरिंग मिशनों के निष्पादन से परिचित कराना था।
- ◆ प्रतिभागी: भारतीय सेना की स्पीयर कॉर्प्स के स्पीयरहेड गनर्स, विभिन्न इन्फैंट्री रेजिमेंट्स तथा ITBP के कार्मिक।
- ◆ महत्व: सीमा सुरक्षा और युद्धक अभियानों हेतु सेना और अर्द्धसैनिक बलों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने में सहायक है।
- परिचालन तत्परता: विशेषकर उच्च तुंगता वाले सीमा क्षेत्रों में जटिल युद्धक्षेत्र परिदृश्यों हेतु सैनिकों की तैयारी और क्षमता को बेहतर बनाने में सहायक है।

सामाजिक विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र आयोग के 64वें सत्र में भारत

चर्चा में क्यों ?

भारत न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित सामाजिक विकास आयोग (CSocD64) के 64वें सत्र में भाग ले रहा है।

मुख्य बिंदु

- ◆ नेतृत्व: न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित सामाजिक विकास आयोग (CSocD) के 64वें सत्र में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ **आयोग:** सामाजिक विकास आयोग (CSocD) संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) की एक प्रमुख इकाई है, जो गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समावेशन, समानता एवं कल्याणकारी नीतियों सहित सामाजिक विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करती है।
- ◆ **अध्यक्ष:**
 - 64वें सत्र की अध्यक्षता यूक्रेन की संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि राजदूत क्रिस्टिना हायोविशिन ने की तथा इसमें 100 से अधिक संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने भाग लिया।
 - भारत इस 64वें सत्र का निर्वाचित सदस्य है, जिसमें सदस्य देश सामाजिक विकास से जुड़े मुद्दों पर प्रगति की समीक्षा करते हैं और अनुभव साझा करते हैं।
- ◆ **भारत का वक्तव्य:**
 - भारत ने रेखांकित किया कि सामाजिक न्याय और सामाजिक संरक्षण सांविधानिक गारंटियों में दृढ़ता से निहित हैं तथा देश के दीर्घकालिक विज्ञान 'विकसित भारत 2047' के अनुरूप हैं।
 - मार्गदर्शक सिद्धांत: 'सबका साथ, सबका विकास' को इस बात का प्रतीक बताया गया कि सरकार और समाज के समग्र दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पीछे न रह जाए।

चित्तूर ज़िले ने ई-साइकिल वितरण के लिये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया

चर्चा में क्यों ?

आंध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िला प्रशासन ने 24 घंटे की अवधि के भीतर 5,555 इलेक्ट्रिक साइकिलों का वितरण कर आधिकारिक रूप से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है।

मुख्य बिंदु

- ◆ **रिकॉर्ड:** इस आयोजन ने 24 घंटे में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक साइकिलें वितरित करने का खिताब हासिल किया, जिससे हरित गतिशीलता (ग्रीन मोबिलिटी) पहलों में पहले के वैश्विक मानकों को पीछे छोड़ दिया गया।
- ◆ **लक्षित लाभार्थी:** ई-साइकिलें मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों विशेष रूप से छात्राओं और हाशिये पर रहने वाले समुदायों से आने वाले छात्रों को प्रदान की गईं, ताकि शिक्षा तक पहुँच बेहतर हो तथा ड्रॉपआउट दर कम की जा सके।
- ◆ **लॉजिस्टिक्स:** वितरण प्रक्रिया का नेतृत्व चित्तूर में पुलिस परेड ग्राउंड्स पर ज़िला प्रशासन (कलेक्टरेट) द्वारा किया गया।
- ◆ **स्थिरता पर जोर:** यह पहल ग्रामीण परिवहन के डी-कार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देती है और जीवाश्म ईंधन आधारित आवागमन पर निर्भरता घटाकर भारत की जलवायु कार्रवाई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।
- ◆ **सामाजिक सशक्तीकरण:** छात्रों को स्वच्छ परिवहन उपलब्ध करारक यह कार्यक्रम 'लास्ट-माइल' कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान करता है, जो प्रायः ग्रामीण शिक्षा में बाधा बनती है।

दलाई लामा ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने अमेरिका के लॉस एंजिल्स में आयोजित 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह (2026) में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- ❖ **पुरस्कार और श्रेणी:** दलाई लामा ने अपने एल्बम 'मेडिटेशन: द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा' के लिये सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक, कथन और कहानी कहने की रिकॉर्डिंग श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता।
 - ⦿ यह उनका पहला ग्रैमी पुरस्कार था, जो उन्होंने 90 वर्ष की आयु में प्राप्त किया, जिससे संगीत के सबसे प्रतिष्ठित मंचों में एक आध्यात्मिक गुरु के लिये यह अद्वितीय पहचान बन गई।
 - ⦿ समारोह में संगीतकार रूफस वेनराइट ने उनकी ओर से पुरस्कार स्वीकार किया।
- ❖ **एल्बम की विषयवस्तु:** यह एल्बम दलाई लामा की शांति, करुणा, जागरूकता और सार्वभौमिक जिम्मेदारी संबंधी शिक्षाओं को संगीत रचनाओं और कथन के साथ मिश्रित करता है, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक सद्भाव का संदेश फैलाना है।
 - ⦿ **सहयोग:** इस एल्बम में भारतीय शास्त्रीय संगीत के उस्ताद उस्ताद अमज़द अली खान और उनके बेटों अमान अली बंगश और अयान अली बंगश का योगदान शामिल है, जबकि इसका निर्माण ग्रैमी पुरस्कार विजेता कबीर सहगल ने किया है।
- ❖ **वैश्विक मान्यता:** यह उपलब्धि दलाई लामा की आवाज़ और शिक्षाओं की वैश्विक पहुँच को रेखांकित करती है, जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कलात्मक सीमाओं से परे जाती है।
- ❖ **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया:** इस उपलब्धि की व्यापक रूप से सराहना की गई, हालाँकि चीनी सरकार ने इसकी आलोचना भी की, जिसने दलाई लामा की स्थिति के संदर्भ में इसे राजनीतिक हस्तक्षेप बताया।

वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 मिला

चर्चा में क्यों ?

भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा भूविज्ञान में वर्ष 2026 का क्रैफोर्ड पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसे प्रायः 'भूविज्ञान का नोबेल' कहा जाता है, क्योंकि इसका महत्त्व उन क्षेत्रों में भी है जो नोबेल पुरस्कारों के अंतर्गत नहीं आते।

मुख्य बिंदु

- ❖ **प्रमुख योगदान:** रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने रामनाथन को "अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों (SLCP) और ग्रीनहाउस प्रभाव की भूमिका की वैज्ञानिक समझ को विस्तारित करने में उनके अग्रणी योगदान" के लिये चयनित किया।
- ❖ **नॉन-CO₂ ग्रीनहाउस गैसों की खोज (1975):** उन्होंने प्रथम बार यह प्रमाणित किया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs), जो पूर्व में केवल ओज़ोन परत के क्षरण से संबंधित माने जाते थे, प्रभावशाली ग्रीनहाउस गैसों के रूप में भी कार्य करते हैं।
- ❖ **वायुमंडलीय ब्राउन मेघ (ABC):** उनके शोध में दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र के ऊपर बने कालिख और धूल के विशाल ब्राउन मेघ की उपस्थिति को रेखांकित किया गया।
- ❖ उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि ये कण (ब्लैक कार्बन) सूर्य विकिरण को अवशोषित कर वायुमंडल को गर्म करते हैं तथा साथ-ही-साथ पृथ्वी की सतह को ठंडा करते हैं, जिससे मानसूनी प्रवृत्तियाँ प्रभावित होती हैं।
- ❖ **क्रैफोर्ड पुरस्कार:**
 - ⦿ इसकी स्थापना वर्ष 1980 में उद्योगपति होल्गर क्रैफोर्ड और उनकी पत्नी अन्ना-ग्रेटा द्वारा की गई थी।
- ❖ **पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था:** रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज (यही संस्था नोबेल पुरस्कार भी प्रदान करती है)।
- ❖ **क्षेत्र :** यह सम्मान उन क्षेत्रों में दिया जाता है जो नोबेल पुरस्कार की परिधि में सम्मिलित नहीं हैं, जैसे- गणित, खगोल विज्ञान, भूविज्ञान तथा जीव विज्ञान।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0: त्रिपुरा की ग्राम पंचायत प्रथम

चर्चा में क्यों ?

त्रिपुरा ने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) 2.0 में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्थानीय शासन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है।

मुख्य बिंदु

- ◆ PAI 2.0 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन: त्रिपुरा के सेपाहिजाला ज़िले के जम्पुइजाला आरडी ब्लॉक में स्थित जुगल किशोर नगर ग्राम समिति ने लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के मूल्यांकन में 88.44 स्कोर के साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- ◆ त्रिपुरा पंचायतों का प्रदर्शन: राज्य का असाधारण प्रदर्शन यहीं सीमित नहीं रहा:
 - दक्षिण नलचर ग्राम पंचायत (नलचर आरडी ब्लॉक, सेपाहिजाला) ने 88.14 अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया।
 - चेश्रीमाई ग्राम पंचायत (चारिलम आरडी ब्लॉक, सेपाहिजाला) ने 87.85 अंकों के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया।
- ◆ पूर्ण भागीदारी: त्रिपुरा ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये अपनी सभी 1,176 ग्राम पंचायतों और ग्राम समितियों के डेटा को 100% जमा और सत्यापित करने का गौरव हासिल किया।
- ◆ पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) 2.0:
 - यह भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है जो देश भर में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है।
 - सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के अनुरूप 9 विषयों में फैले 435 स्थानीय संकेतकों के आधार पर स्थानीय निकायों का मूल्यांकन करता है।
 - प्रमुख संकेतक: इनमें पारदर्शिता, सेवा वितरण, विकेंद्रीकृत योजना, सामुदायिक भागीदारी और शासन के परिणाम शामिल हैं।
- ◆ उद्देश्य: इस सूचकांक का लक्ष्य राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र और स्थानीय स्वशासन को मज़बूत करना है।

कलपेट्टा भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस ज़िला न्यायालय बना

चर्चा में क्यों ?

केरल के वायनाड स्थित कलपेट्टा न्यायिक ज़िला भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस ज़िला न्यायालय बन गया है।

मुख्य बिंदु

- ◆ ऐतिहासिक उपलब्धि: कलपेट्टा भारत का पहला ज़िला न्यायालय बन गया है जो पूर्णतः पेपरलेस और एक पूर्ण डिजिटल न्यायिक प्रणाली में परिवर्तित हो चुका है।
- ◆ उद्घाटन: इस पेपरलेस न्यायालय प्रणाली का वर्चुअल उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने किया।
- ◆ कार्यप्रणाली:
 - न्यायालय की सभी प्रक्रियाएँ पूर्व-विचारण कार्यवाहियाँ, साक्ष्य का अभिलेखन, अंतरिम आदेश और अंतिम निर्णय—अब बिना किसी भौतिक फाइल के इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित की जा रही हैं।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- 'डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम' (DCMS) नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म केरल उच्च न्यायालय के IT विभाग द्वारा सुरक्षित और दक्ष संचालन सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक रूप से विकसित किया गया है।
- ◆ प्रौद्योगिकी: इस प्रणाली में AI-आधारित न्यायिक सहायता उपकरणों का समावेश है, जो संरचित वाद-सार तैयार करने, टिप्पणियाँ जोड़ने, मामलों का विवरण खोजने और न्यायाधीशों को डिजिटल अभिलेखों तक शीघ्र पहुँच प्रदान करने में सहायक हैं।
- ◆ लाभ: पेपरलेस प्रणाली से मुकदमेबाजी की लागत घटने, दस्तावेजों के आवागमन में होने वाली देरी घटने, न्याय तक पहुँच में सुधार होने तथा न्यायिक प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करके 'हरित न्यायशास्त्र' को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- ◆ अन्य जिलों के लिये मॉडल: यह पहल पूरे देश के अन्य न्यायिक जिलों के लिये एक आदर्श के रूप में देखी जा रही है, जिससे पारंपरिक न्यायालय संचालन को कुशल डिजिटल प्रणालियों में बदलने की संभावना है।

तमिलनाडु ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की

चर्चा में क्यों ?

तमिलनाडु ने चेन्नई में आयोजित UmagineTN 2026 प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति का अनावरण किया।

मुख्य बिंदु

- ◆ नीति लॉन्च: डीप टेक स्टार्टअप नीति 2025-26 की शुरुआत तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने चेन्नई में आयोजित UmagineTN 2026 शिखर सम्मेलन में किया।
- तमिलनाडु ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने डीप टेक स्टार्टअप के लिये समर्पित नीति प्रस्तुत की है।
- ◆ कार्यान्वयन: इस नीति के समन्वय और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नोडल एजेंसी, तमिलनाडु टेक्नोलॉजी (iTNT) हब को सौंपी गई है।
- ◆ निवेश एवं स्टार्टअप समर्थन: यह नीति 100 डीप टेक स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने तथा आगामी पाँच वर्षों में सार्वजनिक व निजी निवेश से ₹100 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखती है, ताकि अनुसंधान और बाजार में उपयोग के बीच अंतर को कम किया जा सके।
- इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर, जैव-प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष तकनीक एवं स्वच्छ ऊर्जा जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है, जिनमें उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान और दीर्घकालिक विकास-अवधि शामिल होती है।
- ◆ इकोसिस्टम विकास: इसका उद्देश्य शैक्षणिक और शोध संस्थानों से स्टार्टअप तक तकनीक हस्तांतरण को सुगम बनाना, पेटेंट निर्माण को प्रोत्साहित करना तथा नवाचार के लिये अवसरचना एवं पूंजी समर्थन को मजबूत करना है।
- ◆ सरकारी सहयोग: इस नीति में 'प्रथम उपयोगकर्ता के रूप में सरकार' (गवर्नमेंट एज अर्ली एडॉप्टर) जैसे कार्यक्रम के प्रावधान शामिल हैं, जिसके तहत चयनित सरकारी विभागों में डीप टेक समाधानों का परीक्षण और सत्यापन किया जाएगा, ताकि स्टार्टअप अपनी तकनीकों को प्रमाणित कर सकें।

विश्व कैंसर दिवस 2026

चर्चा में क्यों ?

कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने, शीघ्र पहचान को प्रोत्साहित करने और पूरे विश्व में कैंसर उपचार तक समान पहुँच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 फरवरी, 2026 को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- ◆ **थीम:** वर्ष 2026 की आधिकारिक थीम 'यूनाइटेड बाय यूनिक (United by Unique)' है, जो वर्ष 2025-27 की तीन वर्षीय वैश्विक अभियान शृंखला का हिस्सा है। यह इस तर्क को रेखांकित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति का कैंसर अनुभव भिन्न होता है, फिर भी सभी को समान देखभाल और सम्मान मिलना चाहिये।
 - ⦿ यह थीम व्यक्ति-केंद्रित उपचार पर बल देती है तथा उपचार और उत्तरजीविता की योजना में व्यक्तिगत अनुभवों, आवश्यकताओं एवं सम्मान के महत्त्व को रेखांकित करती है।
- ◆ **उद्देश्य: कैंसर की रोकथाम, शीघ्र पहचान और उपचार के प्रति जागरूकता बढ़ाना।**
 - ⦿ समय पर जाँच (स्क्रीनिंग) और स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करना।
 - ⦿ कैंसर से जुड़े मिथकों, कलंक और भय को तोड़ना।
 - ⦿ रोगियों, उत्तरजीवियों और देखभालकर्ताओं को समर्थन देना।
 - ⦿ पूरे विश्व में समान और गुणवत्तापूर्ण कैंसर देखभाल तक पहुँच में सुधार करना।
- ◆ **भागीदारी:** व्यक्ति, समुदाय, स्वास्थ्य संस्थान और सरकारें जागरूकता अभियानों, शैक्षिक कार्यक्रमों एवं जाँच गतिविधियों के माध्यम से कैंसर के विरुद्ध कार्रवाई को बढ़ावा देने में भाग लेते हैं।
 - ⦿ स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस तर्क पर जोर देते हैं कि शीघ्र पहचान से जीवन बचते हैं और समय पर जाँच व जीवनशैली में बदलाव से अनेक कैंसर मामलों को रोका या बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है।
- ◆ **रोकथाम योग्य कारण: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के विश्लेषण के अनुसार, लगभग 10 में से 4 नए कैंसर मामलों को जोखिम कम करने वाले उपायों जैसे तंबाकू से बचाव, अस्वस्थ आहार और शराब के सेवन में कमी तथा शारीरिक गतिविधि बढ़ाने से रोका जा सकता है।**
- ◆ **समानता और पहुँच:** विश्व कैंसर दिवस विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में उच्च-गुणवत्ता वाली देखभाल तक समान पहुँच की आवश्यकता पर बल देता है, जहाँ संसाधनों तथा जागरूकता की कमी के कारण देर से निदान एवं खराब परिणाम देखने को मिलते हैं।

ओलंपिक शीतकालीन खेल मिलानो कॉर्टिना 2026

चर्चा में क्यों ?

शीतकालीन ओलंपिक खेलों का 25वाँ संस्करण 6 फरवरी से आधिकारिक रूप से शुरू होगा। मिलानो कॉर्टिना 2026 वह पहला अवसर होगा जब दो शहर संयुक्त रूप से शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेंगे और यह चौथी बार है जब इटली शीतकालीन खेलों की मेजबानी करेगा।

मुख्य बिंदु

- ◆ **उद्घाटन समारोह:** 6 फरवरी, 2026 को मिलानो के प्रतिष्ठित सैन सिर्रो स्टेडियम में आयोजित किया गया।
- ◆ **समापन समारोह:** यह 22 फरवरी, 2026 को प्राचीन वेरोना एरिना में होने वाला है।
- ◆ **मास्कॉट्स: टीना और माइलो,** दो स्टोट्स जिनके नाम मेजबान शहरों से प्रेरित हैं (टीना – कॉर्टिना के लिये, माइलो – मिलानो के लिये)।
- ◆ **थीम: 'आर्मोनिया' (संगति)** नाम का यह शो बालिच वंडर स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया है और इसमें मारिया कैरी, एंड्रिया बोसेली एवं लौरा पौसिनी ने परफॉर्म किया है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ **भारत की भागीदारी:** भारत 2026 खेलों में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण दल लेकर गया है, जो वैश्विक शीतकालीन खेलों में भारत की उपस्थिति को जारी रखता है।
- ◆ **एथलीट्स:** अरिफ मोहम्मद खान, एक अनुभवी अल्पाइन स्कीयर, जिन्होंने पहले बीजिंग 2022 शीतकालीन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, अब अल्पाइन स्कीइंग श्रेणी में क्वालीफाई कर चुके हैं।
 - **स्टैनज़िन लुंडुप:** क्रॉस-कंट्री स्कीइंग में प्रतिस्पर्द्धा करेंगे। उनकी भागीदारी एक चयन प्रक्रिया के बाद सुनिश्चित हुई, जिसमें राष्ट्रीय कोटा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय अहम रहा।
- ◆ **भारत की शीतकालीन ओलंपिक में भागीदारी:** जबकि शीतकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 1924 में शुरू हुए, भारत ने वर्ष 1964 में अपनी शुरुआत की।
 - आगामी मिलाओ कॉर्टिना ओलंपिक्स सहित, भारत 12 शीतकालीन ओलंपिक संस्करणों में भाग ले चुका है, जिसमें अब तक 17 अलग-अलग एथलीटों ने देश का प्रतिनिधित्व किया।

आंध्र प्रदेश में भारत का पहला स्वदेशी हरित यूरिया संयंत्र

चर्चा में क्यों ?

भारत का पहला बड़े पैमाने पर स्वदेशी हरित यूरिया संयंत्र आंध्र प्रदेश के पुडीमडका ग्रीन हाइड्रोजन हब में विकसित किया जाएगा और चालू किया जाएगा।

मुख्य बिंदु

- ◆ **रणनीतिक समझौता ज्ञापन (MoU):** NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL), जो NTPC लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है और असागो इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक MoU पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
 - समझौते के तहत, NGEL असागो को हरित अमोनिया, नवीकरणीय विद्युत, CO₂ तथा अन्य उपयोगिताएँ उपलब्ध कराएगा।
- ◆ **उद्देश्य:** हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके हरित यूरिया का उत्पादन करना, जिससे जीवाश्म ईंधन आधारित अमोनिया पर निर्भरता कम होगी।
 - यह पहल घरेलू हरित यूरिया मूल्य श्रृंखला के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आयातित उर्वरकों पर निर्भरता घटेगी।
 - इसका लक्ष्य रोजगार सृजन करना, हरित ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करना और आंध्र प्रदेश के औद्योगिक विकास में योगदान देना है।
- ◆ **पर्यावरणीय प्रभाव:** पारंपरिक यूरिया संयंत्रों की तुलना में कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है।
 - यह भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य और राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को समर्थन देता है।
- ◆ **नवाचार:** भारत में पहली बार विकसित की जा रही स्वदेशी हरित यूरिया तकनीक, जो उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी।

प्लास्टिंडिया 2026 नई दिल्ली में शुरू हुआ

चर्चा में क्यों ?

प्लास्टिंडिया 2026, जो विश्व की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक है, फरवरी 2026 में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हुई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- ♦ **कार्यक्रम:** यह प्लास्टिक उद्योग के त्रिवार्षिक (हर तीन वर्ष में आयोजित होने वाले) मेगा आयोजन **प्लास्टइंडिया 2026 का 12वाँ संस्करण** है।
 - ⦿ यह आयोजन **पाँच रणनीतिक स्तंभों व्यापार, प्रौद्योगिकी, प्रतिभा, परंपरा और पर्यटन** पर आधारित है, जो उद्योग की वृद्धि, नवाचार, कौशल विकास तथा सांस्कृतिक एकीकरण पर जोर देता है।
- ♦ **आयोजक:** रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग (DCPC), रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय के सहयोग से।
- ♦ **थीम:** प्लास्टइंडिया 2026 का आयोजन 'भारत नेक्स्ट' थीम के अंतर्गत किया जा रहा है।
 - ⦿ यह प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य घरेलू प्लास्टिक उद्योग तथा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है।
- ♦ **सततता पर जोर:** पहली बार इसे **शून्य अपशिष्ट प्रदर्शनी (Zero Waste Exhibition)** के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कार्यक्रम के दौरान उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का पृथक्करण, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

केरल के सीएम ने इनवेसिव स्पीशीज़ डिटेक्शन ऐप लॉन्च किया

चर्चा में क्यों ?

केरल ने पूरे राज्य में आक्रामक पौधों की प्रजातियों की पहचान और निगरानी के लिये विकसित AI-संचालित मोबाइल एप्लीकेशन **NeophyteID** को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है।

मुख्य बिंदु

- ♦ **लॉन्च और विकासकर्ता:** यह ऐप 2 फरवरी, 2026 को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया। इसे मालाबार बॉटनिकल गार्डन एंड इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंसेज़ (MBGIPS) ने विकसित किया है।
- ♦ **AI तकनीक:** YOLOv11 मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करते हुए यह उपकरण केरल में लगभग 98 आक्रामक प्रजातियों की वास्तविक-समय पहचान और भू-स्थानिक (जियोस्पेशियल) ट्रैकिंग प्रदान करता है।
- ♦ **कार्यप्रणाली और पहुँच:** उपयोगकर्ता पौधों की तस्वीर खींचकर अंग्रेज़ी और मलयालम दोनों भाषाओं में त्वरित, डेटा-आधारित पहचान प्राप्त कर सकते हैं।
- ♦ **पारिस्थितिक प्रभाव:** NeophyteID का लक्ष्य उन्मूलन अभियानों के समय देशी पौधों को होने वाली क्षति से बचाना है।
- ♦ **डेटा-आधारित संरक्षण:** AI और भू-स्थानिक ट्रैकिंग का उपयोग शोधकर्ताओं को आक्रामक प्रजातियों के वितरण पैटर्न पर समृद्ध आँकड़े उपलब्ध कराता है, जो हटाने और पुनर्स्थापन रणनीतियों की योजना बनाने के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

भारत ने छठी बार ICC U-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता

चर्चा में क्यों ?

भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड अंडर-19 को बड़े अंतर से हराकर **ICC पुरुष अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2026** की ट्रॉफी अपने नाम की, जिससे इस प्रारूप में भारत ने अपना छठा खिताब जीतकर टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी टीम द्वारा सबसे अधिक खिताब जीतने का रिकॉर्ड कायम किया।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- ◆ ऐतिहासिक जीत: भारत ने जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया।
 - फाइनल में भारत का स्कोर: 411/9
 - इंग्लैंड का स्कोर: 311 (ऑल आउट)
 - उपविजेता: इंग्लैंड (अंडर-19)
 - जीत का अंतर: 100 रन
- ◆ टीम का प्रदर्शन: भारत की पारी को 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की शानदार 175 रनों की पारी ने मजबूती दी, जिसे अंडर-19 क्रिकेट इतिहास की सबसे उल्लेखनीय पारियों में से एक माना जा रहा है।
 - भारतीय कप्तान: आयुष म्हात्रे
 - मैच ऑफ द मैच (फाइनल): वैभव सूर्यवंशी
 - टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी: वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने सात मैचों में शानदार 439 रन बनाए।
- ◆ रिकॉर्ड बढ़ाने वाला खिताब: इस जीत के साथ भारत ने अपना छठा ICC अंडर-19 विश्व कप खिताब जीता, जिससे टूर्नामेंट में देश का रिकॉर्ड और मजबूत हुआ तथा भारत अंडर-19 विश्व कप इतिहास की सबसे सफल टीम बना रहा।
- ◆ युवा प्रतिभा का उदय: इस टूर्नामेंट ने भारतीय क्रिकेट में मजबूत प्रतिभा-शृंखला को उजागर किया। सूर्यवंशी का असाधारण प्रदर्शन और दबाव में टीम की सामूहिक निरंतरता भारतीय क्रिकेट के उज्वल भविष्य का संकेत देती है।

भारतीय टीचर रूबल नागी ने प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 जीता

चर्चा में क्यों ?

भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 से सम्मानित किया गया है।

मुख्य बिंदु

- ◆ पुरस्कार: रूबल नागी ने ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 जीता, जिसके तहत उन्हें 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की गई। यह पुरस्कार दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम द्वारा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान प्रदान किया गया।
- ◆ आयोजक: यह पुरस्कार GEMS एजुकेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और UNESCO के सहयोग से वार्की फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है।
- ◆ कार्य और योगदान: रूबल नागी को पूरे भारत के वंचित समुदायों के बच्चों तक कला-आधारित शिक्षा पहुँचाने के उनके अभिनव प्रयासों के लिये सम्मानित किया गया।
 - रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने 100 से अधिक निम्न-आय वाले समुदायों और गाँवों में 800 से अधिक शिक्षण केंद्र स्थापित किये हैं।
 - ये केंद्र उन बच्चों को संरचित शिक्षण अवसर प्रदान करते हैं जिन्हें औपचारिक शिक्षा तक सीमित या कोई पहुँच नहीं थी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ कला के माध्यम से शिक्षा: उनके कार्य का एक प्रमुख पहलू उपेक्षित दीवारों को इंटरएक्टिव शैक्षिक भित्ति-चित्रों में बदलना है, जिन्हें 'लिविंग वॉलस ऑफ लर्निंग' कहा जाता है। इनसे बच्चों को साक्षरता, संख्या ज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय जागरूकता और अन्य विषय उनके आसपास के वातावरण में ही सिखाए जाते हैं।
 - इस पद्धति से एक मिलियन से अधिक बच्चों को शैक्षिक कार्यक्रमों से जोड़ा गया है और विद्यालय छोड़ने की दर में उल्लेखनीय कमी आई है।
- ◆ चयन और वैश्विक मान्यता: रूबल नागी का चयन 139 देशों से प्राप्त 5,000 से अधिक नामांकनों और आवेदनों में से किया गया, जो शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्य के वैश्विक महत्त्व तथा प्रभाव को दर्शाता है।
- ◆ पुरस्कार राशि का उपयोग: वह इस धनराशि से एक व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की योजना रखती हैं, जहाँ पेशेवर कौशल और डिजिटल साक्षरता का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वंचित बच्चों एवं युवाओं के लिये अवसरों का विस्तार किया जा सके।

यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनीरत्न का दर्जा

चर्चा में क्यों ?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (DPSU) यंत्र इंडिया लिमिटेड (YIL) को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा प्रदान करने की मंजूरी दी है, जो इसे एक सरकारी संगठन से लाभ कमाने वाली कॉर्पोरेट इकाई में रूपांतरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

मुख्य बिंदु

- ◆ यंत्र इंडिया लिमिटेड (YIL): यंत्र इंडिया लिमिटेड का गठन 1 अक्टूबर, 2021 को पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) के निगमीकरण के बाद किया गया था, जिसके तहत रक्षा विनिर्माण में स्वायत्तता, दक्षता और प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने के उद्देश्य से सात नए DPSU बनाए गए।
- ◆ संगठन का प्रकार: यह रक्षा मंत्रालय (MoD) के अंतर्गत रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन एक अनुसूची 'A' श्रेणी का रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (DPSU) है।
- ◆ मुख्य उत्पाद: कार्बन फाइबर कंपोजिट, एल्युमिनियम मिश्रधातु, ग्लास कंपोजिट तथा मध्यम एवं बड़े कैलिबर के गोला-बारूद, बख्तरबंद वाहन, तोपें और मुख्य युद्धक टैंक (MBT) के लिये असेंबली उत्पाद।
- ◆ स्वायत्तता और अधिकारों में वृद्धि: मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा मिलने के बाद YIL का निदेशक मंडल अब सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना ₹500 करोड़ तक के पूंजीगत व्यय प्रस्तावों को स्वतंत्र रूप से मंजूरी दे सकता है।
- ◆ आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा: यह कदम आयात निर्भरता कम करने, स्वदेशी डिजाइन और उत्पादन क्षमताओं को प्रोत्साहित करने तथा रक्षा औद्योगिक आधार को सुदृढ़ करने के लिये आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है।

रॉयल चैलेंजर्स बंगलूरु ने दूसरा खिताब जीता

चर्चा में क्यों ?

रॉयल चैलेंजर्स बंगलूरु (RCB) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को हराकर अपना दूसरा महिला प्रीमियर लीग (WPL) खिताब जीतते हुए क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- ◆ **लक्ष्य:** दिल्ली कैपिटल्स ने जेमिमा रोड्रिग्स (37 गेंदों में 57 रन) की शानदार अर्द्धशतकीय पारी के दम पर 204 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा।
- ◆ **रिकॉर्ड रन-चेज़:** रॉयल चैलेंजर्स बंगलूरु ने 19.4 ओवरों में 204/4 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया, जो किसी बड़े T20 फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा सफल रन-चेज़ है।
- ◆ **स्टार प्रदर्शन:**
 - **स्मृति मंधाना:** कप्तानी पारी खेलते हुए 41 गेंदों में 87 रन बनाए, जो WPL फाइनल में किसी खिलाड़ी का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है।
 - **जॉर्जिया वॉल:** 54 गेंदों में 79 रन बनाए और मंधाना के साथ दूसरे विकेट के लिये रिकॉर्ड 165 रनों की साझेदारी की।
- ◆ **फ्रैंचाइज़ उपलब्धि:** इस जीत के साथ RCB, मुंबई इंडियंस के बाद दूसरी ऐसी फ्रैंचाइज़ बन गई जिसने दो WPL खिताब (2024 और 2026) जीते हैं।
- ◆ **मुख्य उपलब्धियाँ और पुरस्कार:**
 - **ऑरेंज कैप (सर्वाधिक रन):** स्मृति मंधाना (RCB) — 377 रन।
 - **पर्पल कैप (सर्वाधिक विकेट):** राधा यादव (DC) — 14 विकेट।
 - **सीज़न की उभरती खिलाड़ी:** जॉर्जिया वॉल (RCB)।
- ◆ **महिला खेलों के लिये महत्त्व:** इस तरह की हाई-प्रोफाइल जीतें महिला पेशेवर खेलों के 'सामान्यीकरण' में योगदान देती हैं और 'खेलो इंडिया' पहल के तहत स्थानीय स्तर पर भागीदारी को प्रोत्साहित करती हैं।

अंतरिक्ष-आधारित AI डेटा केंद्रों के लिये चीन की योजना

चर्चा में क्यों ?

चीन ने घोषणा की है कि वह अपनी उन्नत तकनीकी और अंतरिक्ष अवसंरचना रणनीति के तहत आगामी पाँच वर्षों में अंतरिक्ष-आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) डेटा केंद्रों को प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है।

मुख्य बिंदु

- ◆ **एकीकृत संरचना:** यह योजना क्लाउड, एज और टर्मिनल (डिवाइस) क्षमताओं को समेकित करते हुए एक नई अंतरिक्ष संरचना विकसित करने का लक्ष्य रखती है।
- ◆ **औद्योगिक-स्तरीय 'स्पेस क्लाउड':** वर्ष 2030 तक चीन बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा केंद्रों से संचालित कक्षीय 'स्पेस क्लाउड' स्थापित करने का इरादा रखता है, जिससे ऊर्जा-गहन AI प्रोसेसिंग को पृथ्वी से कक्षा में स्थानांतरित किया जा सके।
- ◆ **प्रसंस्करण क्षमता:** यह अवसंरचना कंप्यूटिंग शक्ति, भंडारण क्षमता और संचार बैंडविड्थ के 'गहन एकीकरण' को सक्षम बनाएगी, जिससे पृथ्वी पर उत्पन्न डेटा को सीधे अंतरिक्ष में संसाधित किया जा सकेगा।
- ◆ **घरेलू उपलब्धि:** एक महत्वपूर्ण प्रमाण-कार्य (पूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट) के रूप में, अलीबाबा क्लाउड का Qwen-3 मॉडल हाल ही में एक परीक्षण उपग्रह पर कक्षा में सफलतापूर्वक इन्फरेंस चलाकर विश्व का पहला सामान्य-उद्देश्य AI बनने का कीर्तिमान स्थापित किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ **चीन बनाम स्पेसएक्स:** यह घोषणा चीन को स्पेसएक्स की कक्षीय महत्वाकांक्षाओं का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी बनाती है।
 - स्पेसएक्स ने AI कंपनी xAI के साथ विलय के बाद सौर-ऊर्जा संचालित कक्षीय डेटा केंद्रों और अंतरिक्ष कंप्यूटिंग उपग्रहों की योजनाओं को आगे बढ़ाया है।
- ◆ **संबद्ध चुनौतियाँ:** 'स्पेस क्लाउड' के लिये उपग्रहों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि (संभावित रूप से मिलियन) टकराव के जोखिम को काफी बढ़ा देती है और अंतरिक्ष संचालन प्रबंधन को और जटिल बनाती है।
 - तकनीकी जोखिम: अंतरिक्ष-आधारित हार्डवेयर सौर ज्वालाओं, विकिरण और सूक्ष्म उल्कापिंडों के प्रभावों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है।

वर्ष 2035 तक आंध्र प्रदेश को क्लीन एनर्जी हब बनाएगा नीति आयोग

चर्चा में क्यों ?

नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश को वर्ष 2035 तक भारत के शीर्ष तीन नवीकरणीय ऊर्जा हब में बदलने के उद्देश्य से एक रूपरेखा (ड्राफ्ट ब्लूप्रिंट) का अनावरण किया। इस रणनीति को **ASSET (एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन)** प्लेटफॉर्म के तहत नीति आयोग के CEO बी.वी.आर. सुब्रमण्यम ने राज्य के मुख्य सचिव को प्रस्तुत किया।

मुख्य बिंदु

- ◆ **स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण:** इस रूपरेखा का लक्ष्य वर्ष 2035 तक आंध्र प्रदेश को एक प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक और निर्यातक बनाना है।
 - यह योजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा, कार्बन न्यूनीकरण, आर्थिक विकास और जलवायु कार्रवाई की व्यापक पहल के साथ मेल खाती है और वर्ष 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य का समर्थन करती है।
- ◆ **ऊर्जा सुलभता और दक्षता:** नीति आयोग के अनुमान के अनुसार, पावर खरीद लागत ₹3.90-4 प्रति यूनिट तक घट सकती है, जबकि कुल आपूर्ति लागत ₹6 प्रति यूनिट से नीचे रखी जाएगी।
- ◆ **संप्रेषण आधुनिकीकरण:** ट्रांसमिशन उन्नयन के लिये ₹65,000-70,000 करोड़ का निवेश निर्धारित किया गया है, जिसमें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, GIS सबस्टेशन और HVDC लाइनें शामिल हैं।
- ◆ **ऊर्जा वार रूम:** इन पहलों की प्रगति पर निगरानी के लिये एक समर्पित मॉनिटरिंग सेल स्थापित किया जाएगा।
- ◆ **समयसीमा:** इस रूपरेखा को मार्च 2026 की शुरुआत तक अंतिम रूप देने की उम्मीद है, जबकि इसका कार्यान्वयन उसी माह के मध्य से शुरू होने की संभावना है।

दिल्ली पुलिस ने 'ऑपरेशन शास्त्र' शुरू किया

चर्चा में क्यों ?

दिल्ली पुलिस ने 'ऑपरेशन शास्त्र' शुरू किया है, जो सोशल मीडिया पर बंदूकों और हथियारों के बढ़ते महिमामंडन तथा प्रदर्शन को निशाना बनाने वाला एक बड़ा अभियान है। इसका उद्देश्य गन कल्चर/हथियार संस्कृति पर रोक लगाना और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करना है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- ◆ **उद्देश्य:** यह अभियान ऑनलाइन हथियारों और हिंसक चित्रों को सामान्य बनाने तथा उनका महिमामंडन करने से रोकने पर केंद्रित है, जिनके बारे में पुलिस का मानना है कि वे युवाओं को प्रभावित कर सकते हैं तथा असुरक्षित व्यवहार को बढ़ावा दे सकते हैं।
- ◆ **कार्यान्वयन एजेंसियाँ:** यह पहल दिल्ली पुलिस के नेतृत्व में पुलिस आयुक्त के निर्देशों के तहत तथा साइबर इकाइयों और फील्ड टीमों के समन्वित सहयोग से चलाई जा रही है।
 - ऑपरेशन शास्त्र के तहत अधिकारियों ने हजारों सोशल मीडिया खातों और शॉर्ट-फॉर्म वीडियो की निगरानी की, जहाँ लोग प्रभाव जमाने या रोमांच के लिये बंदूकें, चाकू या अन्य हथियारों का प्रदर्शन करते दिखाई दिये।
- ◆ **तकनीकी दृष्टिकोण:** इस अभियान में सोशल प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सामग्री की डिजिटल स्कैनिंग और व्यावहारिक विश्लेषण को शामिल किया गया, ताकि हथियारों के महिमामंडन को बढ़ावा देने वाली आपत्तिजनक पोस्टों की पहचान की जा सके।
- ◆ **महत्त्व:** ऑपरेशन शास्त्र सार्वजनिक सुरक्षा के लिये उभरते खतरों से निपटने हेतु ऑनलाइन निगरानी और स्थानीय कार्रवाई को जोड़ने वाला आधुनिक पुलिसिंग दृष्टिकोण दर्शाता है।
 - यह अभियान समुदायों को जागरूक करने तथा युवाओं को हथियारों और हिंसा को ग्लैमराइज करने वाली सामग्री बनाने या साझा करने से हतोत्साहित करने का भी प्रयास करता है।

गोवा बना बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा भारतीय राज्य

चर्चा में क्यों ?

गोवा पक्षियों के दस्तावेजीकरण और जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अपना व्यापक राज्य-स्तरीय बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है।

मुख्य बिंदु

- ◆ **राज्य:** गोवा में 'बर्ड एटलस ऑफ गोवा' जारी किया गया, जिससे यह ऐसा करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया।
 - केरल राज्य-स्तरीय बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य था।
- ◆ **लॉन्च:** इस एटलस का विमोचन गोवा के नौवें बर्ड फेस्टिवल के दौरान किया गया, जो जैव विविधता के प्रति जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी पर राज्य के जोर को दर्शाता है।
- ◆ **उद्देश्य:** यह बर्ड एटलस गोवा में पक्षी प्रजातियों और उनके वितरण का व्यवस्थित तथा स्थानिक मानचित्रण प्रदान करता है।
 - इससे दीर्घकालिक पारिस्थितिक निगरानी, वैज्ञानिक अनुसंधान और संरक्षण योजना को समर्थन मिलने की उम्मीद है।
- ◆ **कार्यप्रणाली:** यह एटलस नागरिक विज्ञान (सिटिजन साइंस) के सहयोग से तैयार किया गया, जिसमें पक्षी विज्ञानी, शोधकर्ता, पक्षी प्रेमी तथा स्वयंसेवकों ने फील्ड अवलोकन और डेटा प्रदान किया।
- ◆ **महत्त्व:**
 - यह राज्य स्तर पर पक्षी जैव विविधता से संबंधित आँकड़ों की कमी को पूरा करता है।
 - यह नीति निर्माताओं और संरक्षणकर्ताओं को आवास संरक्षण तथा प्रजाति प्रबंधन के लिये सूचित रणनीतियाँ बनाने में सहायता करेगा।
 - यह परियोजना वन्यजीव संरक्षण में जनभागीदारी को बढ़ावा देती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



VOC पोर्ट एंटी-ड्रोन सुरक्षा तैनात करने वाला भारत का पहला पोर्ट बना

चर्चा में क्यों ?

चिदंबरनार पोर्ट प्राधिकरण (VOC पोर्ट) भारत का पहला बंदरगाह बन गया है जिसने उन्नत एंटी-ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती शुरू की है।

मुख्य बिंदु

- ❖ **प्रणाली:** एंटी-ड्रोन सुरक्षा प्रणाली में रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन और ऑप्टिकल ट्रैकिंग तकनीकों का समेकन किया गया है, ताकि बंदरगाह क्षेत्र के आसपास अनधिकृत ड्रोन गतिविधियों का पता लगाया जा सके, उनकी निगरानी की जा सके तथा उन पर प्रतिक्रिया दी जा सके।
- ⦿ यह कदम तमिलनाडु में चिदंबरनार पोर्ट प्राधिकरण (VOC पोर्ट) द्वारा लागू किया गया है।
- ❖ **उद्देश्य:** इस प्रणाली का लक्ष्य समुद्री अवसंरचना की सुरक्षा को सुदृढ़ करना, महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की रक्षा करना और प्रमुख परिचालन क्षेत्रों में मानव-रहित हवाई प्रणालियों से उत्पन्न संभावित खतरों को रोकना है।
- ⦿ यह पहल बंदरगाह सुरक्षा उपायों में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है और व्यापार मार्गों तथा समुद्री प्रतिष्ठानों को उभरते तकनीकी खतरों से सुरक्षित रखने की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है।
- ❖ **सुरक्षा चिंता:** विश्व स्तर पर वाणिज्यिक ड्रोन के बढ़ते उपयोग ने सुरक्षा एजेंसियों को जासूसी, तस्करी या संवेदनशील अवसंरचना के पास आकस्मिक हवाई क्षेत्र उल्लंघन से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिये काउंटर-ड्रोन प्रणालियाँ अपनाने हेतु प्रेरित किया है।

कोटक बना पूरी तरह से डिजिटल FPI रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक

चर्चा में क्यों ?

कोटक महिंद्रा बैंक भारत का पहला कस्टोडियन बन गया है जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) के पंजीकरण और खाता खोलने की पूरी प्रक्रिया को सुगम बनाया है, जो पूंजी बाजार तक डिजिटल पहुँच में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

मुख्य बिंदु

- ❖ **संस्था:** इस उपलब्धि की घोषणा कोटक महिंद्रा बैंक ने की।
- ⦿ भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक, जब इसकी कस्टडी शाखा ने FPI के लिये पूरी तरह से डिजिटल ऑनबोर्डिंग सक्षम की।
- ❖ **नवाचार:** यह भारत में पहली बार है जब किसी FPI लाइसेंस और उससे जुड़े ग्राहक खाता खोलने से संबंधित दस्तावेज पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों (eSign) के माध्यम से निष्पादित किये गए हैं, बिना भौतिक 'वेट सिग्नेचर' की आवश्यकता के।
- ⦿ यह कदम जनवरी 2026 में SEBI द्वारा शुरू किये गए एकीकृत डिजिटल वर्कफ्लो के बाद उठाया गया है, जो FPI पंजीकरण के लिये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) पोर्टल में डिजिटल हस्ताक्षरों के उपयोग की अनुमति देता है।
- ❖ **उद्देश्य:** इस पहल का उद्देश्य विदेशी निवेशकों के लिये भारतीय बाजार में प्रवेश की प्रक्रिया को सरल एवं तीव्र बनाना है, ताकि कागजी कार्यवाही कम हो, परिचालन जोखिम घटें और ऑनबोर्डिंग अनुभव का आधुनिकीकरण हो सके।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **लाभ:** कागज़-रहित ऑनबोर्डिंग से वैश्विक निवेशकों के लिये समय और लॉजिस्टिक बोझ में उल्लेखनीय कमी आती है।
 - ⦿ यह ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देता है और भारत में अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने की आकांक्षा को समर्थन देता है।
 - ⦿ यह पूंजी बाजारों के लिये भारत की डिजिटल अवसंरचना को मज़बूत करता है।
- ❖ **महत्त्व:** यह विकास वित्तीय बाजारों में डिजिटल रूपांतरण की दिशा में भारत की प्रगति को दर्शाता है और निवेशक पंजीकरण तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु SEBI के व्यापक सुधारों के अनुरूप है।

वॉलमार्ट \$1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुँचने वाला पहला रिटेलर बना

चर्चा में क्यों ?

वॉलमार्ट ने 1 ट्रिलियन डॉलर के बाज़ार मूल्यांकन को पार कर एक ऐतिहासिक वित्तीय उपलब्धि हासिल की है और इस तरह वह प्रमुख वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के वर्चस्व वाले 'ट्रिलियन-डॉलर क्लब' में शामिल होने वाली पहली पारंपरिक रिटेल कंपनी बन गई है।

मुख्य बिंदु

- ❖ **वॉलमार्ट:** यह अमेरिका स्थित एक बहुराष्ट्रीय खुदरा निगम है, जो हाइपरमार्केट, डिस्काउंट डिपार्टमेंट स्टोर्स और किराना आउटलेट्स की अपनी व्यापक शृंखला के लिये जाना जाता है।
- ❖ **ऐतिहासिक उपलब्धि:** वॉलमार्ट का बाज़ार पूंजीकरण पहली बार 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया।
 - ⦿ जिससे वह एनवीडिया, अल्फाबेट (गूगल की मूल कंपनी) और अन्य तकनीकी दिग्गजों जैसी शीर्ष कंपनियों की श्रेणी में शामिल हो गया।
- ❖ **वृद्धि के कारक:**
 - ⦿ इसके ऑनलाइन मार्केटप्लेस और ई-कॉमर्स सेवाओं का विस्तार।
 - ⦿ संचालन में एकीकृत डिजिटल और AIआधारित क्षमताओं से मिला बढ़ावा।
 - ⦿ वॉलमार्ट+ जैसी सब्सक्रिप्शन सेवाओं और तीव्र डिलीवरी विकल्पों को सुदृढ़ करना।
 - ⦿ वॉलमार्ट के विज्ञापन व्यवसाय में वृद्धि और आपूर्ति-शृंखला नवाचार।
- ❖ **महत्त्व:**
 - ⦿ यह खुदरा उद्योग की गतिशीलता में बदलाव को दर्शाता है, जहाँ एक पारंपरिक रिटेलर ने आमतौर पर तकनीक और डिजिटल-केंद्रित कंपनियों के पास रहने वाले स्थान में प्रवेश किया है।
 - ⦿ यह वॉलमार्ट की ओम्नी-चैनल रणनीति और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में नवाचार करने की उसकी क्षमता में निवेशकों के विश्वास का संकेत देता है।

केरल में भारत का पहला 'एल्डरली बजट'

चर्चा में क्यों ?

29 जनवरी 2026 को वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल द्वारा प्रस्तुत केरल राज्य बजट 2026-27 में, वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिये मुख्य बजट के साथ एक विशेष 'एल्डरली बजट' दस्तावेज़ पेश करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- ◆ **एल्डरली बजट के प्रमुख स्तंभ:** राज्य ने वृद्ध आबादी में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव से निपटने के लिये विशेष निधियाँ और नीतिगत ढाँचे निर्धारित किये हैं:
- ◆ **वित्तीय सुरक्षा:** सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर **₹2,000 प्रति माह** किया गया है, जिससे **60 लाख से अधिक लोगों** को लाभ मिलेगा।
 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष पेंशन के लिये कुल आवंटन **₹14,500 करोड़** रखा गया है।
- ◆ **स्वास्थ्य एवं जेरियाट्रिक देखभाल:**
 - **मेनोपॉज़ क्लिनिक:** जिला अस्पतालों में **₹3 करोड़** के प्रारंभिक व्यय के साथ स्थापित किये गए हैं।
 - **'मिसिंग मिडल' के लिये बीमा:** गरीबी रेखा से ऊपर लेकिन मौजूदा योजनाओं के दायरे से बाहर परिवारों को लक्षित करने वाली स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु **₹50 करोड़** का आवंटन।
 - **पैलियेटिव केयर:** सामुदायिक-आधारित पैलियेटिव केयर नेटवर्क के लिये बढ़ी हुई फंडिंग, जो केरल के स्वास्थ्य मॉडल की पहचान है।
- ◆ **आवास एवं अवसंरचना:**
 - **रिटायरमेंट होम:** निजी और सहकारी क्षेत्रों द्वारा आधुनिक रिटायरमेंट होम के निर्माण को सब्सिडी देने के लिये **₹30 करोड़** का आवंटन।
 - **वृद्ध-अनुकूल शहर:** स्थानीय निकायों को पार्कों और पैदल पथों सहित **'एज-फ्रेंडली'** सार्वजनिक अवसंरचना विकसित करने हेतु विशेष अनुदान।
- ◆ **केयर इकोनॉमी:**
 - **ऑन-कॉल स्वयंसेवक सेवाएँ:** अकेले रहने वाले बुजुर्गों को दैनिक कामों और चिकित्सकीय यात्राओं में सहायता देने के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा स्वयंसेवकों के समूह के विकास हेतु **₹10 करोड़**।
 - **वायोमित्रम योजना:** सभी नगरपालिकाओं एवं पंचायत वार्डों तक विस्तार, ताकि घर-घर निशुल्क दवाएँ और जाँच उपलब्ध कराई जा सकें।
- ◆ **महत्त्व:** केरल में बुजुर्ग आबादी भारत में सबसे अधिक है, जिससे **स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और देखभाल प्रणालियों** पर दबाव बढ़ता है।
 - एल्डरली बजट जनसांख्यिकीय वास्तविकता के प्रति एक **सक्रिय नीतिगत प्रतिक्रिया** का प्रतिनिधित्व करता है, न कि केवल प्रतिक्रियात्मक कल्याण व्यय का।

एयरबस-GSV सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

चर्चा में क्यों ?

वैश्विक एयरोस्पेस अग्रणी **एयरबस** ने गुजरात के वडोदरा स्थित **गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV)** में एक अत्याधुनिक **'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' (CoE)** का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु

- ◆ **सहयोग:** एयरबस और GSV के बीच यह सहयोग भारत के एयरोस्पेस अनुसंधान इकोसिस्टम को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है, विशेष रूप से **सतत विमानन प्रौद्योगिकियों** में तथा इस क्षेत्र में **उद्योग-शिक्षा सहभागिता** को और गहरा करने का उद्देश्य रखता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ **CoE के उद्देश्य:** विमानन क्षेत्र के डी-कार्बोनाइजेशन पर केंद्रित अनुसंधान, जिसमें सतत विमानन ईंधन (SAF) और हाइड्रोजन-आधारित प्रणोदन प्रणालियाँ शामिल हैं।
- **कौशल विकास:** भारतीय एयरोस्पेस इकोसिस्टम के लिये एक विशेषीकृत कार्यबल तैयार करना, विशेष रूप से विमानन संचालन, रखरखाव और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों को लक्षित करते हुए।
- ◆ **अनुसंधान एवं नवाचार:** वास्तविक विश्व की एयरोस्पेस चुनौतियों के समाधान हेतु उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोगात्मक परियोजनाओं को आगे बढ़ाना।
- ◆ **गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV):** भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय।
- **स्थान:** वडोदरा में स्थित यह विश्वविद्यालय पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के लिये प्रमुख शैक्षणिक प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
- ◆ **महत्त्व:** यह CoE वडोदरा में स्थित C-295 विमान निर्माण सुविधा (टाटा-एयरबस सहयोग) को पूरक बनाता है और घरेलू आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ करता है।

जर्मनी में BIOFACH 2026 में भारत को 'कंट्री ऑफ द ईयर' चुना गया

चर्चा में क्यों?

भारत को फरवरी 2026 में जर्मनी के नूर्नबर्ग में आयोजित होने वाले जैविक उत्पादों के विश्व के अग्रणी व्यापार मेले BIOFACH 2026 में 'कंट्री ऑफ द ईयर' (Country of the Year) का प्रतिष्ठित खिताब प्रदान किया गया है।

मुख्य बिंदु

- ◆ **कार्यक्रम:** BIOFACH 2026 जर्मनी में आयोजित होने वाला जैविक उत्पादों का विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है।
- भारत को वैश्विक मंच पर अपनी जैविक कृषि की ताकत और निर्यात क्षमता को मान्यता देते हुए आधिकारिक रूप से 'कंट्री ऑफ द ईयर' घोषित किया गया है।
- ◆ **आयोजन प्राधिकरण:** भारत की भागीदारी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) द्वारा आयोजित की जा रही है।
- **पैन-इंडिया प्रतिनिधित्व:** 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रदर्शक भाग ले रहे हैं, जो भारत की कृषि तथा क्षेत्रीय विविधता को प्रदर्शित करते हैं।
- **उत्पाद:** यहाँ चावल, तिलहन, दलहन, मसाले, जड़ी-बूटियाँ, काजू, अदरक, हल्दी, बड़ी इलायची, दालचीनी, आम प्युरी, आवश्यक तेल तथा अन्य मूल्यवर्द्धित जैविक उत्पादों की विस्तृत शृंखला प्रदर्शित की जा रही है।
- ◆ **निर्यात प्रोत्साहन:** यह आयोजन भारतीय जैविक निर्यातकों को वैश्विक खरीदारों से जुड़ने, बाजार तक पहुँच बढ़ाने और वैश्विक जैविक बाजार में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है।
- ◆ **महत्त्व:** BIOFACH में 'कंट्री ऑफ द ईयर' के रूप में भारत की पहचान उसकी जैविक कृषि में नेतृत्व भूमिका, बढ़ते निर्यात प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संधारणीय कृषि पद्धतियों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



विशाखापत्तनम में ऐतिहासिक समुद्री संगम

चर्चा में क्यों ?

पहली बार भारत एक साथ तीन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री आयोजनों—अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा (**International Fleet Review-IFR**) 2026, अभ्यास मिलन 2026 और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (**IONS**) के नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।

मुख्य बिंदु

- ◆ **स्थल:** विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश — भारत की पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय और एक रणनीतिक समुद्री प्रवेश द्वार।
- ◆ **मुख्य आयोजन:** यह पहली बार होगा जब भारत इन तीनों प्रमुख समुद्री आयोजनों की मेज़बानी एक साथ कर रहा है।
- ◆ **IFR 2026:** 18 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू युद्धपोतों के एक विशाल बेड़े की समीक्षा करेंगी, जिसमें INS विक्रांत जैसे पोतों के साथ भारत की 'बिल्डर नेवी' को प्रदर्शित किया जाएगा।
- ◆ **अभ्यास मिलन 2026:** मिलन भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें पेशेवर आदान-प्रदान, सामरिक अभ्यास और संयुक्त समुद्री अभियानों को शामिल किया जाता है।
- ◆ **IONS सम्मेलन:** भारत वर्ष 2025–2027 की अवधि के लिये अध्यक्षता संभाल रहा है और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिये 25 से अधिक देशों की मेज़बानी कर रहा है।
- ◆ **भागीदारी:** 50-70 से अधिक देशों के युद्धपोतों और विमानों के भाग लेने की उम्मीद है, जो प्रमुख समुद्री शक्तियों तथा क्षेत्रीय साझेदारों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- ◆ **वैश्विक उपस्थिति:** संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, श्रीलंका, ईरान, यूनाइटेड किंगडम, यूएई, दक्षिण अफ्रीका सहित कई देश इसमें भाग लेंगे, जो व्यापक कूटनीतिक सहभागिता को दर्शाता है।

IIT मद्रास ने डीप-टेक स्टार्टअप्स के लिये ₹600 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड बनाया

चर्चा में क्यों ?

IIT मद्रास रिसर्च पार्क ने भारत के डीप-टेक इकोसिस्टम में प्रारंभिक चरण और प्रौद्योगिकी-गहन स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ₹600 करोड़ का डीप-टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है।

मुख्य बिंदु

- ◆ **फंड:**
 - IIT मद्रास रिसर्च पार्क (IITMRP) ने यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स के सहयोग से ₹600 करोड़ के डीप-टेक वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की घोषणा की है, जिसका नाम **IITM यूनिकॉर्न फ्रंटियर फंड I** रखा गया है।
 - इस फंड में अतिरिक्त ₹400 करोड़ का 'ग्रीनशू विकल्प' भी शामिल है, जिससे डीप-टेक स्टार्टअप्स में निवेश हेतु इसकी संभावित कुल निवेश क्षमता ₹1,000 करोड़ तक पहुँच सकती है।
 - यह फंड प्रारंभिक चरण की डीप-टेक कंपनियों को लक्षित करता है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर, रक्षा प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स और उन्नत अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **रणनीतिक दृष्टि:** यह पहल प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता पर बल देती है, ताकि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी समाधान विकसित करने वाले भारतीय उपक्रमों को समर्थन देकर आयातित प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम की जा सके।
- ❖ **नवाचार समर्थन:** यह फंड 'धैर्यशील पूंजी' (Patient Capital) उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखता है, क्योंकि डीप-टेक स्टार्टअप्स को गहन अनुसंधान एवं विकास (R&D), प्रोटोटाइप निर्माण और नियामकीय चुनौतियों के कारण प्रायः अधिक समय की आवश्यकता होती है।
- ❖ **प्रभाव:** इस पहल से बौद्धिक संपदा-आधारित उपक्रमों की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और अनुसंधान संस्थानों तथा उद्योग के बीच सहयोग को सुदृढ़ करते हुए भारत के डीप-टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती मिलने की अपेक्षा है।
- ❖ **IITMRP:**
 - ⦿ यह भारत के प्रमुख विश्वविद्यालय-आधारित अनुसंधान पार्कों में से एक है, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट करना और अपनी परिसंपत्ति में अनुसंधान एवं विकास इकाइयों को स्थान प्रदान कर अकादमिक जगत तथा उद्योग के बीच के अंतर को कम करना है।

गुजरात ने हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिये स्टारलिनक के साथ LoI एक्सचेंज किया

चर्चा में क्यों ?

गुजरात सरकार ने पूरे राज्य में उच्च-गति सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी के विस्तार के लिये एलन मस्क की स्पेसएक्स की सहायक कंपनी स्टारलिनक के साथ एक आशय पत्र (Letter of Intent - LoI) पर हस्ताक्षर किये हैं।

मुख्य बिंदु

- ❖ **हस्ताक्षरकर्ता:** यह दस्तावेज़ गांधीनगर में राज्य उद्योग आयुक्त पी. स्वरूप और स्टारलिनक इंडिया के प्रमुख प्रभाकर जयकुमार के बीच आदान-प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी उपस्थित थे।
- ❖ **लक्षित क्षेत्र:** यह पहल विशेष रूप से दूरस्थ, सीमावर्ती, जनजातीय और वंचित क्षेत्रों पर केंद्रित है, जहाँ पारंपरिक दूरसंचार अवसंरचना या तो अपर्याप्त है अथवा स्थापित करना चुनौतीपूर्ण है।
- ❖ **प्राथमिकता वाले जिले:** नर्मदा और दाहोद जैसे 'आकांक्षी जिलों' पर विशेष जोर दिया गया है।
- ❖ **पायलट परियोजना का दायरा:** प्रारंभिक चरण में निम्नलिखित प्रमुख सार्वजनिक अवसंरचनाओं को जोड़ने का लक्ष्य है—
 - ⦿ शिक्षा: स्मार्ट कक्षाओं हेतु राज्य विद्यालय।
 - ⦿ स्वास्थ्य: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHCs) और टेलीमेडिसिन सेवाएँ।
 - ⦿ सुरक्षा: तटीय पुलिस चौकियाँ और राजमार्ग सुरक्षा प्रणाली।
 - ⦿ लोक सेवाएँ: कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) और ई-गवर्नेंस केंद्र।
 - ⦿ लॉजिस्टिक्स एवं पर्यावरण: बंदरगाह, GIDC औद्योगिक पार्क और वन्यजीव अभयारण्य।
- ❖ **संयुक्त कार्यदल:** पायलट आकलन की निगरानी एवं क्रियान्वयन के समन्वय हेतु गुजरात सरकार और स्टारलिनक के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त कार्यदल गठित किया जाएगा।
- ❖ **नियामकीय स्थिति:** यद्यपि स्टारलिनक को आशय पत्र (LoI) जारी किया गया है, किंतु अंतिम वाणिज्यिक शुरुआत भारत की केंद्रीय प्राधिकरणों (दूरसंचार विभाग/IN-SPACe) से लाइसेंस और सुरक्षा संबंधी स्वीकृतियों के अधीन होगी।
- ❖ **महत्त्व:** यह रणनीतिक पहल गुजरात के डिजिटल कनेक्टिविटी मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में डिजिटल अंतर को पाटना है जहाँ भौगोलिक या लागत संबंधी कारणों से स्थलीय दूरसंचार नेटवर्क कमजोर या अव्यवहार्य हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



भारत लगाएगा लद्दाख में दो नए टेलीस्कोप

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत सरकार ने लद्दाख में अपनी भू-आधारित खगोल विज्ञान अवसंरचना के व्यापक विस्तार को स्वीकृति दी है, जिसमें दो नए मेगा-टेलीस्कोप की स्थापना तथा एक मौजूदा सुविधा के उन्नयन को शामिल किया गया है।

मुख्य बिंदु

- ◆ नई टेलीस्कोप परियोजनाएँ: नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप और नेशनल लार्ज ऑप्टिकल-नियर इन्फ्रारेड टेलीस्कोप की स्थापना।
- ◆ नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप (NLST): सूर्य की सतह और वायुमंडल का उच्च-रिज़ॉल्यूशन में अवलोकन करने हेतु।
 - स्थान: पैंगोंग त्सो झील के निकट, लद्दाख।
 - वैज्ञानिक फोकस: सौर चुंबकीय क्षेत्र, सौर ज्वालान (फ्लेयर), कोरोनल मास इजेक्शन तथा अंतरिक्ष मौसम संबंधी घटनाएँ।
- ◆ महत्त्व: पूर्ण होने पर NLST भारत की तीसरी भू-आधारित सौर वेधशाला होगी। यह तमिलनाडु स्थित कोडाइकनाल सौर वेधशाला और राजस्थान स्थित उदयपुर सौर वेधशाला जैसी मौजूदा सुविधाओं का पूरक बनेगी तथा भारत की आदित्य-L1 अंतरिक्ष वेधशाला से प्राप्त आँकड़ों को भी सुदृढ़ करेगी।
- ◆ नेशनल लार्ज ऑप्टिकल-नियर इन्फ्रारेड टेलीस्कोप (NLOT): गहन अंतरिक्ष अनुसंधान के लिये एक उन्नत ऑप्टिकल और निकट-अवरक्त टेलीस्कोप।
 - वैज्ञानिक अनुप्रयोग: एक्सोप्लैनेट, तारकीय और आकाशगंगीय विकास, ब्रह्मांड विज्ञान, सुपरनोवा तथा दूरस्थ आकाशगंगाओं का अध्ययन।
- ◆ महत्त्व: अपने बड़े संग्रहण क्षेत्र और उच्च ऊँचाई वाले स्थान के कारण NLOT गहन अंतरिक्ष अवलोकन के लिये क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली ऑप्टिकल टेलीस्कोप में से एक होगा।
- ◆ हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप (HCT) का उन्नयन: HCT को 3.7 मीटर के खंडित प्राथमिक दर्पण वाले टेलीस्कोप में उन्नत किया जाएगा, जिससे इसकी संवेदनशीलता और ऑप्टिकल-अवरक्त तरंगदैर्घ्य क्षेत्र में कवरेज में सुधार होगा।
 - वैज्ञानिक प्रभाव: उन्नत HCT गहन अवलोकन को संभव बनाएगा तथा अंतर्राष्ट्रीय वेधशालाओं और इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित नए टेलीस्कोप का पूरक बनेगा।
- ◆ लद्दाख क्यों ? : उच्च ऊँचाई, स्वच्छ और शुष्क आकाश तथा कम वायुमंडलीय विक्षोभ के कारण लद्दाख को खगोलीय अवलोकन के लिये एक आदर्श स्थल के रूप में पहचाना गया है। यहाँ पहले से ही कई महत्वपूर्ण ऑप्टिकल और उच्च-ऊर्जा खगोल विज्ञान सुविधाएँ स्थापित हैं।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 'पढ़ाई विद AI' ऐप लॉन्च किया

चर्चा में क्यों ?

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिले में 'पढ़ाई विद AI' नामक डिजिटल शिक्षा पहल की शुरुआत की।

मुख्य बिंदु

- ◆ उद्देश्य: इस पहल का उद्देश्य पूर्णतः डिजिटल शिक्षण वातावरण प्रदान करना है, जिसमें निरंतर शैक्षणिक परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री और मार्गदर्शन सुनिश्चित हो सके।
 - यह पहल विशेष रूप से उन छात्रों के लिये तैयार की गई है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें प्रौद्योगिकी-समर्थित शिक्षण सहयोग की आवश्यकता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ **विज्ञान:** मुख्यमंत्री ने इस तर्क पर जोर दिया कि शिक्षा एक परिवर्तनकारी शक्ति है, जो सोच का विस्तार करती है और समाज के भविष्य का निर्माण करती है। राज्य सरकार नवाचार और समान अवसरों के माध्यम से शिक्षा को सशक्त बनाने के लिये प्रतिबद्ध है।
 - इस पहल को NTPC का सहयोग प्राप्त है, जो इस मंच के माध्यम से छात्रों को आधुनिक, प्रौद्योगिकी-आधारित और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने में सहायता कर रहा है।
- ◆ **समान पहुँच:** यह मंच AI-आधारित प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए छात्रों की भौगोलिक या सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किये बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिये बनाया गया है।
- ◆ **महत्त्व:** यह पहल सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एकीकरण की दिशा में राज्य सरकार के व्यापक प्रयासों को दर्शाती है।
 - इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों के छात्रों के बीच शैक्षणिक असमानताओं को दूर करना और सीखने के परिणामों में सुधार करना है।

नेशनल क्वांटम मिशन के तहत अमरावती क्वांटम वैली लॉन्च की गई

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के महत्वाकांक्षी नेशनल क्वांटम मिशन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के अमरावती में अमरावती क्वांटम सेंटर की आधारशिला रखी।

मुख्य बिंदु

- ◆ **नेशनल क्वांटम मिशन:** भारत के नेशनल क्वांटम मिशन के लिये लगभग ₹6,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है और यह 17 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित 43 संस्थानों को सम्मिलित करता है।
 - इसे चार प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत संगठित किया गया है: क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग एवं मेट्रोलॉजी और क्वांटम सामग्री व उपकरण।
- ◆ **नोडल मंत्रालय:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
- ◆ **विज्ञान:** विभिन्न प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म (सुपरकंडक्टिंग और फोटोनिक) का उपयोग करते हुए 50-1,000 भौतिक क्यूबिट की श्रेणी में मध्यम-स्तरीय क्वांटम कंप्यूटरों का विकास।
 - उद्देश्य: उपग्रह-आधारित सुरक्षित क्वांटम संचार और भू-आधारित क्वांटम नेटवर्क की स्थापना करना।
 - अनुप्रयोग: रक्षा एवं अंतरिक्ष क्षेत्रों में उच्च-सटीकता समय-निर्धारण, नेविगेशन, इमेजिंग और डिटेक्शन करना।
- ◆ **अमरावती क्वांटम वैली:** इसे एक समर्पित क्वांटम नवाचार क्लस्टर के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसमें अनुसंधान संस्थान, उद्योग, स्टार्टअप और प्रतिभा विकास पारितंत्र का एकीकरण किया जाएगा।
 - क्वांटम क्लाउड एक्सेस और नवाचार केंद्रों के लिये IBM तथा भारतीय IT कंपनी TCS जैसी वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ सहयोग करना।
- ◆ **रणनीतिक महत्त्व:** क्वांटम प्रौद्योगिकी को वैश्विक स्तर पर क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (CET) माना जाता है, जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा और एन्क्रिप्शन प्रणालियों पर गहरा प्रभाव है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



दिल्ली ने 'लखपति बिटिया योजना' शुरू की

चर्चा में क्यों ?

दिल्ली सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लखपति बिटिया योजना नामक एक नई सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है, जिसके तहत जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक संरचित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

मुख्य बिंदु

- ♦ **लॉन्च:** लखपति बिटिया योजना की घोषणा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा की गई है और यह 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगी।
 - यह योजना वर्ष 2008 में शुरू की गई पुरानी 'लाड़ली योजना' का स्थान लेगी और उसे उन्नत रूप में लागू करेगी, जिसे क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।
- ♦ **उद्देश्य:** इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की समस्या को रोकना तथा उनकी शैक्षिक निरंतरता, वित्तीय सुरक्षा और सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है।
 - यह आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की बालिकाओं को शिक्षा के प्रमुख चरणों पर चरणबद्ध बैंक जमा के माध्यम से सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।
- ♦ **वित्तीय संरचना:** इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता को प्रमुख शैक्षिक चरणों से जोड़कर किस्तों में जमा किया जाएगा — जन्म से लेकर स्नातक या डिप्लोमा पाठ्यक्रम तक।
 - जमा की गई कुल राशि पर ब्याज अर्जित होगा और परिपक्वता पर लाभार्थी के बैंक खाते में यह राशि ₹1 लाख से अधिक हो जाने के लिये डिज़ाइन की गई है।
 - जो बालिकाएँ पूर्व 'लाड़ली योजना' की लाभार्थी हैं, उन्हें उनके अधिकार मिलते रहेंगे, जबकि नए लाभार्थियों को संशोधित लखपति बिटिया योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा।
- ♦ **पात्रता मानदंड:** योजना का लाभ पाने के लिये बालिका का जन्म दिल्ली में होना चाहिये और उसके परिवार का कम से कम तीन वर्ष से दिल्ली में निवास होना आवश्यक है, जिसकी वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक न हो।
 - प्रति परिवार अधिकतम दो बालिकाएँ इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगी।
- ♦ **प्रत्यक्ष अंतरण:** भुगतान पूरी तरह डिजिटल आवेदन और वितरण प्रक्रिया के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंकड बैंक खाते में जमा किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता तथा सुगमता सुनिश्चित होगी।

विश्व रेडियो दिवस 2026

चर्चा में क्यों ?

विश्व रेडियो दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जिसे प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रेडियो को संचार का एक सशक्त माध्यम, सूचना तक पहुँच का महत्वपूर्ण साधन और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने वाले माध्यम के रूप में मान्यता देना है।

मुख्य बिंदु

- ♦ **आधिकारिक थीम:** "रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता: AI एक उपकरण है, आवाज़ नहीं (Radio and Artificial Intelligence: AI is a tool, not a voice)।"

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ **शीम का उद्देश्य:** 'रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता' विषय इस बात का अन्वेषण करता है कि उभरती प्रौद्योगिकियाँ प्रसारकों का समर्थन कैसे कर सकती हैं, बिना उन्हें प्रतिस्थापित किये।
- ◆ **मान्यता:** यह वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना का सम्मान करता है और समावेशी समाजों के निर्माण तथा पूरे विश्व में विविध श्रोताओं तक पहुँचने में रेडियो की भूमिका को स्वीकार करता है।
- ◆ **स्वीकृति:** इस दिवस की घोषणा वर्ष 2011 में UNESCO द्वारा की गई थी और बाद में वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अपनाया गया।
- ◆ **विश्व रेडियो दिवस कॉन्क्लेव 2026:** आकाशवाणी रायपुर (छत्तीसगढ़) ने UNESCO के सहयोग से छत्तीसगढ़ में एक प्रमुख कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसमें मानव-केंद्रित संचार के संरक्षण में AI की भूमिका पर विचार-विमर्श किया गया।
- ◆ **महत्त्व:** विश्व रेडियो दिवस तेजी से बदलते मीडिया परिवेश में रेडियो की स्थायी प्रासंगिकता का उत्सव मनाता है।

हिमाचल प्रदेश में देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन

चर्चा में क्यों ?

पहाड़ी पर्यटन और पुष्पोत्पादन को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए, CSIR-हिमालयी जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान (IHBT) ने काँगड़ा ज़िले के पालमपुर में स्थित अपना ट्यूलिप गार्डन आधिकारिक रूप से आम जनता के लिये खोल दिया है।

मुख्य बिंदु

- ◆ **दूसरा ट्यूलिप गार्डन:** यह देश का दूसरा प्रमुख ट्यूलिप गार्डन है, जो श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के बाद आता है, जो एशिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है।
- ◆ **रणनीतिक स्थान:** लगभग 1,290 मीटर की ऊँचाई पर स्थित यह उद्यान धौलाधार पर्वतमाला की विशिष्ट कृषि-जलवायु परिस्थितियों का लाभ उठाता है।
- ◆ **विविधता और विस्तार:** उद्यान में 50,000 से अधिक ट्यूलिप हैं, जो लाल, पीले, गुलाबी और सफेद सहित कई किस्मों तथा रंगों में हैं।
- ◆ **अनुसंधान एकीकरण:** यह केवल एक वाणिज्यिक उद्यान नहीं है, बल्कि CSIR-IHBT, पालमपुर द्वारा प्रबंधित एक अनुसंधान-सह-प्रदर्शन प्लॉट है।
 - यह स्वदेशी बल्ब उत्पादन के परीक्षण का केंद्र है, जिससे नीदरलैंड से आयात पर भारत की निर्भरता कम करने में सहायता मिलती है।
- ◆ **पुष्पोत्पादन को बढ़ावा:** यह उद्यान स्थानीय किसानों के लिये एक 'तकनीकी केंद्र' के रूप में कार्य करता है और हिमाचल प्रदेश में ट्यूलिप की कृषि को एक उच्च-मूल्य नकदी फसल के रूप में उसकी व्यावसायिक व्यवहार्यता प्रदर्शित करता है।
- ◆ **पर्यटन परिपथ:** यह उद्यान काँगड़ा पर्यटन परिपथ में एक नया आयाम जोड़ता है और 'शोलडर सीज़न' (देर शीतकाल/प्रारंभिक वसंत) के दौरान पर्यटकों को आकर्षित करता है, जब पारंपरिक हिम-पर्यटन धीरे-धीरे कम होने लगता है।
- ◆ **जैव-विविधता संरक्षण:** संस्थान इस मंच का उपयोग आगंतुकों को हिमालयी पुष्प विविधता के महत्त्व के बारे में जागरूक करने के लिये करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



लिम्फैटिक फाइलेरिया के उन्मूलन हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने भारत के 12 स्थानिक राज्यों में लिम्फैटिक फाइलेरिया (LF) के उन्मूलन हेतु वार्षिक राष्ट्रव्यापी सामूहिक औषधि वितरण (MDA) अभियान की शुरुआत की।

मुख्य बिंदु

- ❖ सामूहिक औषधि वितरण (MDA) अभियान: लिम्फैटिक फाइलेरियासिस (LF) के संचरण को रोकने और इसे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के उद्देश्य से।
- ❖ रणनीति: गर्भवती महिलाओं, निर्धारित आयु से कम बच्चों और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़ते हुए, शेष सभी पात्र लोगों को प्रतिवर्ष एंटी-फाइलेरियल दवाएँ दी जाती हैं।
- ❖ प्रयुक्त दवाएँ: सामान्यतः डायडथाइलकार्बामाज़ीन (DEC), एल्बेंडाज़ोल तथा चयनित ज़िलों में आइवरमेक्टिन (त्रि-दवा उपचार – IDA) का उपयोग किया जाता है।
- ❖ लक्षित राज्य: यह अभियान 12 स्थानिक राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लागू किया जा रहा है।
- ❖ लिम्फैटिक फाइलेरियासिस (LF):
 - ⦿ यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTD) है, जो परजीवी कृमियों (Wuchereria bancrofti, Brugia malayi) के कारण होता है।
 - ⦿ इसका संचरण संक्रमित मच्छरों के काटने से होता है।
 - ⦿ दीर्घकालिक संक्रमण से हाथीपाँव (Elephantiasis), हाइड्रोसील और दीर्घकालिक दिव्यांगता जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं।
 - ⦿ LF के वैश्विक बोझ का एक बड़ा हिस्सा भारत में पाया जाता है।
- ❖ समय से पहले लक्ष्य: भारत का वर्ष 2027 का लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य (SDG 3) को निर्धारित समय से पहले प्राप्त करने के प्रति देश के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है।

निवेदिता दुबे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की पहली महिला सदस्य बनीं

चर्चा में क्यों ?

निवेदिता दुबे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। यह नियुक्ति भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र में नेतृत्व और लैंगिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

मुख्य बिंदु

- ❖ ऐतिहासिक नियुक्ति: निवेदिता दुबे ने सदस्य (मानव संसाधन) के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) बोर्ड में दूसरा सबसे बड़ा पद है। इसके साथ ही वह AAI के बोर्ड में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं।
- ❖ संगठन: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) एक वैधानिक निकाय है, जो भारत में नागरिक उड्डयन अवसंरचना के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन के लिये उत्तरदायी है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ **पृष्ठभूमि:** उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1995 में AAI में प्रबंधन प्रशिक्षु (Management Trainee) के रूप में की थी।
- वर्षों के दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में एयरपोर्ट मैनेजर सहित विभिन्न भूमिकाएँ निभाई और क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक (पूर्वी क्षेत्र) के रूप में भी सेवा दी।
- ◆ **भूमिका एवं दायित्व:** AAI बोर्ड में सदस्य (मानव संसाधन) के रूप में वह नीति निर्माण, कार्मिक प्रबंधन, औद्योगिक संबंधों और संगठन के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
- ◆ **महत्त्व:** उनकी नियुक्ति को भारत में महिलाओं और युवाओं के लिये एक प्रेरणादायक उपलब्धि के रूप में व्यापक रूप से सराहा जा रहा है, विशेष रूप से विमानन क्षेत्र में, जहाँ ऐतिहासिक रूप से वरिष्ठ शासन स्तरों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व सीमित रहा है।

भारत पहली BRICS शेरपा बैठक 2026 की मेज़बानी करेगा

चर्चा में क्यों ?

भारत ने BRICS समूह की 2026 अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली में पहली BRICS शेरपा और सू-शेरपा बैठक की मेज़बानी की।

मुख्य बिंदु

- ◆ **अध्यक्षता एवं प्रतिनिधि:** बैठक की अध्यक्षता भारत के BRICS शेरपा और सचिव (आर्थिक संबंध) सुधाकर दलेला ने की, जबकि शंभू एल. हक्की, भारत के BRICS सू-शेरपा भी इसमें शामिल रहे।
- ◆ **प्रतिभागी:** ब्राज़ील, चीन, मिस्त्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित BRICS के सदस्य व साझेदार देशों के वरिष्ठ अधिकारी तथा शेरपा चर्चा में सम्मिलित हुए।
- ◆ **थीम:** प्राथमिकताओं को “अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिये निर्माण (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability)” थीम के तहत प्रस्तुत किया गया, जो BRICS नेतृत्व के प्रति भारत के जन-केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- ◆ **फोकस:** स्वास्थ्य, कृषि, श्रम, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, नवाचार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), सुरक्षा तथा आर्थिक और वित्तीय क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया गया।
- ◆ **महत्त्व:** इस बैठक ने आगामी BRICS शिखर सम्मेलन से पहले सहयोग, अनुकूलन, नवाचार और सततता को बढ़ावा देकर भारत के 2026 BRICS एजेंडा की आधारशिला रखी।

नई दिल्ली में सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2026 में नई दिल्ली में सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया, जो देश के केंद्रीय प्रशासनिक बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

मुख्य बिंदु

- ◆ **उद्घाटन:** सेवा तीर्थ का उद्घाटन प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के नए परिसर के रूप में किया गया है, जो सेवा-उन्मुख शासन की दिशा में एक परिवर्तन का प्रतीक है।
- **कर्तव्य भवन** में प्रमुख केंद्रीय मंत्रालय स्थित हैं ताकि समन्वय और प्रशासनिक दक्षता में सुधार हो सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ स्थानांतरण: प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक से सेवा तीर्थ में स्थानांतरित किया गया है।
 - ये इमारतें सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य भारत के प्रशासनिक बुनियादी ढाँचे का पूर्ण आधुनिकीकरण करना है।
- ◆ प्रासंगिकता और विशेषताएँ: नए परिसर ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण के अनुकूल हैं, जिनमें हरित भवन मानकों और आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं का समावेश है।
 - इनकी डिजाइन पारदर्शिता, सुलभता और निर्बाध सार्वजनिक संपर्क को बढ़ावा देती है।
- ◆ औपनिवेशिक विरासत से प्रतीकात्मक परिवर्तन: यह कदम औपनिवेशिक काल की प्रशासनिक इमारतों से आधुनिक, भारत-केंद्रित शासन स्थलों की ओर संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है, जो 'विकसित भारत' की परिकल्पना के अनुरूप है।

केरल में स्त्री सुरक्षा योजना

चर्चा में क्यों ?

केरल सरकार ने राज्य में बेरोज़गार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है।

मुख्य बिंदु

- ◆ योजना: स्त्री सुरक्षा योजना एक राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पहल है जिसे आर्थिक रूप से कमज़ोर, बेरोज़गार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये डिजाइन किया गया है।
 - पात्र लाभार्थियों को राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रणाली के माध्यम से उनके बैंक खातों में प्रति माह 1,000 रुपये की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।
- ◆ लक्षित समूह: यह योजना मुख्य रूप से उन गृहिणियों और बेरोज़गार महिलाओं को लाभ पहुँचाती है जो किसी भी मौजूदा सामाजिक कल्याण पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आती हैं।
- ◆ पात्रता:
 - केरल का स्थायी निवासी होना अनिवार्य।
 - आयु 35-60 वर्ष।
 - बेरोज़गार हों।
 - अंत्योदय अन्न योजना (पीला कार्ड) या प्राथमिकता वाले परिवार (गुलाबी कार्ड) राशन कार्ड श्रेणी से संबंधित हों।
 - अन्य कल्याणकारी पेंशन योजनाओं का लाभार्थी नहीं हों।
- ◆ आवेदन प्रक्रिया: स्थानीय स्वशासन संस्थानों (पंचायत, नगरपालिका, निगम) के माध्यम से आवेदन जमा किये जाते हैं और स्थानीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाता है।
- ◆ हस्तांतरण की विधि: प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से वित्तीय सहायता वितरित की जाती है, ताकि पारदर्शिता और समय पर वितरण सुनिश्चित हो सके।
 - यह योजना केरल सरकार द्वारा अपनी सामाजिक सुरक्षा और लैंगिक कल्याण पहलों के हिस्से के रूप में वित्त पोषित है।
- ◆ ट्रांसजेंडरों का समावेश: उनका समावेश सामाजिक न्याय और समावेशी कल्याणकारी नीतियों के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
कलासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ सत्यापन और नियंत्रण: लाभार्थियों की सूचियों का स्थानीय निकाय स्तर पर सत्यापन किया जाता है ताकि दोहराव रोका जा सके और केवल पात्र आवेदकों को ही लाभ मिले।
- ❖ महत्त्व: यह योजना केरल के सामाजिक सुरक्षा ढाँचे को मजबूत करती है, महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देती है और लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए विकास में योगदान देती है।

PNB सोल्जरथॉन 2026

चर्चा में क्यों ?

पंजाब नेशनल बैंक ने अपने 132वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले समारोहों के तहत राष्ट्रव्यापी मैराथन आयोजन, PNB सोल्जरथॉन 2026 की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु

- ❖ आयोजन: PNB सोल्जरथॉन 2026 बैंक के प्रमुख मैराथन आयोजन का दूसरा संस्करण है, जिसका उद्देश्य फिटनेस, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव को प्रोत्साहित करना है।
 - ⦿ PNB सोल्जरथॉन 2026 मैराथन अप्रैल 2026 में प्रस्तावित है।
- ❖ आयोजक: इस कार्यक्रम की घोषणा पंजाब नेशनल बैंक ने नई दिल्ली के द्वारका स्थित अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में की है।
- ❖ थीम: Run with Soldiers, Run for Soldiers अर्थात "सैनिकों के साथ दौड़ें, सैनिकों के लिये दौड़ें"।
- ❖ स्थापना दिवस: यह घोषणा PNB के 132वें स्थापना दिवस समारोहों की शुरुआत का प्रतीक है, जो बैंक की विरासत और सामाजिक सहभागिता की भूमिका को दर्शाती है।
- ❖ उद्देश्य: इस मैराथन का उद्देश्य फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना तथा नागरिक-सैन्य संपर्क को प्रोत्साहित करना है, जिसमें सैनिकों, पूर्व सैनिकों, युवाओं और आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
 - ⦿ खेलकूद में भागीदारी को देशभक्ति के प्रतीकों के साथ जोड़कर, सोल्जरथॉन PNB के सामुदायिक सहभागिता, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र निर्माण के व्यापक मिशन को सुदृढ़ करता है।

भारत-थाईलैंड संयुक्त इन-सिटू एयर एक्सरसाइज़

चर्चा में क्यों ?

भारतीय वायु सेना और रॉयल थाई वायु सेना दोनों के बीच परिचालन समन्वय और अंतरसंचालनीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक संयुक्त इन-सिटू एयर एक्सरसाइज़ आयोजित की जा रही है।

मुख्य बिंदु

- ❖ अभ्यास: इन-सिटू एयर एक्सरसाइज़ से तात्पर्य वास्तविक उड़ान और युद्ध-संबंधी परिस्थितियों में आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण अभियान से है।
 - ⦿ यह एक्सरसाइज़ बलों को पृथक सिमुलेशन के स्थान पर परिचालन परिवेश के निकट एकीकृत रूप से कार्य करने का अवसर प्रदान करती है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ **प्रमुख विमान और प्लेटफॉर्म:** भारत ने अपनी कई अग्रिम पंक्ति के विमान और प्लेटफॉर्म को तैनात किया है, जिनमें **Su-30MKI** लड़ाकू विमान, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (**AWACS**), एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (**AEW&C**) प्लेटफॉर्म तथा **IL-78** मध्य-वायु ईंधन भरने वाले विमान सम्मिलित हैं।
 - थाई वायु सेना अपने **ग्रिपेन मल्टीरोल लड़ाकू विमान** के साथ भाग ले रही है, जिससे संयुक्त उड़ान संचालन और सामरिक समन्वय को बढ़ावा मिल रहा है।
- ◆ **उद्देश्य:** इस अभ्यास का **प्राथमिक उद्देश्य** दोनों वायु सेनाओं के बीच हवाई अभियानों में **परिचालन समन्वय, अंतरसंचालनीयता और पारस्परिक समझ** को सुदृढ़ करना है।
- ◆ **रणनीतिक महत्व:** यह अभ्यास भारत की **एक्ट ईस्ट पॉलिसी** और थाईलैंड की **एक्ट वेस्ट पॉलिसी** के व्यापक ढाँचे के भीतर भारत और थाईलैंड के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को उजागर करता है।
- ◆ **लाभ:** एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और एरियल रिफ्यूइंग प्लेटफॉर्म जैसे फोर्स मल्टीप्लायरों की भागीदारी निगरानी, कमांड और कंट्रोल तथा विस्तारित मिशन सहनशक्ति क्षमताओं के उन्नत एकीकरण को प्रदर्शित करती है।

भारत में निर्मित ओरल पोलियो वैक्सिन (nOPV2) को WHO की पूर्व-अर्हता प्राप्त

चर्चा में क्यों ?

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए प्रकार के ओरल पोलियो वैक्सिन (**nOPV2**) को पूर्व-अर्हता (**Pre-qualification**) प्रदान की है, जिसे वैश्विक स्तर पर टीकों की बेहतर आपूर्ति के माध्यम से पोलियो प्रकोप को अधिक स्थायी रूप से नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

मुख्य बिंदु

- ◆ **निर्माण:** यह उपलब्धि भारत के लिये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टीके का निर्माण हैदराबाद स्थित कंपनी **बायोलॉजिकल ई. लिमिटेड (BioE)** द्वारा किया जा रहा है।
- ◆ **स्वास्थ्य सुरक्षा को प्रोत्साहन:** यह स्वीकृति राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा तथा वैश्विक पोलियो उन्मूलन अभियान में भारत की भूमिका को सुदृढ़ करती है।
- ◆ **nOPV2 एक 'गैम-चेंजर' के रूप में:** वर्तमान पोलियो उन्मूलन में प्राथमिक चुनौती **सर्कुलेटिंग वैक्सिन-डेरिव्ड पोलियोवायरस (cVDPV2)** है - ऐसे प्रकोप जो तब होते हैं जब पारंपरिक ओरल वैक्सिन में कमजोर वायरस कम प्रतिरक्षित समुदायों में उत्परिवर्तन के कारण एक घातक रूप में वापस आ जाता है।
- ◆ **आनुवंशिक स्थिरता:** nOPV2 को आनुवंशिक रूप से अधिक स्थिर बनाया गया है, जिससे पारंपरिक टीकों की तुलना में **पक्षाघातकारी रूप में परिवर्तित होने का जोखिम लगभग 80% तक कम** हो जाता है।
- ◆ **विशाल उत्पादन क्षमता:** बायोलॉजिकल ई. लिमिटेड से प्रति वर्ष **600 मिलियन खुराक** का उत्पादन होने की संभावना है, जिससे इंडोनेशिया स्थित मूल निर्माता पर निर्भरता घटेगी और वैश्विक आपूर्ति में विविधता आएगी।
- ◆ **लॉजिस्टिक्स:** इस वैक्सिन की **सेल्फ लाइफ 24 महीने** है तथा इसे **मानक तापमान पर छह माह तक** संगृहीत किया जा सकता है, जिससे इसे दूरदराज क्षेत्रों तक पहुँचाना सुगम होगा।
- ◆ **विश्व पोलियो दिवस:** यह दिवस प्रतिवर्ष **24 अक्टूबर** को मनाया जाता है, ताकि देशों को पोलियो के विरुद्ध संघर्ष में निरंतर सतर्कता बनाए रखने के लिये प्रेरित किया जा सके।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025

चर्चा में क्यों ?

भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (CPI) 2025, जिसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया, 182 देशों और क्षेत्रों को 0 (अत्यधिक भ्रष्ट) से 100 (अत्यंत स्वच्छ) के पैमाने पर रैंक करता है। यह रैंकिंग 13 स्वतंत्र डेटा स्रोतों से प्राप्त विशेषज्ञ आकलनों और व्यावसायिक धारणा सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धारित की गई है।

मुख्य बिंदु

- ◆ रैंकिंग: भारत 182 देशों में से 91वें स्थान पर रहा।
- ◆ स्कोर: भारत का स्कोर 100 में से 39 रहा, जो पिछले वर्ष के 38 के स्कोर से थोड़ा सुधार दर्शाता है।
- ◆ प्रगति: हालाँकि इससे भारत को वर्ष 2024 की 96वीं रैंक से पाँच स्थान ऊपर चढ़ने में मदद मिली, लेकिन यह वैश्विक औसत स्कोर 43 से नीचे बना हुआ है।
 - भारत की रैंकिंग में सुधार: इस मामूली सुधार का श्रेय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) और ई-गवर्नेंस के विस्तार को दिया जाता है, जिससे कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में बिचौलियों द्वारा भ्रष्टाचार कम हुआ है।
 - चिंताएँ: रिपोर्ट में कहा गया है कि सेवाओं में निम्न स्तर की रिश्तखोरी में कमी आई है, लेकिन राजनीतिक वित्तपोषण और मुखबिरों तथा पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।
- ◆ क्षेत्रीय तुलना: भारत पाकिस्तान (136वें) और बांग्लादेश (150वें) से बेहतर है, लेकिन भूटान (18वें) और चीन (75वें) से पीछे है।
- ◆ शीर्ष देश: डेनमार्क (प्रथम, स्कोर 89) सबसे कम भ्रष्ट देश के रूप में अग्रणी, इसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर (तीसरे स्थान पर, एशिया में सर्वोच्च) हैं। न्यूज़ीलैंड और नॉर्वे शीर्ष पाँच में शामिल हैं, जो नॉर्डिक और प्रशांत क्षेत्र के शासन मॉडल की निरंतर पारदर्शिता को दर्शाता है।
- ◆ सबसे निचले पायदान: गृहयुद्ध, राज्य विफलता या निरंकुश शासन से जूझ रहे देशों में सोमालिया और दक्षिण सूडान सबसे निचले पायदान पर (स्कोर 9) हैं। इसके पहले वेनेजुएला, यमन और लीबिया हैं, जो सार्वजनिक जवाबदेही और कानून के शासन पर दीर्घकालिक संघर्ष के विनाशकारी प्रभाव को दर्शाते हैं।
- ◆ वैश्विक निष्कर्ष: वैश्विक औसत स्कोर घटकर 42 हो गया, जो पिछले दशक में सबसे कम है, यह दर्शाता है कि विश्व में भ्रष्टाचार की धारणा बिगड़ रही है।
- ◆ विशेष आँकड़ा: 182 देशों में से 122 देशों ने 50 से कम अंक प्राप्त किये, जो दर्शाता है कि अधिकांश राष्ट्र सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार नियंत्रण में संघर्षरत हैं।

प्रधानमंत्री का सेवा तीर्थ से पहला निर्णय

चर्चा में क्यों ?

भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ से कई महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की, जो सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं के वित्तीय समावेशन, कृषि अवसंरचना और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से लिये गए हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- ❖ पीएम राहत योजना (PM RAHAT Scheme): यह योजना दुर्घटना पीड़ितों को ₹1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार प्रदान करती है, ताकि समय पर और किफायती चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जा सके।
- ❖ लखपति दीदी लक्ष्यों में वृद्धि: सरकार ने लखपति दीदी योजना के लाभार्थियों का लक्ष्य 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ कर दिया है (मार्च 2029 तक), ताकि महिलाओं के वित्तीय समावेशन और बचत लाभ का विस्तार किया जा सके।
- ❖ कृषि अवसंरचना निधि लक्ष्य: कृषकों की क्रेडिट तक पहुँच और कृषि मूल्य शृंखलाओं को मजबूत करने के लिये इस निधि के तहत ऋण आवंटन बढ़ा दिया गया है।
- ❖ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 में ₹10,000 करोड़ का कोर्पस:
 - ⦿ इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप का समर्थन करना है। यह फंड पूरे देश में नई तकनीक-आधारित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
- ❖ निर्णय नागरिक-केंद्रित शासन और सामाजिक कल्याण को दर्शाते हैं: ये पहलें सामूहिक रूप से सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, महिला सशक्तीकरण और नवाचार-प्रधान विकास पर केंद्रित हैं।

भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में वाटरजेट प्रोडक्शन एवं टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों ?

भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में एक अत्याधुनिक वाटरजेट प्रोडक्शन एवं टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया, जो समुद्री स्वावलंबन और बढ़ी हुई परिचालन क्षमता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

मुख्य बिंदु

- ❖ उद्घाटन: भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि ने फरवरी 2026 में इस सुविधा का उद्घाटन किया, जिससे भारत के स्वदेशी रक्षा निर्माण तंत्र को सुदृढ़ किया गया।
- ❖ साझेदार: यह सुविधा मेसर्स मरीन जेट पावर (MJP) इंडिया के साथ साझेदारी में स्थापित की गई है।
 - ⦿ यह यूनिट मैनुफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (ToT) ढाँचे के तहत विकसित की गई, ताकि देश में ही वाटरजेट सिस्टम का उत्पादन तथा परीक्षण किया जा सके।
- ❖ भारत तीसरा देश बन गया: इस विकास के साथ, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बाद तीसरा देश बन गया है, जहाँ एक उन्नत वाटरजेट प्रोडक्शन एवं टेस्टिंग फैसिलिटी मौजूद है।
 - ⦿ यह सुविधा ICG जहाजों में प्रयुक्त वाटरजेट प्रणोदन प्रणालियों के संचालन, रखरखाव और टेस्टिंग को मजबूत करेगी तथा विदेशी परीक्षण अवसंरचना पर निर्भरता को कम करेगी।
- ❖ समर्थन: यह यूनिट स्थानीय निर्माण भागीदारों को रक्षा उत्पादन में शामिल करते हुए घरेलू आपूर्ति शृंखला का समर्थन करेगी, रोजगार सृजित करेगी और MSME तंत्र को मजबूत बनाएगी।
 - ⦿ साथ ही यह दक्षिण एशिया और आसपास के क्षेत्रों के लिये वाटरजेट सिस्टम के परीक्षण और रखरखाव का क्षेत्रीय केंद्र भी बनेगी, जिससे भारत को प्रमुख समुद्री इंजीनियरिंग केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके।
- ❖ तटरक्षक बेड़े की क्षमता में वृद्धि: वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल अपने जहाजों पर 100 से अधिक MJP वाटरजेट प्रणोदन प्रणालियाँ संचालित करता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



गुजरात ने भारत की पहली CBDC-आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की

चर्चा में क्यों ?

गुजरात सरकार ने भारत की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC)-आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य डिजिटल मुद्रा का उपयोग करके खाद्य सब्सिडी वितरण को रूपांतरित करना है।

मुख्य बिंदु

- ❖ **भारत में पहला:** भारत ने गुजरात में अपनी पहली CBDC-सक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) लॉन्च की है, जिसमें सब्सिडी वितरण के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा अधिकृत डिजिटल मुद्रा टोकन का उपयोग किया गया है।
- ❖ **डिजिटल टोकन:** इस प्रणाली के तहत लाभार्थियों को उनके वॉलेट में CBDC से जुड़े डिजिटल कूपन या टोकन प्राप्त होते हैं।
 - ⦿ यह QR कोड या आधार आधारित OTP प्रमाणीकरण का उपयोग करके उचित मूल्य की दुकानों पर सब्सिडी वाले खाद्यान्न को भुनाने के लिये किया जा सकता है।
- ❖ **24x7 पहुँच के लिये ATM:** साबरमती ज़ोन (अहमदाबाद) में 'अन्नपूर्णा ग्रेन ATM' स्थापित किया गया है, जो 35 सेकंड में 25 किलोग्राम तक अनाज वितरण करने में सक्षम है।
 - ⦿ नए मॉडल के तहत मसूर दाल, चना जैसी आवश्यक वस्तुओं को खुले रूप में देने के बजाय 1-किलो सील पैक में वितरित किया जाएगा, जिससे सफाई और गुणवत्ता बनी रहे।
- ❖ **महत्त्व:** CBDC टोकन के उपयोग से यह प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाने, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में भ्रष्टाचार कम करने, लेन-देन की ट्रैसेबिलिटी सुनिश्चित करने और सब्सिडी वितरण में जवाबदेही सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखती है।
- ❖ **विकसित किया गया:** CBDC प्लेटफॉर्म को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा RBI-मान्यता प्राप्त ढाँचे के तहत विकसित किया गया है, जो लाभार्थियों के कल्याण के लिये सुरक्षित और ट्रैसेबल लेन-देन सक्षम बनाता है।

पीएम मोदी ने बारबाडोस की पीएम मिया मोटली को ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी

चर्चा में क्यों ?

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटली को उनकी ऐतिहासिक लगातार तीसरी आम चुनावी विजय पर हार्दिक बधाई दी।

मुख्य बिंदु

- ❖ **ऐतिहासिक विजय:** मिया अमोर मोटली ने बारबाडोस के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरा कार्यकाल हासिल किया, जब उनकी पार्टी ने हाउस ऑफ असेंबली की सभी सीटें जीतीं, जो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि है।
 - ⦿ भारत के प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी, साथ ही India-CARICOM समिट 2024 के दौरान हुई पिछली मुलाकात को याद किया और दोस्ताना द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
 - ⦿ गहरा संबंध: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत बारबाडोस के साथ अपनी पुरानी मित्रता को अत्यंत महत्त्व देता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से लगातार बढ़ रही है।
 - ⦿ उन्होंने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिये बारबाडोस के साथ साझेदारी को और मज़बूत करने की इच्छा जताई।
- ❖ **वैश्विक एवं क्षेत्रीय संदर्भ:** मिया मोटली एक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त अभिकर्ता के रूप में उभरी हैं, जो जलवायु कार्रवाई, आर्थिक सुधारों और दक्षिण-दक्षिण सहयोग का समर्थन कर रही हैं, जिससे बारबाडोस की कूटनीतिक छवि को बढ़ावा मिल रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



रिलायंस को वेनेजुएला से कच्चा तेल आयात करने का अमेरिकी लाइसेंस मिला

चर्चा में क्यों ?

रिलायंस इंडस्ट्रीज को संयुक्त राज्य सरकार द्वारा वेनेजुएला से सीधे कच्चे तेल का आयात करने के लिये एक सामान्य लाइसेंस दिया गया है, जिससे कंपनी को छूट वाले भारी तेल के आयात को पुनः शुरू करने और अपने रिफाइनिंग मार्जिन को बढ़ाने की अनुमति मिलती है।

मुख्य बिंदु

- ◆ वेनेजुएला से तेल आयात: संयुक्त राज्य अमेरिका ने रिलायंस को वेनेजुएला का कच्चा तेल सीधे खरीदने की अनुमति देने वाला लाइसेंस जारी किया, जिससे प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं होगा।
 - वेनेजुएला का कच्चा तेल छूट पर उपलब्ध है और यह रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी की उन्नत इकाइयों के अनुकूल है।
- ◆ स्रोतों में विविधता: यह लाइसेंस भारत के सबसे बड़े निजी रिफाइनर को सीमित आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने और वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं के बीच कच्चे तेल के स्रोतों को विविध बनाने में सहायता करता है।
 - रिलायंस ने वर्ष 2025 में प्रतिबंधों के कारण वेनेजुएला से तेल आयात रोक दिया था, जबकि पहले यह विनिमयकर्ताओं के माध्यम से आयात करता था।
- ◆ प्रभाव: वेनेजुएला से तेल आयात करने से भारत की रूसी कच्चे तेल पर निर्भरता कम हो सकती है तथा भारतीय रिफाइनरीज के लिये सुरक्षित और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित हो सकती है।
- ◆ रणनीतिक ऊर्जा हित: छूट वाले भारी कच्चे तेल को सुनिश्चित करके, रिलायंस अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को मजबूत करता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के ढाँचे के बीच ऊर्जा आपूर्ति शृंखला की सुरक्षा में योगदान देता है।

केरल बना शहरी नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य

चर्चा में क्यों ?

केरल देश का पहला राज्य बन गया है जिसने दीर्घकालिक विकास को दिशा देने और तीव्र शहरीकरण का प्रभावी प्रबंधन करने के उद्देश्य से एक व्यापक शहरी नीति तैयार की है।

मुख्य बिंदु

- ◆ विज्ञान 2050: यह नीति वर्ष 2050 तक राज्य को जलवायु-स्मार्ट शहरों और कस्बों के एक सतत नेटवर्क के रूप में देखने की परिकल्पना करती है, जिसमें वैज्ञानिक योजना तथा सतत शासन पर विशेष जोर दिया गया है।
- ◆ स्वीकृति: स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा लगभग दो वर्षों की तैयारी के बाद, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में केरल मंत्रिमंडल ने इस मसौदा नीति को स्वीकृति दी।
 - इस पहल की पहली घोषणा वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में की गई थी और रोडमैप तैयार करने के लिये राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से युक्त केरल शहरी नीति आयोग का गठन किया गया।
- ◆ परामर्श: आयोग ने मार्च 2025 में नव केरल शहरी नीति रिपोर्ट प्रस्तुत की और कोच्चि में आयोजित एक वैश्विक सम्मेलन से प्राप्त सुझावों को नीति में शामिल किया गया।
 - आयोग के आकलन के अनुसार, वर्ष 2050 तक केरल की शहरी जनसंख्या लगभग 80% तक पहुँचने की संभावना है, जिसके लिये सक्रिय और समावेशी शहरी शासन की आवश्यकता होगी।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ प्रमुख फोकस क्षेत्र: इस नीति में कानूनों और संस्थागत प्रणालियों में सुधार, क्षमता निर्माण, अवसंरचना विकास, जन-केंद्रित सेवाएँ तथा स्थानिक योजना जैसे प्रमुख विषयगत क्षेत्रों को रेखांकित किया गया है।
- इसका उद्देश्य शहरीकरण के लाभों का उपयोग करते हुए असमानताओं को कम करना, सामाजिक समर्थन प्रणालियों को सुदृढ़ करना तथा शहरी क्षेत्रों में अवसंरचना की गुणवत्ता में सुधार करना है।

सरकार ने शिक्षा में AI को जोड़ने के लिये बोधन AI लॉन्च किया

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने पूर्व-प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर शिक्षा प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उपकरणों को एकीकृत करने की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु

- ◆ बोधन AI: IIT मद्रास में स्थित 'सेंटर ऑफ एक्सिलेंस इन AI फॉर एजुकेशन' में 'बोधन एआई' (Bodhan AI) नामक एक गैर-लाभकारी कंपनी शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र के लिये बुनियादी AI तकनीकें विकसित करना है
- बोधन AI, भारत EduAI स्टैक को एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के रूप में विकसित करेगा जो अवधारणा में UPI के समान है ताकि शिक्षा के लिये बड़े पैमाने पर, परस्पर-संगत AI सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकें।
- ◆ उद्देश्य: यह केंद्र पूरे देश में शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में AI उपकरणों को शामिल करने की योजना बना रहा है, जिससे शिक्षा अधिक अनुकूल, प्रभावी और सुलभ बन सके।
- मुख्य क्षेत्र: इस पहल में भारतीय भाषाओं में AI क्षमताओं के अनुसंधान एवं विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें स्वचालित वाक् पहचान (Automatic Speech Recognition), वाक् संश्लेषण (Speech Synthesis) और बहुभाषी भाषा मॉडल शामिल हैं।
- मुख्य जोर ऐसे बहुभाषी AI सिस्टम पर होगा जो विभिन्न भारतीय भाषाओं को समझने और उनमें संवाद करने में सक्षम हों, ताकि छात्रों को उनकी मातृभाषा में प्रतिक्रिया तथा सहयोग मिल सके।
- ◆ अनुप्रयोग: AI उपकरणों से व्यक्तिगत छात्र-अधिगम को बढ़ावा मिलने, शिक्षकों को हस्तक्षेप रणनीतियों में सहायता मिलने तथा प्रशासकों को जिला और विद्यालय स्तर पर शैक्षिक परिणामों के मूल्यांकन में सहायता मिलने की अपेक्षा है।
- ◆ डेटा गोपनीयता और नैतिकता: इस पहल से जुड़े विशेषज्ञों ने छात्र डेटा की सुरक्षा, व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक मंचों पर संग्रहीत न करने तथा AI के उपयोग और उत्तरदायित्वपूर्ण स्क्रीन उपयोग के मध्य संतुलन पर भी बल दिया है।
- ◆ नीतिगत ढाँचा: AI उपकरणों का विकास एवं कार्यान्वयन 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020' के अनुरूप होगा, जिसमें NCERT और SCERT के शैक्षिक ढाँचों को AI इकोसिस्टम में शामिल किया जाएगा।

अंडमान में दो दशक बाद मिट्टी का ज्वालामुखी उद्गार

चर्चा में क्यों ?

उत्तरी अंडमान के डिगलीपुर क्षेत्र में स्थित श्यामनगर में एक मिट्टी का ज्वालामुखी (मड वोल्केनो), जो दो दशकों से अधिक समय से निष्क्रिय था, अचानक सक्रिय हो गया। इस सक्रियता के कारण धरती से मिट्टी और गैस का उत्सर्जन होने लगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- ❖ **भूवैज्ञानिक महत्त्व:** मिट्टी की ज्वालामुखी ऐसी **भूवैज्ञानिक संरचनाएँ** होती हैं जिनमें भूमिगत दबाव और द्रवों की गतिशीलता के कारण मृदा, गैस और पानी बाहर निकलता है। ये **सामान्य लावा वाले ज्वालामुखियों से भिन्न होते हैं।**
- ⦿ **स्थान:** मिट्टी की ज्वालामुखी उत्तर अंडमान के डिगलीपुर क्षेत्र में **जल टिकरे** के पास स्थित है। यह क्षेत्र हरे-भरे वन परिदृश्यों के बीच फैली मिट्टी के ज्वालामुखियों की शृंखला के लिये जाना जाता है।
- ❖ **निगरानी:** इस अप्रत्याशित गतिविधि ने भूवैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है, जो द्वीपों के नीचे होने वाली **भूमिगत प्रक्रियाओं और द्रव गतिकी** को समझने के लिये इस स्थल की अधिक गहन निगरानी कर सकते हैं।
- ❖ **प्रभाव:** स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये विस्फोट स्थल पर आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगाते हुए एहतियाती कदम उठाए हैं। हालाँकि, अब तक किसी बड़ी चोट या संरचनात्मक क्षति की सूचना नहीं मिली है।
- ⦿ विशेषज्ञों का कहना है कि मिट्टी की ज्वालामुखियों के विस्फोट सामान्यतः बाहरी जलवायु कारकों की बजाय **विवर्तनिक गतिविधियों** और **भूमिगत दबाव** से जुड़े होते हैं तथा ऐसे घटनाक्रम **क्षेत्रीय भूविज्ञान** को समझने में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।

तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिये तैयार

चर्चा में क्यों ?

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के नेता **तारिक रहमान** बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिये तैयार हैं, क्योंकि उनकी पार्टी ने **फरवरी 2026** में हुए आम चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल की है।

मुख्य बिंदु

- ❖ **चुनाव:** ये चुनाव बांग्लादेश में **राजनीतिक अनिश्चितता** और **नेतृत्व परिवर्तन** के दौर के बाद एक **महत्त्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव** का प्रतीक बने हैं।
- ❖ **BNP की जीत:** बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने **वर्ष 2026 के आम चुनावों** में निर्णायक जीत हासिल की है, जिससे वह स्पष्ट संसदीय बहुमत के साथ **अगली सरकार** बनाने की स्थिति में आ गई है।
- ❖ **तारिक रहमान:**
 - ⦿ वे BNP के शीर्ष नेता के रूप में उभरे हैं और अब **बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार सँभालने की उम्मीद** है।
 - ⦿ वे पूर्व राष्ट्रपति और BNP के संस्थापक **ज़ियाउर रहमान** और पूर्व प्रधानमंत्री **खालिदा ज़िया** के पुत्र हैं।
 - ⦿ वे वर्षों से BNP की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा रहे हैं, यहाँ तक कि निर्वासन और राजनीतिक चुनौतियों के दौरान भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई।
- ❖ **निर्वासन से वापसी:** रहमान ने लगभग दो दशक विदेश में बिताए और वर्ष 2025 के अंत में उन राजनीतिक बदलावों के बाद बांग्लादेश लौटे, जिससे **घरेलू राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ।**
- ❖ **चुनाव अभियान का केंद्र:** BNP का चुनाव अभियान **आर्थिक पुनरुद्धार, राजनीतिक सुधार और राष्ट्रीय एकता** के वादों पर केंद्रित था, जिसने पूरे देश के मतदाताओं को प्रभावित किया।
- ❖ **भारत के लिये महत्त्व:** बांग्लादेश दक्षिण एशिया में **भारत का एक प्रमुख पड़ोसी** है, जिसके साथ भारत की लंबी स्थलीय सीमा और गहरे आर्थिक, सांस्कृतिक एवं रणनीतिक संबंध हैं।
 - ⦿ BNP के नेतृत्व वाली नई सरकार व्यापार, कनेक्टिविटी परियोजनाओं, सीमा प्रबंधन, आतंकवाद विरोधी समन्वय और **BIMSTEC व SAARC** जैसे क्षेत्रीय समूहों में **द्विपक्षीय सहयोग** को प्रभावित कर सकती है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026

चर्चा में क्यों ?

वीजा-फ्री यात्रा की सुविधा के आधार पर पासपोर्टों की वैश्विक रूप से मान्य रैंकिंग, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत के पासपोर्ट की रैंक में सुधार हुआ है। रैंक में यह वृद्धि भारतीय नागरिकों के लिये बेहतर वैश्विक आवागमन और मज़बूत कूटनीतिक संबंधों को दर्शाती है।

मुख्य बिंदु

- ◆ **वैश्विक रैंकिंग:** वर्ष 2026 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का पासपोर्ट 75वें स्थान पर पहुँच गया है, जो वर्ष 2025 में 85वें स्थान से 10 पायदान की बढ़त है।
 - भारतीय पासपोर्ट धारक अब 56 देशों में बिना पूर्व वीजा के प्रवेश कर सकते हैं। इसमें वीजा-फ्री प्रवेश, वीजा-ऑन-अराइवल तथा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइज़ेशन (ETA) की सुविधा देने वाले देश शामिल हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और अधिक सुगम हुई है।
- ◆ **कार्यप्रणाली:** हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा प्रकाशित सूचकांक, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के डेटा का उपयोग करते हुए, बिना पूर्व वीजा स्वीकृति के प्रवेश की सुविधा के आधार पर 227 गंतव्यों में 199 पासपोर्ट को रैंक करता है।
 - शीर्ष रैंक वाले पासपोर्ट: सिंगापुर 192 वीजा-फ्री गंतव्यों के साथ शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, इसके बाद जापान और दक्षिण कोरिया का स्थान है।
 - निचले पायदान वाले पासपोर्ट: अफगानिस्तान, इराक और सीरिया जैसे देश सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर बने हुए हैं, जो भू-राजनीतिक तथा सुरक्षा चुनौतियों के कारण सीमित अंतर्राष्ट्रीय आवागमन को दर्शाता है।
- ◆ **क्षेत्रीय तुलना:** भारत दक्षिण एशिया के कई पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से ऊपर रैंक पर है, जबकि मालदीव इस क्षेत्र में भारत से कहीं बेहतर स्थान पर है।
- ◆ **महत्त्व:** रैंकिंग में सुधार मज़बूत कूटनीतिक संबंधों, व्यापार और पर्यटन के बेहतर अवसरों तथा भारतीय नागरिकों की यात्रा स्वतंत्रता की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी हुई मान्यता को दर्शाता है।

BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर 2025

चर्चा में क्यों ?

भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को वर्ष 2025 में खेल जगत में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और उपलब्धियों के सम्मान में नई दिल्ली में आयोजित एक प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह में BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया।

मुख्य बिंदु

- ◆ **सम्मान:** स्मृति मंधाना को उनके लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये वर्ष 2025 की BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया।
 - विशेष रूप से वर्ष 2025 महिला विश्व कप में भारत की ऐतिहासिक जीत में उनकी अहम भूमिका और घरेलू लीगों में सफलता के लिये।
- ◆ **खेल सम्मानित खिलाड़ी:** शतरंज की प्रतिभा दिव्या देशमुख को FIDE महिला विश्व कप में उनकी ऐतिहासिक जीत के लिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया।
 - प्रीति पाल को वर्ष 2024 पेरिस पैरालंपिक में दो कांस्य पदक जीतने के लिये पैरा-स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर का खिताब मिला।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ♦ **आजीवन उपलब्धि:** अनुभवी निशानेबाज अंजलि भागवत को उनके पथप्रदर्शक करियर के लिये लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें ओलंपिक फाइनल में पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला शूटर बनना भी शामिल है।
- ♦ **चयन प्रक्रिया:** विजेताओं का चयन एक प्रतिष्ठित जूरी द्वारा किया गया, जिसमें लिण्डर पेस, दीपा मलिक और अंजू बाँबी जॉर्ज जैसी खेल हस्तियाँ शामिल थीं।
- ♦ **महिला खेलों का प्रोत्साहन:** यह पुरस्कार समारोह भारतीय महिला खिलाड़ियों की उत्कृष्टता और प्रभाव को सम्मानित करता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनके योगदान को रेखांकित करता है तथा भावी पीढ़ियों को प्रेरित करता है।

मैग्नस कार्लसन ने 2026 FIDE फ्रीस्टाइल वर्ल्ड चैस टाइटल जीता

चर्चा में क्यों ?

नॉर्वेजियन शतरंज के दिग्गज मैग्नस कार्लसन ने अमेरिकी ग्रैंडमास्टर फैबियानो कारुआना को हराकर 2026 FIDE फ्रीस्टाइल वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीत ली।

मुख्य बिंदु

- ♦ **कार्यक्रम:** 2026 FIDE फ्रीस्टाइल वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप पहली आधिकारिक फ्रीस्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप थी।
- ♦ **आयोजक:** अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) और फ्रीस्टाइल शतरंज ऑपरेशन्स।
- ♦ **स्थान:** श्लॉस वीसेनहाउस, वांगेल्स, जर्मनी।
 - ⦿ यह खिताब उन्हें विभिन्न शतरंज प्रारूपों में 21वीं विश्व चैंपियनशिप जीत दिलाता है।
- ♦ **विजेता:** मैग्नस कार्लसन ने चैंपियनशिप जीती।
- ♦ **रनर-अप:** फैबियानो कारुआना (USA)।
- ♦ **फ्रीस्टाइल शतरंज प्रारूप:** इसे Chess960 (चैस960) के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रारूप में मोहरों (प्यादों को छोड़कर) की शुरुआती स्थिति को यादृच्छिक कर दिया जाता है, जिससे रटी-रटाई 'ओपनिंग्स' की भूमिका कम हो जाती है और रचनात्मकता तथा गणना पर अधिक जोर दिया जाता है।
- ♦ **प्रारूप और प्रतिभागी:** विश्व रैंकिंग और टूरस के आधार पर आठ शीर्ष ग्रैंडमास्टर चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्द्धा के लिये योग्य हुए।
- ♦ **रणनीतिक महत्त्व:** FIDE द्वारा फ्रीस्टाइल चैस को आधिकारिक मान्यता देने से अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं में नवाचार और नए प्रारूपों की बढ़ती स्वीकृति का संकेत मिलता है।

रूस ने व्हाट्सएप को ब्लॉक किया, सरकारी ऐप को बढ़ावा दिया

चर्चा में क्यों ?

रूसी सरकार ने मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप तक पहुँच को ब्लॉक कर दिया है और टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो रूस के दो सबसे अधिक उपयोग किये जाने वाले विदेशी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हैं।

मुख्य बिंदु

- ♦ **व्हाट्सएप प्रतिबंध:** रूस ने व्हाट्सएप को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है, यह आरोप लगाते हुए कि प्लेटफॉर्म ने रूसी कानूनों और नियामक आवश्यकताओं का पालन करने से इनकार किया।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- यह प्रतिबंध इसलिये लागू किया गया क्योंकि व्हाट्सएप स्थानीय कानूनी और सुरक्षा दायित्वों को पूरा नहीं कर पाया।
- ◆ नियामक प्राधिकरण: ये प्रतिबंध रूस के राज्य संचार नियामक, 'रोसकोमनाडज़ोर' (Roskomnadzor) द्वारा लागू किये जाते हैं।
- ◆ स्टेट ऐप की ओर रुझान: रूसी सरकार विदेशी-स्वामित्व वाले सेवाओं की जगह मैक्स, एक राज्य-समर्थित मैसेजिंग और सुपर-ऐप को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।
- ◆ टेलीग्राम पर प्रतिबंध: टेलीग्राम को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है।
 - अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म की कार्यक्षमता पर प्रतिबंध लागू किये हैं और इसे आतंकवादी या निषिद्ध सामग्री हटाने में विफल रहने का आरोप लगाया है।
- ◆ राष्ट्रीय सुरक्षा कथानक: रूसी अधिकारी तर्क देते हैं कि विदेशी मैसेजिंग ऐप्स पर प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये आवश्यक है।
 - इन प्लेटफॉर्म्स पर कथित रूप से आपराधिक गतिविधियाँ, धोखाधड़ी और विदेशी खुफिया पहुँच को सुविधाजनक बनाने का आरोप है।
- ◆ सार्वजनिक प्रतिक्रिया: डिजिटल अधिकार समूहों ने व्हाट्सएप प्रतिबंध और टेलीग्राम पर लगाए गए प्रतिबंधों की आलोचना की है, यह कहते हुए कि ये गोपनीयता तथा स्वतंत्र संचार को कमज़ोर करते हैं, जबकि राज्य-नियंत्रित प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना रूस की डिजिटल संप्रभुता की पहल का हिस्सा है।

पहला स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज़ 'कृष्णा' चेन्नई में लॉन्च किया गया

चर्चा में क्यों ?

भारतीय नौसेना ने फरवरी 2026 में चेन्नई के कट्टुपल्ली स्थित L&T शिपयार्ड में अपना पहला स्वदेश निर्मित और डिज़ाइन किया गया कैडेट प्रशिक्षण जहाज़ (CTS) 'कृष्णा' लॉन्च किया।

मुख्य बिंदु

- ◆ प्रथम स्वदेशी CTS: 'कृष्णा', रक्षा मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित एक अनुबंध के तहत लार्सन एंड टुब्रो (L&T) द्वारा भारतीय नौसेना के लिये निर्मित किये जा रहे तीन कैडेट प्रशिक्षण जहाज़ों में से पहला है।
 - 'कृष्णा' पूरी तरह से सुसज्जित एक पाल-प्रशिक्षण और मोटर चालित जहाज़ है, जो प्रशिक्षण के उद्देश्य से 150 कैडेटों तथा अधिकारियों को रखने में सक्षम है।
 - इस जहाज़ का नाम कृष्णा नदी के नाम पर रखा गया है, जो भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है।
- ◆ लॉन्च समारोह: इस कैडेट प्रशिक्षण जहाज़ का उद्घाटन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान की पत्नी, अनुपमा चौहान द्वारा किया गया।
- ◆ रणनीतिक महत्त्व: यह आधुनिक नौसैनिक अभियानों और समुद्री जीवन से परिचित अच्छी तरह से प्रशिक्षित अधिकारियों को तैयार करके भारत की 'ब्लू-वॉटर' (Blue-water) नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाता है।
 - इस जहाज़ में आधुनिक नेविगेशन (नौवहन), संचार और सुरक्षा प्रणालियाँ मौजूद हैं, जो कैडेटों को अत्याधुनिक समुद्री तकनीक का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करती हैं।
- ◆ डिज़ाइन और निर्माण: इस पोत को पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित किया गया है तथा इसे 2026 के अंत तक भारतीय नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ♦ **आत्मनिर्भर भारत:** यह परियोजना स्वदेशी रक्षा जहाज निर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देकर 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को सुदृढ़ करती है।

यूरोपियन यूनियन ने खोला भारत में अपना पहला 'लीगल गेटवे' ऑफिस

चर्चा में क्यों ?

यूरोपीय संघ (EU) ने नई दिल्ली में अपने पहले 'यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफिस' का उद्घाटन किया। यह भारत और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच भारतीय छात्रों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों विशेष रूप से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) क्षेत्र में कानूनी तथा पारदर्शी आवाजाही को सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बिंदु

- ♦ **अपनी तरह का पहला कार्यालय:** भारत में 'यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफिस' किसी भी साझेदार देश में यूरोपीय संघ (EU) द्वारा खोली गई इस तरह की पहली सुविधा है।
 - ⦿ यह कार्यालय यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों में कार्य, अध्ययन और अनुसंधान के अवसरों हेतु वैध आवागमन के माध्यम पर स्पष्ट तथा विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिये एक 'वन-स्टॉप हब' के रूप में कार्य करता है।
- ♦ **मुख्य फोकस:** इस पहल का उद्देश्य भारतीय ICT छात्रों, पेशेवरों और शोधकर्ताओं को पात्रता मानदंड, कौशल एवं योग्यता आवश्यकताओं तथा पूरे यूरोपीय संघ में उपलब्ध अवसरों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करना है।
 - ⦿ यह 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में अपनाए गए 'भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक एजेंडा' के तहत व्यापक सहयोग का हिस्सा है।
- ♦ **परिचालन संरचना:** लीगल गेटवे ऑफिस तीन परस्पर जुड़े घटकों के माध्यम से कार्य करेगा:
 - ⦿ भारत में एक गेटवे ऑफिस।
 - ⦿ यूरोपीय संघ में एक सपोर्ट ऑफिस।
 - ⦿ एक डिजिटल टूल, जो आवाजाही और वीजा प्रक्रियाओं पर केंद्रीय सूचना केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
- ♦ **रणनीतिक महत्त्व:** इस पहल से प्रवासन और गतिशीलता पर भारत-यूरोपीय संघ के सहयोग के गहराने, शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में संबंध मजबूत होने तथा दोनों क्षेत्रों की प्रतिभाओं एवं अर्थव्यवस्थाओं के लिये पारस्परिक रूप से लाभकारी अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है।
- ♦ **अर्थव्यवस्था और कौशल:** यह कार्यालय विशेष रूप से डिजिटल, वैज्ञानिक और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत के विशाल एवं कुशल कार्यबल तथा वैश्विक प्रतिभा पूल में इसके योगदान की मान्यता को दर्शाता है; साथ ही, यह यूरोपीय नियोक्ताओं व संस्थानों को भारतीय प्रतिभाओं के साथ जुड़ने में भी सहायता प्रदान करता है।

केरल ने ज्वारीय बाढ़ को 'राज्य-विशिष्ट आपदा' घोषित किया

चर्चा में क्यों ?

जलवायु-संवेदनशील नीति की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए, केरल सरकार ने हाल ही में 'ज्वारीय बाढ़' (उच्च ज्वार के दौरान समुद्र का स्थानीय इलाकों में प्रवेश) को 'राज्य-विशिष्ट आपदा' घोषित किया है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- ◆ **ज्वारीय बाढ़:** इसे 'सनी डे फ्लडिंग' या 'नुइसेंस फ्लडिंग' (Nuisance Flooding) के रूप में भी जाना जाता है। यह तब होती है जब तूफान या भारी बारिश की अनुपस्थिति में भी उच्च ज्वार के दौरान समुद्र का स्तर स्थानीय सीमा से ऊपर बढ़ जाता है।
- ◆ **केरल का संदर्भ:** एर्नाकुलम (कोच्चि), अलाप्पुझा और त्रिशूर जैसे जिलों में, समुद्र का पानी बैकवाटर और जल-निकासी प्रणालियों के माध्यम से दिन में दो बार घरों तथा दुकानों में प्रवेश करता है, जिससे पुरानी (क्रोनिक) जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है।
- ◆ **इसे 'आपदा' का दर्जा क्यों ?:** ऐतिहासिक रूप से, आपदा राहत केवल चक्रवात या भूस्खलन जैसी 'आकस्मिक' घटनाओं के लिये आरक्षित थी। केरल का यह बदलाव कई महत्वपूर्ण कारकों पर आधारित है:
 - **बारंबारता और तीव्रता:** जलवायु परिवर्तन और समुद्र के स्तर में वृद्धि (SLR) के कारण उच्च ज्वार अब स्थानीय इलाकों में काफी अंदर तक पहुँच रहे हैं।
 - जो कभी एक मामूली असुविधा थी, वह अब जीवन और संपत्ति के लिये दैनिक खतरा बन गई है।
 - **'धीमी गति' का संकट:** सुनामी के विपरीत, ज्वारीय बाढ़ एक धीमी गति से आने वाली आपदा है। समय के साथ, यह घरों की नींव को नष्ट कर देती है, फर्नीचर खराब कर देती है और कृषि भूमि को लवणीय (खारी) बना देती है।
 - **नीतिगत कमी को दूर करना:** आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत, मानक राहत कोष का उपयोग 'नियमित' ज्वारीय घटनाओं के लिये नहीं किया जा सकता था।
 - इसे 'राज्य-विशिष्ट' घोषित करके, सरकार अब घर की मरम्मत और आजीविका के नुकसान के लिये वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है।
- ◆ **आपदा प्रबंधन के लिये महत्त्व:** यह परिभाषा को 'आकस्मिक आघात' से हटाकर 'संचयी हानि' की ओर ले जाता है, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये 'सेंडाई फ्रेमवर्क' के अनुरूप है।
 - **तटीय भारत के लिये मिसाल:** अन्य संवेदनशील राज्य (जैसे ओडिशा, पश्चिम बंगाल) भी इसका अनुसरण कर सकते हैं क्योंकि समुद्र का बढ़ता स्तर पूरी 7,500 किमी लंबी भारतीय तटरेखा के लिये खतरा उत्पन्न कर रहा है।

उत्तर पूर्व में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु NEST को स्वीकृति दी गई

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (NER) में अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नॉर्थ ईस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर (NEST) की स्थापना हेतु एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्य बिंदु

- ◆ **परियोजना स्वीकृति:** NEST परियोजना को जुलाई 2025 में उत्तर पूर्वी परिषद (NEC) तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) की योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृति दी गई। लगभग ₹22.98 करोड़ के परिव्यय के साथ इसका उद्देश्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (NER) में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना को सुदृढ़ करना है।
- ◆ **कार्यान्वयन एजेंसी:** इस परियोजना का क्रियान्वयन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी द्वारा किया जाएगा।
- ◆ **चार विषयगत स्तंभ:** NEST निम्नलिखित चार प्रमुख फोकस क्षेत्रों के माध्यम से कार्य करेगा—
 - **ग्रासरूट्स प्रौद्योगिकियों पर नवाचार केंद्र:** स्थानीय समस्याओं के लिये तकनीकी समाधान को बढ़ावा देने हेतु।
 - **सेमीकंडक्टर एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिये प्रौद्योगिकी हब:** भावी प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों के अनुरूप।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- बाँस-आधारित प्रौद्योगिकी के लिये उत्कृष्टता केंद्र: क्षेत्रीय संसाधनों का उपयोग करते हुए उत्पाद एवं प्रक्रिया नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु।
- जैव-अवक्रमणीय एवं पर्यावरण-अनुकूल प्लास्टिक के लिये कौशल विकास एवं नवाचार केंद्र: सतत प्रौद्योगिकी और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु।
- ◆ उद्देश्य: NEST क्लस्टर का उद्देश्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के युवाओं विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और दिव्यांगजनों को स्वरोजगार तथा उद्यमिता के लिये सशक्त बनाना है। साथ ही क्षमता निर्माण, अनुसंधान हस्तक्षेप और उत्पादों के व्यावसायीकरण के माध्यम से MSMEs को सुदृढ़ करना है।
- यह अकादमिक संस्थानों, अनुसंधान संगठनों, उद्योग भागीदारों और सरकारी एजेंसियों को जोड़ने के लिये हब-एंड-स्पोक मॉडल अपनाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर R&D हस्तक्षेप, नवोन्मेषी पारिस्थितिकी प्रणाली तथा कौशल विकास को बढ़ावा मिल सके।
- ◆ महत्त्व: नॉर्थ ईस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर (NEST) की स्वीकृति भारत सरकार की एक रणनीतिक पहल है, जिसका उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग कर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में समावेशी विकास, रोजगार सृजन तथा उद्यमशील वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। यह क्षेत्रीय सशक्तीकरण और प्रौद्योगिकी-आधारित आर्थिक रूपांतरण के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है।

थान्या नाथन केरल की पहली दृष्टिहीन महिला न्यायाधीश बनेंगी

चर्चा में क्यों ?

थान्या नाथन इतिहास रचने जा रही हैं, क्योंकि वे केरल की पहली दृष्टिबाधित (पूर्णतः दृष्टिहीन) महिला न्यायाधीश बनने वाली हैं।

मुख्य बिंदु

- ◆ ऐतिहासिक उपलब्धि: थान्या नाथन केरल की न्यायपालिका में न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली पूर्णतः दृष्टिहीन महिला होंगी।
- ◆ सफलता: उन्होंने केरल न्यायिक सेवा में प्रवेश हेतु आयोजित सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रतियोगी परीक्षा में बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
- दृष्टिबाधा के बावजूद उन्होंने सुलभ शिक्षण उपकरणों और डिजिटल सहायता प्रणालियों के सहयोग से विधि शिक्षा पूरी की।
- ◆ न्यायिक समावेशन: उनकी उपलब्धि वर्ष 2025 के सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक निर्णय के बाद संभव हुई, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को न्यायिक सेवा की पात्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।
- उनकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के अंतर्गत समता तथा भेदभाव-निषेध के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करती है, जो लोक सेवाओं में समान अवसर सुनिश्चित करते हैं।
- ◆ महत्त्व: थान्या की सफलता न केवल दिव्यांग व्यक्तियों के लिये प्रेरणास्रोत है, बल्कि भारत के विधि पेशे को अधिक सुलभ और समावेशी बनाने के सतत प्रयासों को भी सशक्त बनाती है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मधुमक्खी गलियारे विकसित करेगा NHAI

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अपनी सतत अवसंरचना विकास रणनीति के तहत भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ हिस्सों के साथ परागण-अनुकूल 'मधुमक्खी गलियारे' विकसित करने की एक अग्रणी पहल की घोषणा की है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- ❖ अपनी तरह की पहली पहल: NHAI का 'मधुमक्खी गलियारे' कार्यक्रम सड़क किनारे की वृक्षारोपण पट्टियों को केवल सजावटी हरियाली से बदलकर पारिस्थितिक रूप से कार्यात्मक हरित गलियारों में परिवर्तित करेगा, जो मधुमक्खियों तथा जंगली मधुमक्खियों जैसे परागणकर्ताओं को समर्थन प्रदान करेंगे।
- ❖ उद्देश्य: इस परियोजना का लक्ष्य घटती परागणकर्ता आबादी की समस्या का समाधान करना, जैव विविधता को बढ़ावा देना तथा कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण फसल परागण जैसी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को सुदृढ़ करना है।
 - मधुमक्खी गलियारे में निरंतर रैखिक वनस्पति पट्टियाँ विकसित की जाएंगी, जिनमें फूलदार वृक्ष, झाड़ियाँ, औषधीय पौधे और घास शामिल होंगी, जो पूरे वर्ष पराग तथा मधुरस उपलब्ध कराएंगी।
- ❖ देशज प्रजातियाँ: नीम, करंज, महुआ, पलाश, बॉटल ब्रश, जामुन और सिरिस जैसी प्रजातियाँ, जो मधुरस तथा पराग से समृद्ध मानी जाती हैं, क्रमबद्ध (स्टैगर्ड) पुष्पन पैटर्न के साथ लगाई जाएंगी, ताकि पूरे वर्ष परागणकर्ताओं को निरंतर समर्थन मिल सके।
- ❖ कार्यान्वयन रणनीति: NHAI के क्षेत्रीय कार्यालय कृषि-जलवायु परिस्थितियों और स्थानीय पारिस्थितिक उपयुक्तता के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के उपयुक्त हिस्सों तथा खाली भूमि खंडों की पहचान करेंगे।
 - वित्तीय वर्ष 2026-27 में NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे लगभग 40 लाख वृक्ष लगाने की योजना बना रहा है, जिनमें से लगभग 60% 'मधुमक्खी गलियारे' पहल के अंतर्गत लगाए जाएंगे।
 - इस अवधि में कम से कम तीन समर्पित परागणकर्ता गलियारों के विकास की अपेक्षा है।
- ❖ महत्त्व: NHAI की 'मधुमक्खी गलियारे' पहल अवसंरचना-आधारित पारिस्थितिक पुनर्स्थापन का एक अभिनव मॉडल प्रस्तुत करती है, जिसके माध्यम से भारत के राजमार्ग नेटवर्क का उपयोग परागणकर्ताओं के आवास और जैव विविधता को समर्थन देने के लिये किया जाएगा।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026

चर्चा में क्यों ?

भारत ने 28 फरवरी, 2026 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 को 'विज्ञान में महिलाएँ: विकसित भारत को गति देने वाली' थीम के साथ मनाया।

मुख्य बिंदु

- ❖ पृष्ठभूमि: भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ताकि भौतिक विज्ञानी सी. वी. रमन द्वारा वर्ष 1928 में किये गए रमन प्रभाव की खोज का सम्मान किया जा सके, जिसके लिये उन्हें वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- ❖ वर्ष 2026 की थीम: 'विज्ञान में महिलाएँ: विकसित भारत को गति देने वाली' थीम ने विकसित भारत के निर्माण में महिला वैज्ञानिकों और नवोन्मेषकों के योगदान पर जोर दिया तथा अनुसंधान, प्रौद्योगिकी एवं STEM क्षेत्रों में उनके प्रयासों को मान्यता दी।
 - यह थीम विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस जैसे वैश्विक प्रयासों के अनुरूप रही, जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी को सुदृढ़ करना है।
- ❖ राष्ट्रीय समारोह: स्कूलों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों एवं विज्ञान केंद्रों में विज्ञान प्रदर्शनियाँ, कार्यशालाएँ, वाद-विवाद, प्रतियोगिताएँ एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गए, ताकि महिलाओं के योगदान को रेखांकित किया जा सके और भावी पीढ़ियों के वैज्ञानिकों को प्रेरित किया जा सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ **महत्त्व:** इस दिवस ने नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया और राष्ट्रीय विकास में विज्ञान की भूमिका को स्वीकार किया, जबकि वर्ष 2026 की थीम ने STEM क्षेत्रों में लैंगिक अंतर को कम करने तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले वैज्ञानिक प्रगति को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया।

भारतीय मणिपुरी फिल्म 'बूंग' ने BAFTA पुरस्कार 2026 जीता

चर्चा में क्यों ?

मणिपुरी भाषा की भारतीय फिल्म 'बूंग' ने 79वें ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स (BAFTA) पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया।

मुख्य बिंदु

- ◆ **ऐतिहासिक जीत:** 'बूंग' प्रतिष्ठित BAFTA पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई।
- ◆ **प्रतिस्पर्धा:** इस मणिपुरी फिल्म ने जूटोपिया 2 और लिलो एंड स्टिच जैसी प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की।
- ◆ **फिल्म की पृष्ठभूमि:** फिल्म का निर्देशन लक्ष्मीप्रिया देवी ने किया है और इसे फरहान अख्तर तथा रितेश सिधवानी सहित अन्य निर्माताओं का समर्थन प्राप्त है।
 - 'बूंग' एक कमिंग-ऑफ-एज ड्रामा है, जो मणिपुर के एक युवा बालक की अपने परिवार को पुनः एकजुट करने की भावनात्मक यात्रा को दर्शाता है।
 - इसका प्रीमियर वर्ष 2024 मेंटोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और इसे कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रदर्शित किया गया है।
- ◆ **थीम:** फिल्म बचपन, पारिवारिक रिश्तों, पहचान एवं भावनात्मक दृढ़ता के इर्द-गिर्द घूमती है, जो इसे बच्चों और परिवारों के लिये वैश्विक स्तर पर उपयुक्त बनाती है।
 - लंदन में आयोजित पुरस्कार समारोह के दौरान निर्देशक ने भावुक स्वीकृति भाषण दिया, जिसमें उन्होंने सांस्कृतिक कथाओं को रेखांकित किया और शांति का आह्वान किया, जो पूरे विश्व के दर्शकों के साथ गूँजा।
- ◆ **महत्त्व:** यह फिल्म भारतीय सिनेमा के लिये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि पहली बार किसी भारतीय निर्माण को इस श्रेणी में बाफ्टा पुरस्कार मिला है।
 - इस जीत के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सामाजिक-सांस्कृतिक कहानियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली है, जिन्हें अब तक मुख्यधारा के भारतीय सिनेमा में सीमित स्थान ही प्राप्त था।

केंद्रीय कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने की स्वीकृति दी

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदलकर 'केरलम (Keralam)' करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है, जिससे राज्य का आधिकारिक नाम मलयालम भाषा में प्रचलित नाम के अनुरूप हो जाएगा।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- ❖ **पृष्ठभूमि:** 'केरलम (Keralam)' राज्य का मूल मलयालम नाम है, जिसका सांस्कृतिक और भाषायी प्रयोग सदियों से निरंतर होता रहा है।
- ❖ **प्राचीन संदर्भ:** इस शब्द का उल्लेख सम्राट अशोक के द्वितीय शिलालेख (257 ईसा पूर्व) में 'केरलपुत्र' के रूप में मिलता है, जो चेर वंश को संदर्भित करता है।
- ❖ **भाषायी पुनर्गठन:** मलयालम भाषी समुदायों के लिये एकीकृत 'केरलम' की मांग राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही उठती रही है।
 - ⦿ **औपनिवेशिक नाम:** अंग्रेजी नाम 'केरल' औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान प्रचलन में आया और स्वतंत्रता के बाद भी बनाए रखा गया।
- ❖ **प्रस्ताव:** केरल विधानसभा ने पहले सर्वसम्मति से नाम परिवर्तन का प्रस्ताव पारित कर इसे केंद्र सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा था।
- ❖ **संवैधानिक और कानूनी आधार:** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों के गठन तथा मौजूदा राज्यों के नाम, क्षेत्रफल या सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार देता है।
- ❖ **प्रक्रिया:** इस प्रक्रिया हेतु आवश्यक है:
 - ⦿ राष्ट्रपति की अनुशंसा पर संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।
 - ⦿ विधेयक को संबंधित राज्य विधानसभा के विचार हेतु भेजा जाता है (हालाँकि ये विचार बाध्यकारी नहीं होते)।
 - ⦿ मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद, परिवर्तन को औपचारिक रूप देने हेतु विधेयक संसद में पेश किया जाता है।
- ❖ **संसदीय स्वीकृति:** विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है।
- ❖ **राष्ट्रपति की स्वीकृति:** पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है।
- ❖ **अनुसूचियों में संशोधन:** अधिनियम के अधिसूचित होने पर संविधान की प्रथम अनुसूची (राज्यों के नामों की सूची) और चतुर्थ अनुसूची (राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित) को तदनुसार अद्यतन किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2026

चर्चा में क्यों ?

पूरे विश्व में 21 फरवरी, 2026 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। यह दिन भाषायी विविधता का उत्सव मनाने, मातृभाषाओं के संरक्षण को बढ़ावा देने तथा शिक्षा और सांस्कृतिक पहचान में मातृभाषाओं की भूमिका को रेखांकित करने के लिये समर्पित है।

मुख्य बिंदु

- ❖ **उत्पत्ति:** UNESCO ने इस दिवस की घोषणा भाषायी विविधता की रक्षा और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की थी, ताकि मातृभाषाओं के सांस्कृतिक तथा शैक्षिक महत्त्व को उजागर किया जा सके।
 - ⦿ यह प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है, जो बांग्लादेश के ऐतिहासिक भाषा आंदोलन की स्मृति में है, जहाँ वर्ष 1952 में छात्रों ने अपनी मातृभाषा बांग्ला को मान्यता दिलाने के लिये अपने प्राणों का बलिदान दिया था।
- ❖ **वर्ष 2026 की थीम:** 'बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज़' (Youth Voices on Multilingual Education)— यह मातृभाषाओं में समावेशी और बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने में युवाओं की भूमिका पर जोर देती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ स्वदेशी अस्मिता का संवर्द्धन: यह स्वदेशी समुदायों को सशक्त बनाने के प्रयासों को रेखांकित करता है, जिसमें मातृभाषाओं को संस्कृति, ज्ञान और पहचान के संवाहक के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है।
- ◆ वैश्विक आयोजन: ढाका के शहीद मीनार पर श्रद्धांजलि, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पैनल चर्चाएँ तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित विविध कार्यक्रमों के माध्यम से भाषायी विविधता का उत्सव मनाया जाता है।
- ◆ महत्त्व: मातृभाषाएँ शिक्षा, पहचान निर्माण और संज्ञानात्मक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
 - अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, भाषायी विविधता के संरक्षण, समावेशी शिक्षा के प्रसार और वैश्विक सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के महत्त्व को सुदृढ़ करता है।

ज़िम्बाब्वे ने लंबे समय तक असर करने वाला HIV-निरोधक इंजेक्शन लेनाकापैविर लॉन्च किया

चर्चा में क्यों ?

ज़िम्बाब्वे HIV की रोकथाम के लिये लंबे समय तक असर करने वाली इंजेक्टबल दवा लेनाकापैविर (Lenacapavir) लॉन्च करने वाले अफ्रीका के पहले देशों में से एक बन गया है। यह कदम महाद्वीप में HIV/AIDS के खिलाफ लड़ाई में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

मुख्य बिंदु

- ◆ लेनाकापैविर: लेनाकापैविर एक दीर्घकालिक प्रभाव वाली एंटीरेट्रोवायरल दवा है, जिसका उपयोग HIV की रोकथाम के लिये प्री-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (PrEP) में किया जाता है।
- ◆ क्रिया-विधि: गिलियड साइसेज़ द्वारा विकसित लेनाकापैविर एक कैप्सिड इनहिबिटर है। यह HIV-1 के वायरल कैप्सिड (जो वायरस की आनुवंशिक सामग्री की रक्षा करने वाला प्रोटीन आवरण है) में उसके जीवन-चक्र के कई चरणों पर हस्तक्षेप करता है, जिससे वायरस निष्क्रिय हो जाता है।
- ◆ छह-महीने का संरक्षण: लेनाकापैविर नगोपोन की पहली ऐसी PrEP दवा है, जिसे वर्ष में केवल दो बार (हर छह महीने में) इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है।
- ◆ WHO पूर्व-अर्हता: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अक्टूबर 2025 में इस दवा को पूर्व-अर्हता प्रदान की और जुलाई 2025 में इसके कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देश जारी किये।
- ◆ क्षेत्रीय नेतृत्व: ज़िम्बाब्वे ने ज़ाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर WHO की सहयोगी पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से इस तकनीक को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाई, जिससे रिकॉर्ड समय में अनुमोदन संभव हुआ।
- ◆ लक्षित आबादी: प्रारंभिक चरण में पूरे देश के 24 केंद्रों पर लगभग 46,500 उच्च-जोखिम वाले व्यक्तियों को लक्षित किया गया है, जिनमें किशोरियाँ, युवा महिलाएँ, यौन कर्मि तथा गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताएँ शामिल हैं।
- ◆ वित्तपोषण और समर्थन: यह कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार और ग्लोबल फंड के सहयोग से संचालित है, जिसके तहत कमजोर वर्गों को यह दवा निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।
- ◆ प्रभावकारिता: नैदानिक परीक्षणों में HIV संक्रमण की रोकथाम में लगभग 100% प्रभावशीलता पाई गई, जो दैनिक मौखिक PrEP गोलियों की तुलना में कहीं अधिक है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



UN ने चार भारतीय राज्यों में सड़क सुरक्षा वित्तपोषण परियोजना लॉन्च की

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा कोष (UNRSF) ने भारत में एक 'सतत सड़क सुरक्षा वित्तपोषण परियोजना' (Sustainable Road Safety Financing Project) शुरू की है, जिसका उद्देश्य चयनित राज्यों में सड़क सुरक्षा हस्तक्षेपों के लिये वित्तीय तंत्र और क्षमता को मजबूत करना है।

- ◆ इस परियोजना का उद्घाटन नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा के लिये संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष दूत, जीन टॉड (Jean Todt) की यात्रा के दौरान किया गया।

मुख्य बिंदु

- ◆ **उद्देश्य:** इस पहल का लक्ष्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के लिये सतत और समन्वित वित्तपोषण तंत्र स्थापित करना है।
 - तकनीकी और नीतिगत सहायता प्रदान करने के लिये यह परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), UNICEF और 'सेव लाइफ फाउंडेशन' (Save LIFE Foundation) जैसे गैर-लाभकारी संगठनों के साथ साझेदारी में लागू की जा रही है।
- ◆ **फोकस राज्य:** प्रभावी सड़क सुरक्षा कार्य योजनाओं को लागू करने की क्षमता निर्माण के लिये यह वित्तपोषण परियोजना भारत के चार राज्यों राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और असम में शुरू की जा रही है।
- ◆ **आवश्यकता:** भारत में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है, जिससे स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में व्यापक क्षति होती है। अनुमानों के अनुसार, इन दुर्घटनाओं से देश की GDP का लगभग 3% नुकसान होता है।
- ◆ **सतत वित्तपोषण रणनीतियाँ:** यह परियोजना सड़क सुरक्षा के लिये अनुमानित और निरंतर फंड सुनिश्चित करने हेतु रोड सेप्टी बॉण्ड, समर्पित कर और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) जैसे नवीन वित्तीय उपकरणों को बढ़ावा देती है।
- ◆ **क्षमता निर्माण:** इसका एक मुख्य हिस्सा राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा निवेशों की योजना बनाने, बजट तैयार करने तथा उनकी निगरानी करने के लिये संस्थागत क्षमता को मजबूत करना है।
- ◆ **वैश्विक संरक्षण:** यह पहल 'सड़क सुरक्षा के लिये दशक की कार्ययोजना 2021-2030' (Global Plan for the Decade of Action for Road Safety) का समर्थन करती है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक पूरे विश्व में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु और गंभीर चोटों को आधा करना है।

रॉब जेटन नीदरलैंड के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने

चर्चा में क्यों ?

रॉब जेटन ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, उन्होंने देश का सबसे युवा और पहला समलैंगिक नेता बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने फरवरी 2026 में कार्यभार संभाला।

मुख्य बिंदु

- ◆ **ऐतिहासिक नेतृत्व:** रॉब जेटन 38 वर्ष की आयु में डच इतिहास के सबसे युवा प्रधानमंत्री और नीदरलैंड का नेतृत्व करने वाले पहले घोषित समलैंगिक व्यक्ति बन गए हैं। यह राजनीति में LGBTQ+ प्रतिनिधित्व की प्रगति को रेखांकित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- वे तीन दलों के अल्पमत गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें उनकी मध्यमार्गी पार्टी डेमोक्रेट्स 66 (D66), मध्य-दक्षिणपंथी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक अपील (CDA) और उदारवादी पीपल्स पार्टी फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी (VVD) शामिल है। निचली सदन की 150 सीटों में से इस गठबंधन के पास कुल 66 सीटें हैं।
- शपथ ग्रहण समारोह (Swearing-In Ceremony): हेग (The Hague) स्थित हुइस टेन बॉश पैलेस (Huis ten Bosch Palace) में राजा विलेम-अलेक्जेंडर ने नई सरकार को शपथ दिलाई।
- राजनीतिक पृष्ठभूमि: जेटन के राजनीतिक करियर की शुरुआत वर्ष 2010 में नगर निगम स्तर से हुई थी।
- वे वर्ष 2017 में डच प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) में शामिल हुए और प्रधानमंत्री बनने से पहले जलवायु एवं ऊर्जा नीति मंत्री तथा उप-प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।
- महत्त्व: जेटन के नेतृत्व को समावेशिता और विविधता के लिये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है, विशेष रूप से LGBTQ+ समुदाय के लिये। नीदरलैंड समान अधिकारों को बढ़ावा देने के लिये जाना जाता है (नीदरलैंड वर्ष 2001 में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला विश्व का पहला देश था)।

पाँच नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे स्टेशनों को 'ईट राइट स्टेशन' सर्टिफिकेशन मिला

चर्चा में क्यों ?

नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) के अंतर्गत आने वाले पाँच रेलवे स्टेशनों को यात्रियों के लिये सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन सेवाएँ सुनिश्चित करने हेतु भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा 'ईट राइट स्टेशन' (Eat Right Station) प्रमाणन से सम्मानित किया गया है।

मुख्य बिंदु

- ईट राइट स्टेशन: यह पहल FSSAI के नेतृत्व में चलाए जा रहे 'ईट राइट इंडिया' आंदोलन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जनता के बीच खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और पोषण को बढ़ावा देना है।
- सम्मानित स्टेशन: नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) के पाँच स्टेशनों को स्टेशन परिसर में स्थित खाद्य आउटलेट्स पर उच्च स्तर की स्वच्छता, गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिये यह प्रमाणन प्रदान किया गया है।
 - दीमापुर रेलवे स्टेशन (नागालैंड)
 - अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन (पश्चिम बंगाल)
 - कोकराझार रेलवे स्टेशन (असम)
 - गोलकगंज रेलवे स्टेशन (असम)
 - न्यू माल जंक्शन रेलवे स्टेशन (पश्चिम बंगाल)
- प्रमाणन के मानदंड: यह प्रमाणन खाद्य सुरक्षा दिशानिर्देशों, स्वच्छता प्रोटोकॉल, भोजन के उचित भंडारण एवं रख-रखाव, सुरक्षित जल की उपलब्धता और उपभोक्ता जागरूकता उपायों के कड़े मूल्यांकन के बाद दिया जाता है।
- कार्यान्वयन भागीदार: इस प्रमाणन को सफल बनाने में FSSAI, नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे, खाद्य विक्रेताओं और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने मिलकर खाद्य सुरक्षा बुनियादी ढाँचे तथा यात्री जागरूकता में सुधार के लिये प्रयास किये।
- पहल का विस्तार: 'ईट राइट स्टेशन' कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार के अन्य राष्ट्रीय प्रयासों, जैसे स्वच्छ भारत मिशन और सुरक्षित जल पहल का पूरक है तथा अन्य रेलवे जोनों को भी इसी तरह के मानक अपनाने हेतु प्रोत्साहित करता है।



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2026



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप

